चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

मूल्य 5 रुपये

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित

11 मई-17 मई 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

मराठवाड़ा

किसानों का मरघट

महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र पिछले तीन वर्षों से भयंकर सूखे की मार झेल रहा है, जिसे स्थानीय लोग दुष्काल की संज्ञा दे रहे हैं. इलाक़े के अधिकांश तालाब और बांध सूखे पड़े हैं. राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि मराठवाड़ा के 833 सिंचाई के साधनों में महज़ 11 फ़ीसद पानी शेष बचा है. हालांकि, गर्मी ने अभी-अभी दस्तक दी है, जबकि मई और जून का महीना शेष है. सूखे की मार के चलते मराठवाड़ा के किसान बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं. इधर सरकारी बैंक किसानों को क़र्ज़ देने से कतरा रहे हैं, तो दूसरी तरफ़ उनके ऊपर क़र्ज़ वापसी का अतिरिक्त दबाव है. इन्हीं दो पाटों के बीच अन्नदाता किसान पिस रहा है और मौत को गले लगा रहा है. मराठवाड़ा के नांदेड़, लातूर, उस्मानाबाद, औरंगाबाद, बीड और जालना ज़िलों में सूखे की स्थिति एवं किसान आत्महत्या के कारणों की पड़ताल कर रही चौथी दुनिया की यह ख़ास रिपोर्ट...

अभिषेक रंजन सिंह

ज़िला मुख्यालय उस्मानाबाद से पंद्रह किलोमीटर दूर एक गांव है रूईभर. यहां 11 दिसंबर, 2014 को बाबा साहब माणिक जगताप ने अपने खेत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. जगताप को कानों से कम सुनाई देता था. परिवार में उनकी विकलांग पत्नी अनिता समेत तीन बेटियां काजल, स्नेहल एवं ज्योत्सना और एक बेटा प्रमोद है. माणिक जगताप की बूढ़ी मां केसर बाई अक्सर बीमार रहती हैं. इस परिवार के पास महज़ सवा बीघा ज़मीन है. बड़ी बेटी ज्योत्सना की शादी हो चुकी है, जिसके लिए माणिक जगताप ने अपने रिश्तेदारों से दो लाख रुपये का क़र्ज़ लिया था. इसके अलावा, माणिक जगताप पर सहकारी बैंक का 11 हज़ार रुपये का क़र्ज़ और था, जो उनके पिता ने लिया था. बैंक एवं रिश्तेदारों के तगादे और फ़सल की बर्बादी ने माणिक जगताप को तनावग्रस्त कर दिया. लिहाज़ा इन सबसे बचने के लिए उन्होंने आत्महत्या कर ली. अब माणिक जगताप के तीन बच्चों और उनकी मां के भरण-पोषण का ज़िम्मा उनकी बेवा अनिता के कंधों पर आ गया है. शारीरिक रूप से विकलांग होने के कारण अनिता ने अपनी सवा बीघा ज़मीन बटाई पर लगा दी है. बावजूद इसके, अनिता का नाम बीपीएल सूची में दर्ज नहीं है और न इस परिवार को इंदिरा आवास योजना और अंत्योदय अन्न योजना का लाभ मिल रहा है. अनिता एक झोपड़ीनुमा कमरे में अपने तीन बच्चों और बूढ़ी सास के साथ ज़िंदगी गुज़ारने पर मजबूर हैं. माणिक जगताप जैसे मजबूर किसान की कहानी से मिलती-जुलती कई कहानियां मराठवाड़ा में बिखरी पड़ी हैं. जिन पर न तो सरकार का ध्यान है और न मीडिया का.

जिस मराठवाड़ा की पहचान वर्ष 1954 के भूमिहीन किसान सत्याग्रह के रूप में होती थी, मौजूदा समय में वह किसान आत्महत्याओं का केंद्र बनता जा रहा है. मराठवाड़ा में सूखे का यह तीसरा साल है. पानी की किल्लत से न सिर्फ़ खेती घाटे का सौदा साबित हो रही है, बल्कि इंसानों से लेकर पशुओं तक का जीना दुश्वार होता जा रहा है. मराठवाड़ा क्षेत्र में कुल आठ ज़िले हैं, जहां सूखे से प्रभावित होने वाले करोड़ों किसानों की समस्याओं में बहुत ज़्यादा फ़र्क़ नहीं है. सूखे से सर्वाधिक प्रभावित जालना और बीड ज़िलों में जल संकट गहराता जा रहा है. यहां सैकड़ों गांवों में टैंकरों के ज़रिये लोगों को पानी मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से वह नाकाफ़ी है. मराठवाड़ा में उन गांवों की संख्या भी कम नहीं है, जहां पानी के लिए रोज़ाना लोगों को मीलों पैदल चलना पड़ता है. खेतों में कुंए और बावड़ियां तो ज़रूर हैं, लेकिन उनमें एक बूंद भी पानी नहीं है. छोटे किसानों के लिए खेतों में बोरवेल लगाना आसान नहीं है, क्योंकि पिछले पांच वर्षों के दौरान मराठवाड़ा के लातूर, बीड, उस्मानाबाद और जालना ज़िले में भूजल स्तर 600 से लेकर 900 फीट नीचे चला गया है.

(शेष पृष्ठ 2 पर)

तपता सूरज, सूखता पानी

मराठवाड़ा में गिरता भूजल स्तर :- वर्ष 2012-13 और वर्तमान स्थिति की तुलना तथा पांच वर्षों का औसत परिवर्तन

ज़िला	जनवरी 2012	जनवरी 2013	जनवरी 2015	पांच वर्षों में औसत तब्दीली
औरंगाबाद	8.38 मीटर	11.95 मीटर	9.46 मीटर	-0.94 मीटर
जालना	7.27 मीटर	10.69 मीटर	8.02 मीटर	-0.40 मीटर
परभणी	7.28 मीटर	10.07 मीटर	11.19 मीटर	-2.87 मीटर
हिंगोली	7.80 मीटर	6.33 मीटर	7.89 मीटर	-4.35 मीटर
नांदेड़	6.23 मीटर	6.57 मीटर	7.62 मीटर	-1.60 मीटर
उस्मानाबाद	5.33 मीटर	10.79 मीटर	6.87 मीटर	-4.13 मीटर
लातूर	4.17 मीटर	5.80 मीटर	8.18 मीटर	-2.52 मीटर
बीड	6.02 मीटर	8.59 मीटर	7.76 मीटर	-0.34 मीटर

स्रोत :-भूजल सर्वेक्षण एवं विकास एजेंसी (जीएसडीए), महाराष्ट्र सरकार.

मराठवाड़ा क्षेत्र में किसानों के लिए त्रासदी का सबब बनी नगदी फ़सल.

मराठवाड़ा : पिछले तीन वर्षों से प्यासी है यहां की धरती.

भूकंप पीड़ितों की जुबानी ...जब सामने गुजरी मौत | P-3

हिमालय को अस्थिर करने पर तुला है चीन | P-5

कमज़ोर पड़ता रमन राज | P-7

मराठवाड़ा : किसानों का मरघट

पृष्ठ 1 का शेष

विडंबना यह है कि सूखे से सर्वाधिक प्रभावित जालना ज़िले में तक़रीबन दो दर्जन बोतल बंद पानी के प्लांट स्थापित हैं. इन संयंत्रों में बड़े पैमाने पर भूमिगत जल का दोहन हो रहा है. अगर समय रहते इन संयंत्रों को बंद नहीं किया गया, तो जालना समेत पूरे मराठावाड़ा में पानी की समस्या और गंभीर रूप ले लेगी. औरंगाबाद प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, एक जनवरी, 2014 से 31 दिसंबर, 2014 तक मराठवाड़ा के कुल आठ ज़िलों में 574 किसानों ने आत्महत्या की. वहीं एक जनवरी, 2015 से 27 अप्रैल, 2015 तक मराठवाड़ा के अलग-अलग ज़िलों में अब तक 268 किसान ख़ुदकुशी कर चुके हैं. मराठवाड़ा में औसतन दो से अधिक (2.29) किसान प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं. किसान आत्महत्या की यही रफ्तार रही, तो सिर्फ़ मराठवाड़ा में साल के आख़िर तक यह आंकड़ा 836 के पार जा सकता है. देश में किसान आत्महत्या की घटनाएं कम होने के बजाय प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही हैं. वर्ष 1995 से लेकर वर्ष 2015 के बीच देश भर में 2,96,438 किसानों ने आत्महत्या की. अकेले महाराष्ट्र में इस दौरान 60,365 किसानों ने ख़ुदकुशी की. पहले किसान आत्महत्याओं की ज़्यादातर घटनाएं विदर्भ, मराठवाड़ा और तेलंगाना में होती

थीं, लेकिन अब देश भर से इस तरह की ख़बरें आ रही हैं. यहां तक कि देश के विकास के लिए मॉडल के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले गुजरात में भी किसानों की आत्महत्या आम बात है. अभी हाल ही में राजकोट ज़िले के भादर गांव के 34 वर्षीय किसान हरेश रवाडिया ने फ़सल नाक़ाम रहने की वजह से आत्महत्या कर ली. इस परिवार की त्रासदी यहीं तक नहीं रुकी. हरेश की मौत से आहत होकर उसकी 31 वर्षीय पत्नी भाविशा ने अपने पति की लाश के सामने आग लगाकर आत्महत्या कर ली. दरअसल, ऐसी आत्महत्याओं की एकमात्र वजह किसानों के ऊपर क़र्ज़ और फ़सल का नाक़ाम रहना ही नहीं है. चौथी दुनिया के इस संवाददाता ने मराठवाड़ा के उन सभी इलाक़ों का भ्रमण किया, जहां बीते दिनों किसानों ने बड़े पैमाने पर आत्महत्या की. किसानों के परिवारीजनों और स्थानीय लोगों से हुई बातचीत से एक बात निकल कर सामने आई कि कई वर्षों से फ़सल नाक़ाम रहने एवं क़र्ज़ की वजह से यहां के किसान आत्महत्या कर रहे हैं. आसान क़र्ज़ पाने के चक्कर में किसान साहूकारों के पास जाते हैं और उनके जाल में फंस जाते हैं. दरअसल, उन्हें बैंकों की जटिल प्रक्रिया में उलझने के बजाय साहूकारों से क़र्ज़ लेना ज़्यादा आसान लगता है और इसी का फ़ायदा साहूकार उठाते हैं. किसान आत्महत्याओं की यह एक बड़ी वजह तो है, लेकिन सिर्फ़ यही एकमात्र कारण नहीं है. इसके पीछे कई अन्य कारण भी हैं, जिनका ज़िक्र करना बेहद ज़रूरी है.

पिछले दो दशकों के दौरान मराठवाड़ा में ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं, चना, अरहर, मूंग, उड़द जैसी परंपरागत खेती का रकबा काफ़ी तेज़ी से घटा है. इसकी जगह नगदी फ़सल कहे जाने वाले गन्ना, कपास और सोयाबीन की खेती बहुतायत होने लगी है. किसान आत्महत्या की बढ़ती घटना के बाद देश में नगदी फ़सल को लेकर एक बड़ी बहस भी हो रही है, लेकिन अमूमन परंपरागत खेती करने वाले किसानों को चौबीस वर्ष पहले इस दुष्चक्र में किसने फंसाया? नब्बे के दशक में डंकल प्रस्ताव के ख़िलाफ़ भारतीय किसान यूनियन के नेता महेंद्र सिंह टिकैत की अगुवाई में हज़ारों किसानों ने आंदोलन किया था. यहां तक कि विरोध जताने के लिए संसद भवन के बाहर भैंसें भी बांध दी गई थीं. कई हफ्तों तक यह आंदोलन चलता रहा, लेकिन तमाम विरोधों के बावजूद तत्कालीन केंद्र सरकार ने देश में बहुराष्ट्रीय बीज एवं कीटनाशक कंपनियों के लिए बाज़ार खोल दिया. हाई-ब्रिड बीजों से किसानों को कितना फ़ायदा और कितना नुक़सान हुआ, उसका आकलन पिछले चौबीस वर्षों के अनुभव से बखूबी किया जा सकता है. मराठवाड़ा में नगदी फ़सल के बढ़ते प्रचलन का सबसे बुरा असर पशुओं पर पड़ा है. इन क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन में काफ़ी कमी आई है, क्योंकि कपास, गन्ना और सोयाबीन के पौधे से पशुओं को चारा नहीं मिलता. नतीज़तन, पशुधन में लगातार गिरावट हो रही है.

फड़नवीस सरकार से किसानों को निराशा

मराठवाड़ा के करोड़ों किसान मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस सरकार की फ़सल मुआवज़ा नीति से ख़ासे नाराज़ हैं. किसानों का कहना है कि पिछले साल के मुक़ाबले इस वर्ष कपास, गन्ना और सोयाबीन का भाव कम है. पिछले वर्ष सोयाबीन का भाव 4,600 रुपये प्रति क्विंटल तक गया था, वहीं इस साल सोयाबीन का बाज़ार भाव अधिकतम 2,900 रुपये है. किसानों की शिकायत है कि पिछली सरकार ने ओलावृष्टि से तबाह हुई फ़सलों के लिए प्रति एकड़ 30 हज़ार रुपये का मुआवज़ा दिया था, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे घटाकर 12 हज़ार रुपये प्रति एकड़ कर दिया है. गौवंश हत्या पर प्रतिबंध लगाने की वजह से भी किसानों की परेशानी बढ़ गई है. किसानों का कहना है कि दूध न देने वाली गायों एवं कृषि कार्य करने में अक्षम बैलों को पालना महंगा साबित हो रहा है. गौवंश सुरक्षा को लेकर सरकार ने क़ानून तो बना दिया है, लेकिन इस बाबत किसानों को कोई आर्थिक मदद नहीं दी गई है. ऐसे में पशुओं के लिए चारे और पानी का इंतज़ाम कैसे होगा, इसका उत्तर सरकार को देना चाहिए?

लीडरों की भीड़ यहां, फॉलोअर कोई नहीं!

महाराष्ट्र में हमेशा कोई न कोई चुनाव होता रहता है. लोकसभा, विधानसभा, ग्राम पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनावों की तरह यहां सहकारी चीनी मिलों, ज़िला सहकारी बैंकों और कृषि उत्पादन बाज़ार समितियों के चुनावों में भी धन-बल का प्रभाव देखा जा सकता है. पिछले दिनों मराठवाड़ा में सहकारी चीनी मिलों की चुनावी सरगर्मियां ज़ोरों पर थीं. ग़ौरतलब है कि यहां की अधिकांश सहकारी चीनी मिलों पर सूबे की राजनीति में सक्रिय बड़े सियासी घरानों का क़ब्ज़ा है. महाराष्ट्र में सत्तर और अस्सी का दशक सहकारिता आंदोलन के लिए जाना जाता है. यह आंदोलन महाराष्ट्र में काफ़ी सफल रहा है. इस दौरान बड़ी संख्या में सहकारी चीनी मिलों की स्थापना हुई. राज्य के हर ज़िले और तहसील स्तर पर ज़िला सहकारी बैंक खोले गए, लेकिन वर्ष 1990 के बाद ये तमाम सहकारी संस्थाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गईं. आज हालत यह है कि मराठवाड़ा की आधे से अधिक चीनी मिलें बंद पड़ी हुई हैं. वहीं दूसरी ओर ज़िला सहकारी और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के पास किसानों को देने के लिए एक धेला तक नहीं है. सूबे में भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या फिर शिवसेना, किसी को भी किसानों की समस्याओं से मतलब नहीं रह गया है. दरअसल, महाराष्ट्र एक प्रदेश होकर भी कई हिस्सों में बंटा हुआ है. पश्चिम महाराष्ट्र क्षेत्र से कोई मुख्यमंत्री बना, तो उसके ऊपर मराठवाड़ा और विदर्भ के साथ भेदभाव का आरोप लगता है. अगर कोई मराठवाड़ा का मुख्यमंत्री बना, तो उसके ऊपर बाकी क्षेत्रों की अनदेखी करने का आरोप लगता है. इन आरोपों की सच्चाई चाहे जो हो, लेकिन इससे बड़ा सच यह है कि मराठवाड़ा आज भी राज्य के बाकी हिस्सों की तुलना में काफी पिछड़ा हुआ है, जबकि इस क्षेत्र ने राज्य को चार मुख्यमंत्री दिए हैं. दरअसल, सूबे की सियासत में एक-दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने की एक परिपाटी-सी बन चुकी है.

किसान कंगाल और आढ़ती मालामाल

जालना ज़िले की अंबड तहसील स्थित कृषि उत्पादन बाज़ार समिति का प्रांगण. यहां एक आढ़त पर चने की बोली लगाई जा रही थी. 3,000 रुपये प्रति क्विंटल से शुरू हुई बोली 4,000 रुपये पर ख़त्म हुई. 4,000 रुपये में जिस उत्तम क्वालिटी का चना आढ़ती ने किसान से ख़रीदा, उसी का भाव जालना और औरंगाबाद की अनाज मंडियों में 5,000 रुपये से लेकर 5,500 रुपये तक था. कृषि उत्पादन बाज़ार समितियों में किसानों का किस तरह शोषण होता है, यह उसकी एक बानगी थी. बाज़ार समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद कितना अहम और मालदार होता है, इसकी झलक यहां होने वाले चुनावों में साफ़ देखी जा सकती है. इन चुनावों में पानी की तरह पैसा बहाया जाता है. चूंकि बाज़ार समितियों के चुनाव दलीय आधार पर नहीं लड़े जाते, लेकिन उम्मीदवारों को विभिन्न राजनीतिक दलों और आढ़तियों का भरपूर समर्थन मिलता है. चुनाव जीतने के बाद बाज़ार समिति के पदाधिकारी किसानों के बजाय आढ़तियों के हितों के लिए काम करते हैं. मराठवाड़ा के किसान एक तरफ़ प्रकृति की मार झेल रहे हैं, दूसरी तरफ़ अनाज व्यापारी उनका शोषण कर रहे हैं. अंबड बाज़ार समिति से एक गांव की दूरी औसतन पांच से दस किलोमीटर है. कोई किसान जब अपनी बैलगाड़ी पर चना, ज्वार, बाजरा, उड़द और अरहर लादता है, तो उस समय उसे मालूम नहीं होता है कि बाज़ार में उसकी फ़सल को क्या भाव मिलेगा. महाराष्ट्र की मंडियों में खाद्यानों का भाव चाहे कितना ही अधिक क्यों न हो, लेकिन बाज़ार समितियों में किसानों को वही भाव मिलता है, जो आढ़ती लॉबी चाहती है. अनाज के बिचौलियों का नेटवर्क गांवों से शुरू होता है और बरास्ते बाज़ार समिति देश की बड़ी अनाज मंडियों तक पहुंचता है. सरकार को मालूम है कि इसमें कौन-कौन शामिल है, लेकिन वह इस पर अंकुश नहीं लगाती, क्योंकि राजनीति और सरकार कारोबारियों को नाराज़ करके नहीं चलाई जा सकती.

मराठवाड़ा के किसानों का अर्थशास्त्र

वर्ष 1972 में मराठवाड़ा में भीषण अकाल पड़ा था, लेकिन उन दिनों किसान आत्महत्या की एक भी घटना नहीं हुई थी, क्योंकि उस समय नगदी फ़सलों का प्रचलन नहीं था. मराठवाड़ा के किसानों का अपना एक अर्थशास्त्र भी है. यहां गन्ना, मौसम्मी और अनार की खेती प्राय: वही किसान करते हैं, जिनके पास खेती की अधिक ज़मीन है. ऐसे किसान दूसरे कारोबार भी करते हैं. पानी की कमी को पूरा करने के लिए ये संपन्न किसान लाखों रुपये की लागत से एक से अधिक कई गहरे बोरवेल लगाते हैं. एक पुष्ट गन्ना तैयार होने में क़रीब 180 लीटर पानी की आवश्यकता होती है. इस तरह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सूखाग्रस्त मराठवाड़ा में गन्ना उगाने के लिए भूमिगत जल का किस पैमाने पर दोहन किया जाता होगा. मराठवाड़ा में आत्महत्या करने वाले किसानों की बात करें, तो इनमें गन्ना, मौसम्मी और अनार की खेती करने वाले बड़े किसानों की संख्या शून्य है. आत्महत्या करने वाले सर्वाधिक ऐसे किसान हैं, जो मुख्य रूप से कपास, सोयाबीन, ज्वार एवं बाजरा इत्यादि की खेती करते हैं. दरअसल, ऐसे किसान बरसात के भरोसे खेती करते हैं. बैंक और साहूकारों से क़र्ज़ लेकर खेती करना इनकी नियति बन चुकी है.

मुआवज़ा के बजाय ठोस कृषि नीति बने

महाराष्ट्र में आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारीजनों को राज्य सरकार की ओर से एक लाख रुपये का मुआवज़ा मिलता है.

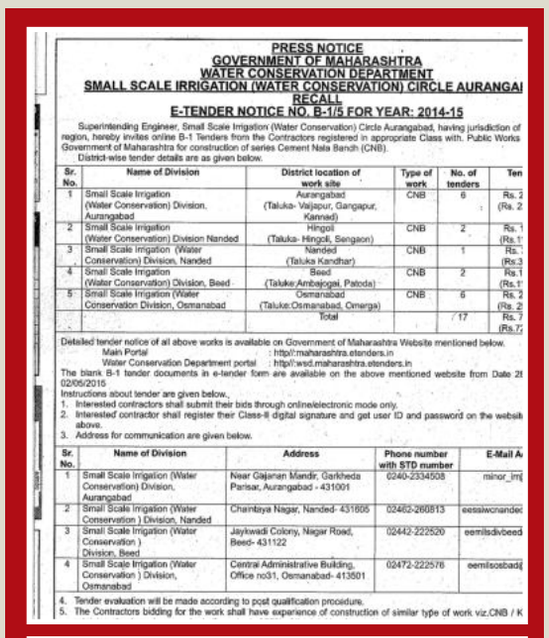

PRESS NOTICE
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA
WATER CONSERVATION DEPARTMENT
SMALL SCALE IRRIGATION (WATER CONSERVATION) CIRCLE AURANGAI
RECALL
E-TENDER NOTICE NO. B-1/5 FOR YEAR: 2014-15

Superintending Engineer, Small Scale Irrigation (Water Conservation) Circle Aurangabad, having jurisdiction of region, hereby invites online B-1 Tenders from the Contractors registered in appropriate Class with. Public Works Government of Maharashtra for construction of series Cement Nala Bandh (CNB).
District-wise tender details are as given below.

Sr. No.	Name of Division	District location of work site	Type of work	No. of tenders	Ten
1	Small Scale Irrigation (Water Conservation) Division, Aurangabad	Aurangabad (Taluka- Vaijapur, Gangapur, Kannad)	CNB	6	Rs. 2 (Rs. 2
2	Small Scale Irrigation (Water Conservation) Division Nanded	Hingoli (Taluka- Hingoli, Sengaon)	CNB	2	Rs. 1 (Rs.1
3	Small Scale Irrigation (Water Conservation) Division, Nanded	Nanded (Taluka Kandhar)	CNB	1	Rs. (Rs.3
4	Small Scale Irrigation (Water Conservation) Division, Beed	Beed (Taluke:Ambajogai, Patoda)	CNB	2	Rs.1 (Rs.1
5	Small Scale Irrigation (Water Conservation Division, Osmanabad	Osmanabad (Taluke:Osmanabad, Omerga)	CNB	6	Rs. 2 (Rs. 2
		Total		17	Rs. 7 (Rs.7

Detailed tender notice of all above works is available on Government of Maharashtra Website mentioned below.
Main Portal : http//:maharashtra.etenders.in
Water Conservation Department portal : http//:wsd.maharashtra.etenders.in
The blank B-1 tender documents in e-tender form are available on the above mentioned website from Date 2 02/05/2015
Instructions about tender are given below.
1. Interested contractors shall submit their bids through online/electronic mode only.
2. Interested contractor shall register their Class-II digital signature and get user ID and password on the websit above.
3. Address for communication are given below.

Sr. No.	Name of Division	Address	Phone number with STD number	E-Mail A
1	Small Scale Irrigation (Water Conservation) Division, Aurangabad	Near Gajanan Mandir, Garkheda Parisar, Aurangabad - 431001	0240-2334508	minor_irr
2	Small Scale Irrigation (Water Conservation) Division, Nanded	Chambiya Nagar, Nanded- 431605	02462-260813	eessiwcnande
3	Small Scale Irrigation (Water Conservation) Division, Beed	Jaykwadi Colony, Nagar Road, Beed- 431122	02442-222520	eemilsdivbeed
4	Small Scale Irrigation (Water Conservation) Division, Osmanabad	Central Administrative Building, Office no31, Osmanabad- 413501	02472-222576	eemilsosbad

4. Tender evaluation will be made according to post qualification procedure.
5. The Contractors bidding for the work shall have experience of construction of similar type of work viz.CNB / K

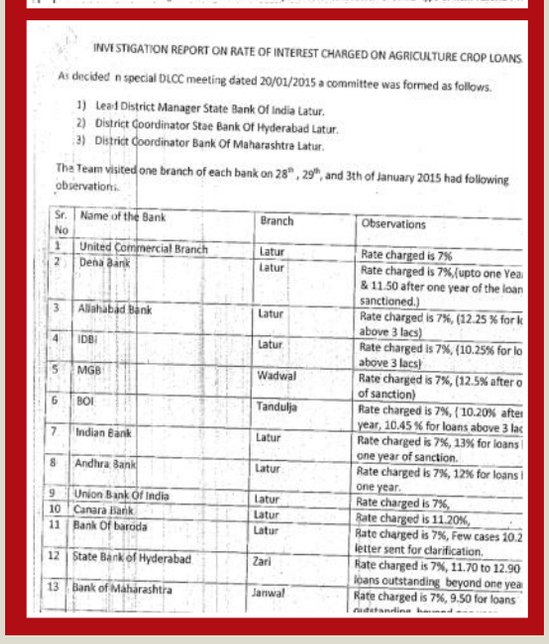

INVESTIGATION REPORT ON RATE OF INTEREST CHARGED ON AGRICULTURE CROP LOANS

As decided n special DLCC meeting dated 20/01/2015 a committee was formed as follows.

1) Lead District Manager State Bank Of India Latur.
2) District Coordinator Stae Bank Of Hyderabad Latur.
3) District Coordinator Bank Of Maharashtra Latur.

The Team visited one branch of each bank on 28th , 29th, and 3th of January 2015 had following observations.

Sr. No	Name of the Bank	Branch	Observations
1	United Commercial Branch	Latur	Rate charged is 7%
2	Dena Bank	Latur	Rate charged is 7%,(upto one Yea & 11.50 after one year of the loan sanctioned.)
3	Allahabad Bank	Latur	Rate charged is 7%, (12.25 % for l above 3 lacs)
4	IDBI	Latur	Rate charged is 7%, (10.25% for lo above 3 lacs)
5	MGB	Wadwal	Rate charged is 7%, (12.5% after o of sanction)
6	BOI	Tandulja	Rate charged is 7%, (10.20% afte year, 10.45 % for loans above 3 lac
7	Indian Bank	Latur	Rate charged is 7%, 13% for loans one year of sanction.
8	Andhra Bank	Latur	Rate charged is 7%, 12% for loans one year.
9	Union Bank Of India	Latur	Rate charged is 7%,
10	Canara Bank	Latur	Rate charged is 11.20%,
11	Bank Of baroda	Latur	Rate charged is 7%, Few cases 10.2 letter sent for clarification.
12	State Bank of Hyderabad	Zari	Rate charged is 7%, 11.70 to 12.90 loans outstanding beyond one yea
13	Bank of Maharashtra	Janwal	Rate charged is 7%, 9.50 for loans

उक्त राशि में मृत किसान के आश्रितों को 30 हज़ार रुपये नगद मिलते हैं, शेष 70 हज़ार रुपये की राशि को आश्रितों के नाम पर फिक्स कर दिया जाता है. अब राज्य की नई भाजपा सरकार मुआवज़ा राशि को एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की योजना बना रही है. अगर सरकार इस मसौदे को अमल में लाती है, तो इसके दीर्घकालिक परिणाम काफ़ी गंभीर हो सकते हैं. सरकार को इसका सियासी फ़ायदा तो मिलेगा, लेकिन किसानों को भविष्य में इसकी बड़ी क़ीमत चुकानी पड़ेगी. दरअसल, देश के किसानों को मुआवज़े से अधिक ठोस कृषि नीति की ज़रूरत है. केंद्र में सरकार किसी की हो, उसकी कृषि नीति किसानों से ज़्यादा व्यापारियों के लिए फ़ायदेमंद रही है. अक्सर यह देखा गया है कि रबी और ख़रीफ की फ़सल तैयार होने के समय भाव अचानक कम हो जाता है. किसानों को हर हाल में अपनी फ़सल बेचनी होती है, क्योंकि एक तो उन्हें महाजनों का क़र्ज़ चुकाना पड़ता है, दूसरा यह कि अनाज रखने के लिए उनके पास पर्याप्त जगह नहीं होती. किसानों की इस मजबूरी का सीधा लाभ व्यापारियों को मिलता है. किसानों के घर से एक-एक दाना कम भाव में ख़रीद लेने के बाद बिजनेस लॉबी की चहलक़दमी नई दिल्ली स्थित केंद्रीय मंत्रालयों में बढ़ जाती है. इसके बाद शुरू होता है कारोबार का गंदा खेल. कपास और चीनी का निर्यात करना कारोबारियों, केंद्रीय मंत्रियों और मंत्रालय के सचिवों के लिए कब फ़ायदेमंद होगा, इसकी पटकथा नई दिल्ली में लिखी जाती है. आज़ादी के बाद देश में जितनी भी सरकारें बनी हैं, उन सबने मुआवज़े के नाम पर किसानों को ठगा है. देश के करोड़ों किसानों को सरकार से मुआवज़ा नहीं, बल्कि फ़सल की सही क़ीमत चाहिए. किसानों को उचित सब्सिडी और सभी फ़सलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहिए. भूमंडलीकरण का सबसे अधिक फ़ायदा देश के व्यापारी उठा रहे हैं, जबकि इसका सबसे ज़्यादा नुक़सान किसानों को झेलना पड़ रहा है. थोड़े-बहुत मुआवज़े से किसानों की हालत में सुधार नहीं हो सकता.

सस्ती कार और महंगी खेती

चौथी दुनिया के पास एक जांच रिपोर्ट की प्रति मौजूद है. यह रिपोर्ट विभिन्न बैंकों द्वारा किसानों को खेती के लिए दिए गए क़र्ज़ पर ब्याज वसूलने को लेकर है. यह रिपोर्ट बताती है कि लगभग सारे बैंक किसानों से 13 फ़ीसद तक सालाना ब्याज वसूले हैं. ग़ौरतलब है कि अगर एक लाख रुपये प्रतिमाह कमाने वाले किसी व्यक्ति को एक कार या बंगला लेना हो, तो उसे अधिक से अधिक 10 से 11 फ़ीसद ब्याज देना होता है. मराठवाड़ा के लातूर ज़िले में किसानों को सात फ़ीसद से अधिक ब्याज दरों पर क़र्ज़ देने वाले 13 सरकारी बैंक और तीन निजी बैंक हैं, जैसे यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, देना बैंक, इलाहाबाद बैंक, आईडीबीआई बैंक, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, आंध्रा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक. जबकि आईसीआईसीआई बैंक ने इस बाबत कोई रिपोर्ट जांच समिति के पास नहीं भेजी है.

का बरखा जब कृषि सुखाने

महाराष्ट्र सरकार के जल संरक्षण विभाग (औरंगाबाद मंडल) ने 29 अप्रैल, 2015 को टाइम्स ऑफ इंडिया अख़बार में वर्ष 2014-15 के लिए ई-निविदा संख्या- बी-1/5 प्रकाशित कराई. उक्त निविदा में औरंगाबाद, हिंगोली, नांदेड़, बीड और उस्मानाबाद ज़िलों की 10 तहसीलों में सीमेंट नाला बांध (सीएनबी) के निर्माण के लिए कुल 727.39 लाख रुपये की प्राक्कलित राशि तय की गई. हैरानी की बात यह है कि उक्त ई-निविदा में कार्य समाप्ति का कोई ज़िक्र नहीं है. उक्त निविदा की तारीख़ और उसमें भाग लेने वाले ठेकेदारों के आवेदन की स्क्रूटनी की प्रक्रिया में ही मई महीना बीत जाएगा. इस इलाक़े में मानसून अमूमन जून में सक्रिय होता है. इस तरह मराठवाड़ा क्षेत्र में सीमेंट नाला बांध बनाने का काम अगर जून में शुरू होता है, तो इसे पूरा होने में कम से कम छह महीने या उससे अधिक समय लग सकता है. इस बाबत सवाल पूछे जाने पर लघु सिंचाई परियोजना (जल संरक्षण) औरंगाबाद क्षेत्र के अधीक्षण अभियंता एसएच खरात ने बताया कि इससे पहले भी एक निविदा विभाग की ओर से प्रकाशित की गई थी, लेकिन स्क्रूटनी में कोई भी ठेकेदार सफल नहीं हुआ. लिहाज़ा विभाग ने पुन: ई-निविदा प्रकाशित की है. यह पूछे जाने पर कि मराठवाड़ा क्षेत्र में जालना सर्वाधिक सूखा पीड़ित ज़िला है, लेकिन वहां किसी तहसील में सीमेंट नाला बांध बनाने की योजना इस निविदा में नहीं है. इस पर खरात ने कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया. दिलचस्प बात यह है कि प्रशासन को इस तरह के कार्य मानसून शुरू होने से पहले पूरे कर लेने चाहिए, ताकि ख़रीफ़ फ़सल के समय किसानों को सिंचाई का लाभ मिल सके.

आत्महत्या करने वाले बटाईदार किसान अपात्र

बटाई पर खेती करने वाला किसान अगर फ़सल नाक़ाम रहने और क़र्ज़ की वजह से आत्महत्या करता है, तो उसके परिवारीजन सरकारी मुआवज़े के हक़दार नहीं हैं. महाराष्ट्र सरकार की इस मुआवज़ा नीति में अमानवीय पहलू की झलक साफ़ देखी जा सकती है. एक जनवरी, 2015 से लेकर 27 अप्रैल, 2015 के बीच मराठवाड़ा के आठ ज़िलों क्रमश: औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड़, बीड, लातूर और उस्मानाबाद में कुल 268 किसानों ने आत्महत्या की. प्रशासन ने इनमें से 158 किसानों के परिवारीजनों को मुआवज़े का हक़दार माना और उन्हें एक लाख रुपये का मुआवज़ा दिया, जबकि 36 किसानों को प्रशासन ने अपात्र क़रार दिया. ऐसे किसान परिवारों को किसी तरह की सरकारी मदद नहीं दी गई. उल्लेखनीय है कि इन अपात्रों में भूमिहीन किसानों की संख्या अधिक है, जो दूसरे के खेतों में बटाई करते हैं. पिछले साल यानी एक जनवरी, 2014 से 31 दिसंबर, 2014 के बीच मराठवाड़ा के विभिन्न ज़िलों में 574 किसानों ने आत्महत्या की. इनमें से 429 किसानों के परिवारीजनों को सरकारी मुआवज़े का लाभ मिला, जबकि बाकी 143 किसानों को प्रशासन ने अपात्र क़रार दिया. देश में भूमिहीन बटाईदार किसानों की संख्या करोड़ों में है, लेकिन ऐसे किसानों को न तो बैंक कृषि क़र्ज़ देते हैं और न उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का लाभ मिल पाता है. फ़सल नाक़ाम होने पर भी उन्हें कोई सरकारी मदद नहीं मिलती. क़र्ज़ से दबा ऐसा किसान अगर आत्महत्या कर लेता है, तो उसे कफ़न भी उधार के पैसों से नसीब हो पाता है. तकलीफदेह बात यह है कि बटाईदार किसानों की इस गंभीर समस्या पर सरकार चुप और संसद ख़ामोश है. ■

arsingh@chauthiduniya.com

जालना के बाज़ार समिति में किसानों की ऊपज की मनमानी बोली लगा रहे आढ़ती.

कीटनाशकों का व्यापार : मराठवाड़ा में साहूकारों का नया धंधा.

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 07 अंक 10
दिल्ली, 11 मई-17 मई 2015
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)

सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999
6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-42296060
+91-8451050786
+91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

भूकंप पीड़ितों की जुबानी

...जब सामने गुजरी मौत

अरुण तिवारी

बीते 25 अप्रैल की दोपहर को नेपाल से होकर गुजरी भूकंप नाम की त्रासदी से जो भी बचकर निकला है, वह यही कह रहा है कि हमने एक गुलजार जगह को बंजर होते देखा है. हर उस आदमी के सामने मौत का वह नजारा सामने पसरा हुआ है, जिसे उसने उन क्षणों में जिया था. जो भी नेपाल की उस भयावह त्रासदी से गुजरकर भारत लौट रहा है, उससे बात करते हुए मौत का सन्नाटा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है. 1934 के बाद नेपाल में आए इस विनाशकारी भूकंप ने इस गरीब देश को बीसियों साल पीछे धकेल दिया है. काठमांडू में शायद ही कोई ऐसा घर बचा होगा, जहां से लाशें न निकल रही हों. मुर्दों की संख्या इतनी कि पशुपति के आर्या घाट पर निर्वाण के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है.

नेपाल में आए भूकंप में जिंदा बचने वालों ने उस त्रासदी की कहानी बताई जिसने घरों, मंदिरों और ऐतिहासिक इमारतों को पल भर में बर्बाद करके रख दिया. इतने लोगों की मौत के बाद बचे हुए लोगों के लिए अब आश्रय, भोजन और साफ स्वच्छता की बुनियादी जरूरतों को पूरा किए जाने की चुनौती है. भारत के सबसे करीबी देश कहे जाने वाले नेपाल को 7.9 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने हिलाकर रख दिया. सड़कों में बड़ी-बड़ी दरारें आ गई हैं और इमारतों व रहने की जगहें ढह जाने के कारण हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा. अब ये सारे लोग खुले आसमान के नीचे रहने के लिए बाध्य हैं क्योंकि अब उनके पास वह घर नहीं है जिसे उन्होंने पूरी जिंदगी की मेहनत के बाद बनाया था. कई कामगारों सहित बड़ी संख्या में यहां आए भारतीयों ने कहा कि उन्हें भोजन और साफ-सफाई जैसी बुनियादी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. यहां कोलकाता से श्रमिकों ने अपनी परेशानियों के बारे में बताया. वे वापस लौटना चाहते हैं. उन्होंने बताया कि हम यहां काम करने आए थे लेकिन इतनी बड़ी त्रासदी देखने के बाद हम वापस चले जाएंगे. वे कहते हैं कि पता नहीं हम कैसे घर लौटेंगे? बिजली नहीं रहने के कारण कोई सूचना नहीं है.

कोलकाता के रहने वाले एक और श्रमिक ने कहा हम सब यहां काम करते हैं. हमें पहले से यह मालूम है कि नेपाल भूकंप के मामले में संवेदनशील जगह है लेकिन इतनी बड़ी त्रासदी आएगी, इसकी किसी को आशंका नहीं थी. उन्होंने बताया कि शुरुआती झटकों के समय हमें लगा कि हल्के झटके ही लगेंगे लेकिन कुछ ही देर बाद यह महसूस होने लगा कि कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली है. उसी दौरान एक और भयावह दृश्य हमारे सामने से गुजरा, जब हमने देखा कि मलबे में दबी एक महिला किसी तरह निकलने का प्रयास कर रही है. हमने देखा कि आस-पास के लोग बदहवासी की हालत में सड़क पर भाग रहे हैं. अगल-बगल इमारतें भी गिर रही थीं, जो निकल पाने में सफल हो जा रहा था, वही सफल था. अन्यथा कई लोग सड़कों से भागने के दौरान ही बगल की इमारत उनके ऊपर ढह जाने के कारण दब गए. पता नहीं, उन लोगों का क्या हुआ? वे बचे या नहीं बचे. हम लोग जहां रहते थे, वहां आस-पास के लोगों का भी कोई हाल नहीं मिल रहा है. लोग भागे जा रहे थे, भागे जा रहे थे. कुछ भी बचने की कोई उम्मीद नहीं थी. स्थिति यह है कि घायलों को अस्पताल में जगह नहीं मिल पा रही है. अन्य लोगों की तरह आभास केशी ने भी इस जलजले को महसूस किया. आभास ने कहा कि जब भूकंप के हल्के झटके लगने शुरू हुए तो मैं अपने कमरे में ही बैठा हुआ था. उसी दौरान हमारे बैठक कक्ष में भूकंप का तेज झटका महसूस हुआ और वहां रखा सामान इधर-उधर गिर पड़ा. घर की बगल में एक खुला मैदान है. हम सभी डरे-सहमे व सलामती की दुआ करते हुए वहां एकत्रित हुए. मैंने देखा कि हमारे घर के परिसर की छह फीट ऊंची दीवार जमींदोज हो गई, जिससे रास्ता बंद हो गया. लोग जान बचाने के लिए अपने घरों से निकल खुली जगहों की ओर दौड़ रहे थे.

मैंने पहली बार महसूस किया कि कंक्रीट की इमारतें तक भूकंप जैसी आवाज पैदा कर सकती हैं. उसके बाद लोगों में चीख-पुकार मचनी शुरू हो गई. खुशकिस्मती से हमारी और हमारे दर्जनभर पड़ोसियों की इमारतें सही-सलामत खड़ी थीं, लेकिन भूतल पर स्थित इमारत के पानी के टैंक फट गए. टैंक का फटना एक धमाके जैसा था. शुरुआती झटका थमने के बाद हमें क्या करना चाहिए, हमने इस पर विचार-विमर्श करना शुरू किया. हम में से कुछ तुरंत कुछ चादरें और खाने-पीने की चीजें लेने के लिए घर के अंदर दौड़े, क्योंकि भूकंप के बाद दोबारा आए जोरदार झटके से हमें स्पष्ट हो गया कि हम इमारत में वापस नहीं आ सकेंगे. मैंने वहां से दो मोटरसाइकिलें निकालीं और उन्हें खुली जगह पर रख दी, ताकि जरूरत पड़ने पर मैं किसी को कच्चे रास्ते से उन पर अस्पताल ले जा सकूं. शाम में मैंने अपने आसपास की जगहों का मोटा-मोटा जायजा लिया. कन्वेंशन सेंटर में कई हजार लोग जुटे हुए थे, लेकिन उससे आगे टुंडीखेल मैदान में हजारों लोग एकत्रित थे. यह जगह काठमांडू के हाइड पार्क जैसी है. युवा उद्यमियों के एक समूह को एक बहुत बड़ी प्लास्टिक शीट मिली थी, जिसकी मदद से उन्होंने एक तंबू बनाया. इसमें करीब 60-70 लोगों को आश्रय मिल गया. रात खुले आसमान तले गुजरी. आंखों से नींद गायब थी. न कोई ट्रैफिक का शोर और न कोई चहल-पहल. वह मंजर ऐसा था, मानो वक्त ठहर गया हो.

चारों तरफ फैली तबाही संतोष वापस लौटे हैं. नेपाल में भूकंप से सहमे संतोष के परिजन व गांव वाले उसके सकुशल वापसी व उसके वहां रहने वाले अन्य लोगों की सलामती की खबर पाकर खुश हैं. पीड़ित काठमांडू में व्यवसाय करता है. वह वहां कई रिश्तेदारों के साथ रहता है. उसने गांव वालों को आंखों देखा हाल सुनाया. उसने बताया कि भूकंप के दौरान वह अपने कार्यालय में ही था. जैसे ही भूकंप के झटके लगने शुरू हुए तो हम जान बचाकर भागे. इस पूरी त्रासदी में हमारे ऑफिस के कई कर्मचारी लापता हैं. उनके बारे में कोई खबर नहीं मिल रही है.

ईश्वर ही जानता है. नेपाल में आए भूकंप में जख्मी हुए पूर्वी चंपारण के छौड़ादानो थाना क्षेत्र के नारायण पकड़िया चौक निवासी राजकिशोर प्रसाद ने बताया कि वह पिछले नौ वर्षों से काठमांडू के काली माता में रहकर फर्नीचर बनाने का कार्य कर रहे थे. राजकिशोर, जिनके हाथ की हड्डी गत शनिवार को नेपाल में आए जलजले में टूट गयी थी, ने भूकंप के बाद के वहां का मंजर को बयान करते हुए बताया कि वह खुद को खुशकिस्मत मानते हैं कि इतने विनाशकारी भूकंप में केवल उनके हाथ की हड्डी टूटी और उनकी जान बच गई. उन्होंने बताया कि वहां भूकंप के बाद मकानों के मलबे में लाशें दबी हुई थीं और सैकड़ों जख्मी लोग दर्द से कराह रहे थे और मदद के लिए चीख-पुकार रहे थे, पर अफरा-तफरी के उस माहौल में उनकी सुध किसे थी, सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आ रहे थे. उसके तीन दोस्तों ने छत से कूदकर अपनी जान बचाई. उन्होंने कहा कि 45 हजार रुपये में एक मिनी बस किराये पर लेकर वे किसी प्रकार अपने वतन वापस लौट पाए हैं. राजधानी काठमांडू की ज्यादातर इमारतें बर्बाद हो चुकी हैं. जो घर बचे भी हैं, वहां रहने वाले लोग इस भय से जगह छोड़कर भाग चुके हैं कि कहीं दोबारा उसी तीव्रता वाला भूकंप आ गया तो फिर क्या होगा? इस तरह की परिस्थितियों में चोर भी सक्रिय हैं जो घर की वस्तुओं को लूट कर ले जा रहे हैं. प्राइवेट वाहन से आठ घंटे का सफर 24 घंटे में तय कर लोग बॉर्डर पहुंच रहे हैं. वाहन वाले मजबूरी का गलत फायदा उठाकर मनमानी भाड़ा वसूल रहे हैं. उसको वहां से आने में 48 घंटे लगे. मगर, वह भूख से परेशान था. नेपाल में आए भयंकर भूकंप के चलते वहां फंसे भारतीयों को निकालने का काम निरंतर जारी है. काठमांडू से दिल्ली लाए गए भूकंप पीड़ितों से

चारों तरफ फैली तबाही को देखकर माधोपुरा में रहने वाला संतोष वापस लौटा है. नेपाल में भूकंप से सहमे संतोष के परिजन व गांव वाले उसके सकुशल वापसी व वहां रहने वाले अन्य लोगों की सलामती की खबर पाकर खुश हैं. पीड़ित काठमांडू में व्यवसाय करता है. वह वहां कई रिश्तेदारों के साथ रहता है. उसने गांव वालों को आंखों देखा हाल सुनाया. उसने बताया कि भूकंप के दौरान वह अपने कार्यालय में ही था. जैसे ही भूकंप के झटके लगने शुरू हुए तो हम जान बचाकर भागे. इस पूरी त्रासदी में हमारे ऑफिस के कई कर्मचारी लापता हैं. उनके बारे में कोई खबर नहीं मिल रही है.

30 लोग बिहार के थे. इकसे बाद ट्रेन से पटना पहुंचे इन परिवारों के चेहरे पर भूकंप का खौफ साफ दिख रहा था. लोगों ने बताया कि नेपाल में सुपौल जिले के कई परिवार अभी भी फंसे हैं. सुपौल के महावीर चौक पर रहने वाले विमल मोहनका के भाई बद्री प्रसाद अग्रवाल सहित परिवार के 10 लोग काठमांडू में तीन दिनों से फंसे हैं. वहां फंसे हुए लोगों में छोटे-छोटे बच्चे भी शामिल हैं. इन लोगों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए सुपौल के जिला प्रशासन ने राज्य और केंद्र सरकार से मदद मांगी है. परिजनों का कहना है कि काठमांडू के लिंक रोड स्थित एक पार्क में पूरा परिवार पानी के लिए तरस रहा है. परिजनों का कहना है कि फोन पर बात हुई थी, वे तीन दिनों से एक मैदान मे रात बीता रहे हैं. उनलोगों ने बताया कि वहां सैंकड़ो नेपाली नागरिक भूखे-प्यासे किसी तरह दिन गुजार रहे हैं.

चीन भी कर रहा भूकंप पीड़ितों की मदद

नेपाल में आए भीषण भूकंप के कुछ ही घंटों के भीतर वहां बड़े पैमाने पर भारत की ओर से राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए गए थे. भारत वहां किसी भी दूसरे देश की तुलना में व्यापक पैमाने पर बचाव और राहत अभियान में जुटा है. चीन, जो नेपाल में निवेश के मामले में भारत को 2014 में ही पछाड़ चुका है, अब मानवीय सहायता के इस काम में भारत से कदम मिलाने के लिए संघर्ष कर रहा है.

भारत और चीन दोनों ही एशिया की उभरती हुई वैश्विक शक्तियां हैं. नेपाल को इस मुश्किल समय से बाहर निकालने के लिए दोनों ने ही पूरी सहायता देना शुरू कर दिया है. हालांकि मदद के मामले में भारत चीन से कहीं ज्यादा आगे है, लेकिन अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो दुनिया के अन्य देशों से ज्यादा ये दोनों देश नेपाल को मदद कर रहे हैं. चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन और भारत नेपाल के पड़ोसी हैं. हम एक साथ वहां काम करना चाहेंगे और भारत के साथ सकारात्मक समन्वय बनाते हुए नेपाल को कठिनाइयों से निकालने और देश के पुनर्निमाण में मदद करेंगे. इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि भूकंप के बाद भारतीय राहत दल सबसे पहले नेपाल पहुंच गया था. भारत नेपाल के सिस्टम और वहां के लोगों से भलीभांति परिचित है. राजनीतिक कारणों से भी यह अपेक्षित था कि भारत मदद के साथ तेजी से पहुंचेगा. खासकर तब, जब वह यह चाहता हो कि चीन और माओवादियों को वहां जमने का मौका न दिया जाए. दरअसल, भारत जो कुछ भी कर रहा है, अगर वो नहीं करता, तो आश्चर्य का विषय होता. ■

feedback@chauthiduniya.com

केन्द्र सरकार ने हर संकट के नाम पर बिहार को हरसंभव मदद का वायदा किया है. वह चाहे बेमौसम बरसात से पीड़ित किसानों को फसल क्षति का मुआवजा हो या आंधी व ओलावृष्टि से पीड़ित आबादी को राहत देने का मामला हो या भूकम्प पीड़ितों को सहायता का. केन्द्र हर बार मंत्रियों की टीम बिहार भेजता रहा है और उस टीम में शामिल मंत्री व उसके नेता बिहार के साथ खड़े रहने व उसे हरसंभव मदद का मुक्त–कंठ से वायदा करते रहे हैं, लेकिन पिछले कई हफ्तों से जारी इस कदमताल से बिहार को कैसे और क्या मिलना है, यह खुलासा कहीं से नहीं हो रहा है.

सभी फोटो–संजय कुमार

राहत की राजनीति या राजनीति की राहत

बिहार में प्रकृति की मार जब भी पड़ती है, उत्तर बिहार के जिलों पर अधिक पड़ती है. उत्तर बिहार के कोई डेढ़ दर्जन जिले प्रकृति के कोपभाजन रहे हैं, लेकिन पूर्णिया, कोशी और दरभंगा के अतिरिक्त तिरहुत प्रमंडल के सीतामढ़ी, शिवहर, मुंगेर प्रमंडल के खगड़िया, बेगूसराय व भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल को सबसे अधिक मार झेलनी पड़ती है. ये क्षेत्र नदियों की शरणास्थली के तौर पर जाने जाते हैं. बिहार की 73 प्रतिशत भूमि और 74 प्रतिशत आबादी बाढ़ पीड़ित है, जिसका अधिकांश क्षेत्र यही है. पूर्णिया और सहरसा जिले की कोशी के जलप्रलय, जिसे कुसहा त्रासदी कहते हैं, की पीड़ा से अब तक मुक्त नहीं हुए हैं. उस त्रासदी से आतंकित भूमि और आबादी में अभी विश्वास का माहौल बनाना है, लेकिन इस भूमि को त्रासदी से मुक्ति नहीं मिलनी है. इसलिए इस बार भी इसी क्षेत्र में रूप बदल कर संकटों का आना हुआ है. बिहार सरकार जो भी रिपोर्ट तैयार करे और केन्द्र जितनी और जैसी भी सहायता दे दे, यह सहायता बहुत मायने नहीं रखता.

चौथी दुनिया ब्यूरो

बिहार पर प्रकृति पिछले कुछ हफ्तों में कुछ ज्यादा ही नाराज लगती है. पहले बेमौसम बरसात से हजारों एकड़ में लगी गेहूं, मकई व दलहन–तिलहन के साथ–साथ केला, आम व लीची की बागानी फसलों की व्यापक क्षति हुई. इस मार से किसानों को दिन में तारे दिखने लगे थे कि आंधी के साथ ओला–वृष्टि (काल बैसाखी) की ऐसी चोट पड़ी कि राज्य के हजारों आशियाने उजड़ गए. इसकी चोट पर किसी मरहम की तलाश चल ही रही थी कि नेपाल में धरती डोल गई और आशियानों के साथ जिन्दगी की उम्मीदें भी धराशायी हो गई. यह सिलसिला इतनी तेजी से चला कि सूबे के सुदूर ग्रामांचल से लेकर पटना–दिल्ली तक भौंचक रह गई. पहले तो बेमौसम बरसात और फिर तूफान व ओला–वृष्टि में कई दर्जन लोग मारे गए थे. जो बचा, उसकी रही–सही कसर भूकम्प ने पूरी कर दी. भूकम्प के कहर से डेढ़ सौ से अधिक लोगों की मौत हो गई, तीन सौ से अधिक लोग घायल हो गए और मुख्यतः नेपाल के सीमावर्त्ती और आम तौर पर उत्तर बिहार के जिलों में हजारों लोग बेघर हो गए हैं. पहले बेमौसम बरसात, फिर आंधी व ओला–वृष्टि और उसके बाद भूकम्प के कहर ने बिहार में ऐसी तबाही मचाई है कि उनके जख्म शायद दशकों में भी न भरें. बिहार सरकार और केन्द्र सरकार ने तत्परता से बचाव व राहत की व्यवस्था की है. बिहार सरकार ने बेमौसम बरसात से परेशान किसानों को राहत देने के लिए साढ़े सतरह अरब रुपये से अधिक की राशि जारी कर दी है. जरूरत पड़ने पर और रकम जारी करने का भरोसा दिलाया है. इन प्राकृतिक आपदाओं में मृत लोगों के परिजनों को चार–चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा तो की ही गई, चौबीस से अड़तालीस घंटे के दौरान अनुग्रह राशि के चेकों की संबंधित परिवारों को अदायगी भी कर दी गई. इतना ही नहीं, भूकम्प में नेपाल में मरे बिहारी लोगों के परिजनों को भी इस अनुग्रह–राशि का भुगतान किया जा रहा है. नेपाल के भूकम्प पीड़ितों को सुविधा देने के लिए सीमावर्त्ती नगर रक्सौल, बैरगनिया, जयनगर और जोगबनी के साथ–साथ कोई एक दर्जन अन्य स्थानों पर भी राहत शिविर चलाए जा रहे हैं. ऐसे अनेक स्थानों पर सीमा सुरक्षा बल (एसेसबी) के जवान भी कई राहत शिविर चला रहे हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की भरपूर मदद मिल रही है. बिहार के भूकम्प पीड़ितों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था की गई है. बेमौसम बरसात, आंधी– ओलावृष्टि व भूकम्प से हुई क्षति के आंकलन का काम शुरू करने का दावा किया गया है. अधिकारियों का कहना है कि फसल गंवाने वाले किसानों से मुआवजे के लिए आवेदन हासिल किए जा रहे हैं. पूरी तरह बेघर हुए लोगों की सूची तो तैयार की ही जा रही है, क्षतिग्रस्त मकानों–घरों का भी सर्वेक्षण कार्य तेजी से चल रहा है. अगले कुछ हफ्तों में पीड़ितों को मुआवजे की रकम का भुगतान भी कर दिया जाएगा.

प्राकृतिक संकट के क्षण में इस बचाव व राहत कार्य का सबसे प्रशंसनीय पक्ष है–राज्य और केन्द्र सरकार का एक साथ होना. ऐसा विरल ही होता है–कम से कम बिहार में केन्द्र राज्य के बीच ऐसा समन्वय तो पिछले कई वर्षों या दशकों में देखने को नहीं मिला. बेमौसम बरसात से फसल के मारे जाने पर केन्द्र ने अपनी चिंता जताई थी और मदद का आश्वासन दिया था. आंधी और ओलावृष्टि से जब बिहार के दर्जनों जिलों के तहस–नहस होने की खबर आई तो केन्द्र अत्यधिक संवेदनशील हो गया, सक्रिय दिखने लगा. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वयं चिंता जताई, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री से बातचीत की और केन्द्रीय मंत्रियों की टीम के साथ मौका–मुआयना के लिए बिहार आए. इस टीम में कृषि मंत्री राधामोहन सिंह और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद भी शामिल थे. श्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आंधी और ओलावृष्टि से सबसे अधिक प्रभावित पूर्णिया व मधेपुरा जिलों के विभिन्न क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया. इस सर्वेक्षण में बिहार भाजपा के दिग्गज नेताओं सुशील कुमार मोदी और नंदकिशोर यादव को भी शामिल कर लिया गया था. सर्वेक्षण के बाद केन्द्र और राज्य सरकार के ये नुमाइंदे पूर्णिया में मीडिया से रू–ब–रू हुए तो दो विपरीत राजनीतिक सत्ता ध्रुवों में अद्भुत सद्भाव दिखा. राजनाथ सिंह ने कहा कि बिहार सरकार बेहतर काम कर रही है. केन्द्र बिहार के साथ है और विपदा की इस घड़ी में हरसंभव सहयोग किया जाएगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री और केन्द्र सरकार के हम आभारी हैं. इस संकट के क्षण में उन्होंने अद्भुत तत्परता दिखाई है और हरसंभव सहयोग का वायदा किया है. गृह मंत्री के अनुसार बिहार सरकार आंधी और ओलावृष्टि को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट केन्द्र को सौंपेगी. इस रिपोर्ट के अध्ययन के बाद ही केन्द्र पीड़ित बिहार को मदद की घोषणा करेगा, लेकिन आंकलन रिपोर्ट तैयार होने के पहले ही धरती डोल गई और बिहार का प्रशासन इस आफत से तहस–नहस आबादी व क्षेत्र को फौरी राहत देने में जुट गया. नेपाल का मामला होने के कारण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भूकम्प के बचाव व राहत को लेकर स्वयं अत्यधिक सक्रिय रहे और विदेश मंत्रालय सहित अन्य सारे संबंधित मंत्रालयों को कार्य में झोंक दिया, लेकिन बिहार को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लगातार संपर्क में रहे और यहां भूकम्प की स्थिति का जायजा लेते रहे. भूकम्प पीड़ितों को राहत देने के माले में नीतीश कुमार की सक्रियता को लेकर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में उन्हें धन्यवाद दिया, उनका आभार जताया. केन्द्र ने बिहार की क्षति का जायजा लेने केन्द्रीय मंत्री अनंत कुमार व राधामोहन सिंह के अलावा धर्मेन्द्र प्रधान को भेजा. प्रधानमंत्री ने सुशील कुमार मोदी से फीडबैक लिया. केन्द्र सरकार इस संकट में बिहार को सारी सहायता देने को तत्पर दिखती रही है. अब इस संकट में फौरी राहत से फुरसत पाने के बाद ही प्राकृतिक आपदाओं से बिहार में हुई क्षति की रिपोर्टें तैयार होंगी, केन्द्र से मदद मांगी जाएगी. इन रिपोर्टों को तैयार करने में अब जो वक्त लगे.

बिहार में प्रकृति की मार जब भी पड़ती है, उत्तर बिहार के जिलों पर अधिक पड़ती है. उत्तर बिहार के कोई डेढ़ दर्जन जिले प्रकृति के कोपभाजन रहे हैं, लेकिन पूर्णिया, कोशी और दरभंगा के अतिरिक्त तिरहुत प्रमंडल के सीतामढ़ी, शिवहर, मुंगेर प्रमंडल के खगड़िया, बेगूसराय व भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल को सबसे अधिक मार झेलनी पड़ती है. ये क्षेत्र नदियों की शरणास्थली के तौर पर जाने जाते हैं. बिहार की 73 प्रतिशत भूमि और 74 प्रतिशत आबादी बाढ़ पीड़ित है, जिसका अधिकांश क्षेत्र यही है. पूर्णिया और सहरसा जिले की कोशी के जलप्रलय, जिसे कुसहा त्रासदी कहते हैं, की पीड़ा से अब तक मुक्त नहीं हुए हैं. उस त्रासदी से आतंकित भूमि और आबादी में अभी विश्वास का माहौल बनाना है, लेकिन इस भूमि को त्रासदी से मुक्ति नहीं मिलनी है. इसलिए इस बार भी इसी क्षेत्र में रूप बदल कर संकटों का आना हुआ है. बिहार सरकार जो भी रिपोर्ट तैयार करे और केन्द्र जितनी और जैसी भी सहायता दे दे, यह सहायता बहुत मायने नहीं रखता. कुसहा त्रासदी से पीड़ित हजारों परिवारों का पुनर्वास अब प्रक्रिया के पेच में फंसा है. इस बार भी आंधी व ओलावृष्टि से पीड़ित परिवार को अनुग्रह राशि का भुगतान तो हो गया, पर बैंक में खाता न होने के कारण आधा दर्जन से अधिक परिवारों का चेक पड़ा है. उनके लिए एक ही रास्ता है, बैंक में उन परिवारों का खाता खुलवाया जाए, लेकिन अधिकारियों को फुर्सत कहां है. अभी वे भूकम्प राहत में लगे हैं. शायद इसके बाद कुछ करें, यदि कोई और जरूरी काम न आ जाए. इसी तरह क्षति के सर्वेक्षण का काम भी या तो शुरू ही नहीं हुआ है या कागजों पर ही युद्धस्तर पर चल रहा है. वस्तुतः बिचौलिया संस्कृति का विस्तार राजधानी पटना और जिला–प्रखंड मुख्यालयों से आगे पंचायत स्तर तक हो गया है. बिहार के गांवों में बिचौलिया–मुखिया–पंचायत सचिव या अन्य कारिंदों का काला त्रिकोण विकसित हो गया है, जो सरकारी कल्याण योजनाओं को तो चाट ही रहा है, प्राकृतिक आपदा से पीड़ितों के हिस्से को भी डकार रहा है. क्षति के सर्वेक्षण के नाम पर बिहार के प्राकृतिक आपदा पीड़ित जिलों में ऐसा नज़ारा आम है, लेकिन इस ओर देखने की फुरसत अभी किसी को नहीं है, राजनीति को और न नौकरशाही को. अभी तो केन्द्र और राज्य की सरकारें प्राकृतिक संकट के दौर में राहत के नाम पर कदमताल कर रही हैं.

> नरेन्द्र मोदी और नीतीश कुमार का यह कदमताल अनायास तो नहीं ही है, यह कदमताल राजनीतिक शह-मात के खेल का ही एक अंग है. इन प्राकृतिक आपदाओं ने नीतीश कुमार को नये सिरे से जनता के बीच गहरे तक जाने का एक मौका दिया है और वह इसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं. नीतीश ने बचाव-राहत कार्य का पूरा रोड-मैप खुद तैयार किया, अधिकारियों की शिविरों व अन्य स्थानों पर तैनाती की, मंत्रियों को जिलों में कैम्प करवाया और सारी कार्रवाई का पर्यवेक्षण खुद कर रहे हैं.

नरेन्द्र मोदी और नीतीश कुमार का यह कदमताल अनायास तो नहीं ही है, यह कदमताल राजनीतिक शह–मात के खेल का ही एक अंग है. इन प्राकृतिक आपदाओं ने नीतीश कुमार को नये सिरे से जनता के बीच गहरे तक जाने का एक मौका दिया है और वह इसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं. नीतीश ने बचाव–राहत कार्य का पूरा रोड–मैप खुद तैयार किया, अधिकारियों की शिविरों व अन्य स्थानों पर तैनाती की, मंत्रियों को जिलों में कैम्प करवाया और सारी कार्रवाई का पर्यवेक्षण खुद कर रहे हैं. जहां जैसी जरूरत होती है, वैसा वे करते हैं और खुद मुस्तैद रहते हैं. एक वाक्य में वह सब जगह मुस्तैद रहते हैं, दिखते हैं. बिहार विधानसभा चुनाव में अब छह महीने का समय भी नहीं बचा है. इन आपदाओं की छाया–बचाव, राहत कार्य, सहयोग व असहयोग आदि का उस चुनाव पर असर पड़ना तय है. भला ऐसे अवसर को कोई कैसे हाथ से जाने देगा और उसमें भी भाजपा जैसी पार्टी, जो सत्ता हासिल करने को बेकरार बैठी है. इसलिए सूबे में सबसे अधिक संकट के दौर में जनता के बीच नीतीश कुमार का इस तरह सशरीर बना रहना भाजाप को कैसे गंवारा हो सकता है. लिहाजा, भाजपा और उसके नेता नरेन्द्र मोदी के लिए अपने सद्भावपूर्ण रुख का प्रदर्शन जरूरी हो गया. भाजपा ने भी इसे नीतीश कुमार की तरह बिहार की जनता के बीच जाने के एक अतिरिक्त और महत्वपूर्ण अवसर के तौर पर लिया और सक्रिय हो गई. वह और उसके नेता नरेन्द्र मोदी नीतीश कुमार को ऐसा कोई भी अवसर फिलहाल नहीं देना चाहते, जिससे राजनीतिक तौर पर उन्हें (केन्द्र की भाजपा सरकार को) बिहार के विरोधी के तौर चिह्नित किया जा सके.

केन्द्र सरकार ने हर संकट के नाम पर बिहार को हरसंभव मदद का वायदा किया है. वह चाहे बेमौसम बरसात से पीड़ित किसानों को फसल क्षति का मुआवजा हो या आंधी व ओलावृष्टि से पीड़ित आबादी को राहत देने का मामला हो या भूकम्प पीड़ितों को सहायता का. केन्द्र हर बार मंत्रियों की टीम बिहार भेजता रहा है और उस टीम में शामिल मंत्री व उसके नेता बिहार के साथ खड़े रहने व उसे हरसंभव मदद का मुक्त–कंठ से वायदा करते रहे हैं, लेकिन पिछले कई हफ्तों से जारी इस कदमताल से बिहार को कैसे और क्या मिलना है, यह खुलासा कहीं से नहीं हो रहा है. इस मसले पर केन्द्रीय मंत्रियों की टीमें ही नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी खामोश हैं. बिहार सरकार के वरिष्ठ अधिकारी या भाजपा नेता भूकम्प का हवाला देकर खामोश हो जाते हैं. यह सही भी हो सकता है, पर राजनीति तो अपनी गति से आगे बढ़ती जाती है और वह भी चुनावी साल में. सत्ता जब दांव पर हो या कुर्सी जब मिलती हुई दिखे, तो राजनीति कहती है कि होठ को खुला नहीं रखना चाहिए, सबसे अच्छा चुप रहना है. केन्द्र राज्य की कदमताल और दोनों सत्ता केन्द्रों से जुड़े राजनेताओं–नौकरशाहों की चुप्पी कुछ कहती है. पर, क्या? राम जाने. ■

feedback@chauthiduniya.com

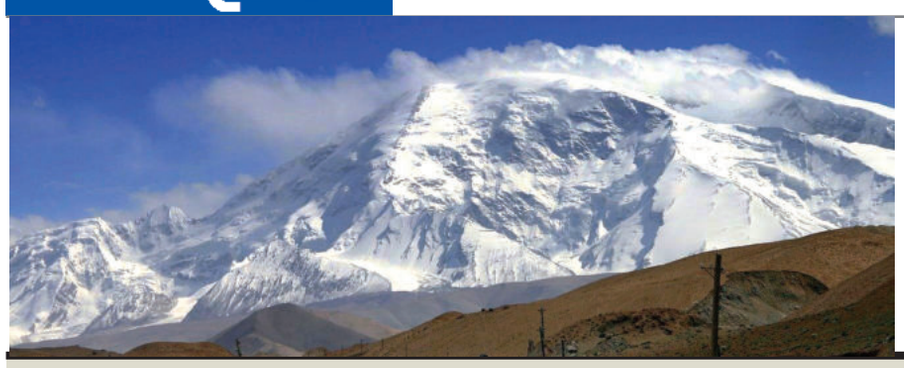

> नेपाल का भूकंप बहाना नहीं बनना चाहिए, लेकिन यह इस बात की गहराई से समीक्षा करने का ज़रिया ज़रूर बनना चाहिए कि चीन से नेपाल तक हिमालय को काटकर बनाए गए द फ्रेंडशिप हाईवे ने हिमालय को कितना नुक़सान पहुंचाया है? अब चीन से नेपाल तक बन रहे रेल मार्ग को लेकर हिमालय के अंदर जो सुरंग खोदे जाने की पूर्व भूमिका बनाई जा रही है, उसकी गतिविधियों से हिमालय कितना परेशान है? हिमालय के सीने पर बसा देश नेपाल, हिमालय के अंदर चल रही हरकतों से महफूज कैसे रह सकता है? नेपाल के भौगोलिक विशेषज्ञों का भी मानना है कि द फ्रेंडशिप हाईवे ने नेपाल का बहुत नुक़सान किया है.

हिमालय को अस्थिर करने पर तुला है चीन

प्रभात रंजन दीन

नेपाल और उत्तर भारत में आए जानलेवा भूकंप के कारणों में टेक्टॉनिक प्लेट्स के खिसकने और टकराने के चाहे जितने भौगोलिक-भूगर्भशास्त्रीय तर्क गढ़े जाएं, लेकिन हिमालय के स्थैर्य (स्थिरता) में लगातार व्यवधान डाल रहे चीन की हरकतों के बारे में भी पूरी दुनिया को विचार करना चाहिए. भारत को घेरने के लिए हिमालय को घेरना ज़रूरी है, इसीलिए चीन हिमालय को तीन तरफ़ से काट-काटकर उसकी चौहद्दी कम कर रहा है. और तो और, हिमालय के नीचे सुरंग खोदने तक के उपक्रम किए जा रहे हैं.

नेपाल का भूकंप बहाना नहीं बनना चाहिए, लेकिन यह इस बात की गहराई से समीक्षा करने का ज़रिया ज़रूर बनना चाहिए कि चीन से नेपाल तक हिमालय को काटकर बनाए गए द फ्रेंडशिप हाईवे ने हिमालय को कितना नुक़सान पहुंचाया है? अब चीन से नेपाल तक बन रहे रेल मार्ग को लेकर हिमालय के अंदर जो सुरंग खोदे जाने की पूर्व भूमिका बनाई जा रही है, उसकी गतिविधियों से हिमालय कितना परेशान है? हिमालय के सीने पर बसा देश नेपाल, हिमालय के अंदर चल रही हरकतों से महफूज कैसे रह सकता है? नेपाल के भौगोलिक विशेषज्ञों का भी मानना है कि द फ्रेंडशिप हाईवे ने नेपाल का बहुत नुक़सान किया है और प्रस्तावित रेल मार्ग तो नेपाल को नेस्तनाबूद कर देगा. वैसे भी, चीन भारत और अपने बीच किसी बफर-स्टेट का अस्तित्व नहीं चाहता. चीन और नेपाल के बीच बना द फ्रेंडशिप हाईवे तिब्बत के ल्हासा से हिमालय के बीच से होता हुआ झांगमू और नेपाल के कोडारी तक पहुंचता है.

बीच में चीन के शंघाई तक जाने वाली सड़क भी इससे कटती हुई जाती है. आप यहां ध्यान देते हुए चलें कि नेपाल के कोडारी इलाके में भूकंप के झटकों ने अत्यधिक तबाही मचाई है. सामरिक एवं रणनीतिक दृष्टि से बनाई गई यह सड़क हिमालय से भारत की तरफ़ बहने वाली सारी प्रमुख नदियों यथा गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, अरुण, कोशी, यहां तक कि हिमालय पर्वत शृंखला की पवित्र चोटी कैलाश, पवित्र मान सरोवर झील को छूती और काटती हुई चलती है. नेपाल के कोडारी तक आने वाली यह सड़क आगे भी अरनिको राजमार्ग के नाम से काठमांडू तक पहुंचती है. हिमालय को काट-काटकर बनाया गया यह हाईवे 5,476 किलोमीटर यानी 3,403 मील का रास्ता तय करता है.

भारत पर हमले के एक साल पहले यानी 1961 से ही चीन हिमालय के इस क्षेत्र को काटकर सड़क ले जाने की कोशिश कर रहा था. भारत-चीन युद्ध के एक साल बाद 1963 में चीन ने काठमांडू-कोडारी रोड बनाना शुरू कर दिया और 1967 में इसे आवागमन के लिए खोल भी दिया. बाद के वर्षों में इसके विस्तार पर लगातार काम होता रहा. आप इस बात पर भी हैरत करेंगे कि चीन जैसे चालाक देश ने नेपाल से लगी अपनी सीमा पर कहीं भी सुरक्षा चौकी नहीं रखी है. केवल कोडारी रोड पर चीन का एक चेक-पोस्ट बना है. अब इसी रूट पर चीन ल्हासा से खासा (नेपाल सीमा पर स्थित) और काठमांडू तक रेलवे लाइन के निर्माण पर काम कर रहा है. ख़ूबी यह है कि चीन और नेपाल को रेल मार्ग से जोड़ने वाले इस प्रोजेक्ट में नेपाल के एक भी श्रमिक को काम में शामिल नहीं किया गया है. चीन 2020 तक इसे पूरा कर लेना चाहता है. इस रेल मार्ग को हिमालय के अंदर-अंदर खुद रही कई लंबी-लंबी सुरंगों से होकर गुजरना है. इस रेल प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत के अलावा कई दूसरे संगठनों ने भी क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरनाक होने के साथ-साथ पर्यावरण को बेहद नुक़सान पहुंचाने वाला बताया है. इसके पहले ब्रह्मपुत्र नदी पर बांधों की शृंखला बनाए जाने की चीन की हरकतों पर भारत सरकार औपचारिक तौर पर आपत्तियां भी दर्ज कर चुकी हैं, लेकिन उन आपत्तियों से चीन की हरकतों पर कोई असर नहीं पड़ रहा.

भूगर्भशास्त्रियों का कहना है कि भारत और यूरेशियाई टेक्टॉनिक प्लेटों के खिसकने की दो वजहें होती हैं, एक तो प्राकृतिक रूप से आंतरिक ऊर्जा के कारण प्लेटों में खिसकाव होता रहता है और दूसरे बाह्य व्यवधान के कारण भी टेक्टॉनिक प्लेट्स में अतिरिक्त कंपन के कारण खिसकाव होता है. प्लेटों के खिसकने के कारण ऊपरी सतह पर भूकंप महसूस होता है. रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि हिमालय क्षेत्र में चीन ने अपनी रक्षा प्रणाली को पुख्ता करने के लिए पर्वतीय शृंखला को तहस-नहस करके रख दिया है, जिसके चलते हिमालय क्षेत्र में अंदरूनी अप्राकृतिक बाधाएं ज़्यादा आ रही हैं. नतीजतन हिम-स्खलन, भू-स्खलन और भूकंपन की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं. केदारनाथ त्रासदी के पीछे भी हिमालय क्षेत्र की अतिरिक्त (मानवीय) भौगर्भिक गतिविधियों को ही ज़िम्मेदार बताया गया था. विकास कार्यों के ज़रिये भारतीय पक्ष भी हिमालय को थोड़ा-बहुत अस्थिर कर रहा है और चीन तो उसे बिल्कुल ही वेध डालने पर आमादा है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा नहीं होती. जम्मू-कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कच्छ, बिहार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भूकंपन के सबसे ख़तरनाक जोन-5 में रखा गया है. इसके अलावा दिल्ली, सिक्किम, उत्तरी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात एवं महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा और राजस्थान का पश्चिमी तट आदि भूकंपीय ख़तरे के जोन-4 में शामिल हैं. इसमें उत्तर भारत को सर्वाधिक ख़तरा उत्तराखंड में बने टिहरी डैम से है. नेपाल में आया भूकंप रिक्टर स्केल पर 7.9 दर्ज किया गया है. टिहरी डैम के बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि रिक्टर स्केल पर 8.5 मैगनिट्यूड से अधिक का कंपन होने पर यह डैम टूट सकता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

...तो उत्तर भारत सैलाब में बह जाएगा

अगर टिहरी डैम टूटा, तो केवल उत्तराखंड ही क्या, पूरा उत्तर भारत ही पानी के अंदर होगा. टिहरी डैम मध्य हिमालय के सबसे सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र (सिसमिक जोन) में बना हुआ है. टिहरी डैम की डिज़ाइन कुछ इस तरह की बनी है कि यह रिक्टर स्केल पर 7.2 तक के झटके बर्दाश्त कर सकता है. हालांकि, डैम के निर्माण से जुड़े रहे इंजीनियरों का कहना है कि 8.5 के मैगनिट्यूड पर अगर भूकंप आया, तो टिहरी डैम ध्वस्त हो सकता है. और अगर ऐसा हुआ, तो उत्तर भारत का अधिकांश हिस्सा धुल जाएगा. भूकंप से भूस्खलन भी तेजी से होता है. अभी हाल ही केदारनाथ में जो आपदा आई थी, उसमें भी टिहरी को काफी ख़तरा था. बड़ा भूस्खलन भी टिहरी डैम को ध्वस्त कर सकता है. टिहरी डैम की दीवारों में पहले से ही कई स्थानों पर दरारें (फिसर्स) हैं, जिनसे रिसाव होता रहता है, जिसे रोकने के लिए रूस से विशेषज्ञों को बुलाना पड़ा. उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के भूकंप विज्ञानी (सिसमोलॉजिस्ट) डॉ. विनोद गौर ने टिहरी डैम की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े किए थे, लेकिन उनके सुझावों को पूरी तरह अनसुना करके टिहरी डैम का निर्माण किया गया. प्रोफेसर जेम्स ब्रूने ने भी टिहरी डैम को विश्व का सबसे असुरक्षित डैम बताया है. हालांकि, टिहरी डैम का निर्माण करने वाले प्रोजेक्ट इंजीनियरों ने प्रोफेसर ब्रूने के फॉर्मूले से मदद भी ली थी.

सतर्कता-सावधानी सबसे बड़ा बचाव

नेपाल में आए भीषण भूकंप ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया. वहां हज़ारों लोग काल के गाल में समा गए, बड़ी संख्या में लोग अभी भी लापता हैं. भारत में भी सैकड़ों लोग भूकंप से प्रभावित हुए. जब-जब हमने प्रकृति से छेड़छाड़ की, प्रकृति अपने रौद्र रूप में हमारे सामने उपस्थित हुई. अगर मानव जनित कारणों पर नज़र दौड़ाएं, तो हम पाएंगे कि हमने ख़ुद ही प्राकृतिक आपदाओं को आमंत्रित किया. भूकंप क्या, क्यों और कैसे, आइए डालते हैं एक नज़र...

राजीव रंजन

भूकंप अक्सर भूगर्भीय दोषों के कारण आते हैं. धरती या समुद्र के अंदर होने वाली विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के कारण भूकंप आते हैं. हमारी धरती चार परतों यानी इनर कोर, आउटर कोर, मैनटल और क्रस्ट से बनी हुई है. 50 किलोमीटर की यह मोटी परत विभिन्न वर्गों में बंटी हुई है, जिन्हें टैक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है. ये टैक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह से हिलती रहती हैं, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा हिलती हैं और इस क्रम में एक प्लेट दूसरी के नीचे आ जाती है, तो भूकंप आता है.

कैसे मापा जाता है भूकंप

भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर और मरकेली स्केल का पैमाना इस्तेमाल किया जाता है. भूकंप की तरंगों को रिक्टर स्केल 1 से 9 तक के आधार पर मापता है. इस स्केल के अंतर्गत प्रति स्केल भूकंप की तीव्रता 10 गुणा बढ़ जाती है और भूकंप के दौरान जो ऊर्जा निकलती है, वह प्रति स्केल 32 गुणा बढ़ जाती है. इसका सीधा मतलब यह हुआ कि 3 रिक्टर स्केल पर भूकंप की जो तीव्रता थी, वह 4 स्केल पर 10 गुणा बढ़ जाएगी. मरकेली स्केल में भूकंप को तीव्रता के बजाय ताकत के आधार पर मापते हैं.

भूकंप के कारण होने वाले नुक़सान के लिए कई कारण ज़िम्मेदार हो सकते हैं, जैसे घरों की खराब बनावट, खराब संरचना, भूमि की प्रकृति, आबादी की बसावट आदि.

भूकंप प्रभावित क्षेत्र

भारत को भूकंप के लिहाज से चार हिस्सों जोन-2, जोन-3, जोन-4 और जोन-5 में बांटा गया है. जोन-2 सबसे कम ख़तरे वाला तथा जोन-5 सर्वाधिक ख़तरनाक माना जाता है. उत्तर-पूर्व के सभी राज्य, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से जोन-5 में ही आते हैं. उत्तराखंड के कम ऊंचाई वाले हिस्सों से लेकर उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर हिस्से तथा दिल्ली जोन-4 में आते हैं. मध्य भारत अपेक्षाकृत कम ख़तरे वाले हिस्से जोन-3 में आता है, जबकि दक्षिण के ज़्यादातर हिस्से सीमित ख़तरे वाले जोन-2 में आते हैं.

भूकंप आने के दौरान क्या करें

- यदि आप किसी भवन के अंदर हैं, तो कुछ क़दम से अधिक न चलें. खुद को गिराएं, ढंकें और थामे रखें. कंपन थम जाने तक अंदर ही रहें और बाहर तभी निकलें, जब आप यह निश्चित कर लें कि अब ऐसा करना सुरक्षित है.
- यदि आप किसी एलिवेटर पर हैं, तो खुद को गिराएं, ढंकें और थामे रखें. कंपन थमने पर नज़दीकी फर्श पर जाने की कोशिश करें, यदि आप सुरक्षित रूप से ऐसा कर सकें.
- यदि आप बाहर हैं, तो इमारतों, पेड़ों, स्ट्रीट लाइटों और बिजली की लाइनों से कुछ क़दम से अधिक दूर न जाएं. फिर खुद को गिराएं, ढंकें और थामे रखें.
- यदि आप किसी बीच पर तट के निकट हैं, तो खुद को गिराएं, ढंकें और थामे रखें और फिर तत्काल ऊंची ज़मीन की ओर जाएं, यदि भूकंप के बाद सुनामी आ रही हो.
- यदि आप वाहन चला रहे हैं, तो किसी खुली जगह तक जाएं, रुकें और वहीं ठहरें तथा अपनी सीट बेल्ट तब तक कसे रखें, जब तक कि कंपन न थम जाएं. एक बार कंपन थम जाने पर सावधानीपूर्वक आगे बढ़ें और उन पुलों या ढलानों पर न जाएं, जो क्षतिग्रस्त हो चुके हों.
- यदि आप किसी पर्वतीय क्षेत्र में या अस्थिर ढलानों या खड़ी चट्टानों पर हैं, तो मलबा गिरने या भूस्खलन होने के प्रति सचेत रहें.

बचाव के उपाय

- भूकंपरोधी मकान का निर्माण कराएं.
- आपदा किट बनाएं, जिसमें रेडियो, मोबाइल, ज़रूरी कागजात, टार्च, माचिस, चप्पल, मोमबत्ती, कुछ पैसे और ज़रूरी दवाएं हों.
- भूकंप आने पर बिजली और गैस बंद कर दें.
- भूकंप अपने पर लिफ्ट का प्रयोग बिल्कुल न करें.
- भूकंप आने पर खुले स्थान पर जाएं. पेड़ों और बिजली की लाइनों से दूर रहें.

सबसे बड़े भूकंप

26 जनवरी, 2001 : गुजरात में 7.9 रिक्टर स्केल तीव्रता वाला शक्तिशाली भूकंप आया था, जिसमें 30 हज़ार लोग मारे गए.

17 अगस्त, 1999 : तुर्की की राजधानी इस्तांबुल और इमिट शहरों में 7.4 रिक्टर स्केल की तीव्रता का भूकंप आया था. 70,000 से अधिक लोग मारे गए और हज़ारों घायल हुए.

1990 : ईरान के गिलान में आए शक्तिशाली भूकंप ने 40,000 से भी अधिक लोगों की जान गई.

दिसंबर,1988: आर्मेनिया के उत्तर-पश्चिम में 6.9 रिक्टर स्केल की तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 25,000 लोगों की जानें गई थीं.

1923 : टोक्यो में ग्रेट कांटो नामक शक्तिशाली भूकंप आया था, जिसमें 1,42,800 लोगों की जानें चली गई थीं. ■

feedback@chauthiduniya.com

रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता और प्रभाव

0 से 1.9- सिर्फ़ सीज्मोग्राफ से ही पता चलता है.
2 से 2.9- हल्का कंपन.
3 से 3.9- कोई ट्रक आपके नज़दीक से गुज़र जाए, ऐसा असर.
4 से 4.9- खिड़कियां टूट सकती हैं, दीवारों पर टंगे फ्रेम गिर सकते हैं.
5 से 5.9- फर्नीचर हिल सकता है.
6 से 6.9- इमारतों की नींव दरक सकती है, ऊपरी मंजिलों को नुक़सान हो सकता है.
7 से 7.9- इमारतें गिर जाती हैं, ज़मीन के अंदर पाइप फट जाते हैं.
8 से 8.9- इमारतों सहित बड़े पुल भी गिर जाते हैं.
9 और उससे ज़्यादा- पूरी तबाही. यदि समुद्र नज़दीक हो, तो सुनामी आने की पूरी आशंका.

हर 87 सेकंड में हिलती है धरती

भूकंप एक सामान्य घटना है. एक अनुमान के अनुसार, विश्व में लगभग प्रत्येक 87 सेकंड में कहीं न कहीं धरती हल्के से कांपती है. इन झटकों को महसूस तो किया जा सकता है, लेकिन ये इतने शक्तिशाली नहीं होते कि इनसे किसी प्रकार की क्षति हो सके. प्रति वर्ष धरती पर औसतन 800 भूकंप ऐसे आते हैं, जिनसे कोई नुक़सान नहीं होता. इनके अतिरिक्त धरती पर प्रति वर्ष 18 बड़े भूकंप आने के साथ एक अति तीव्र भूकंप भी आता है.

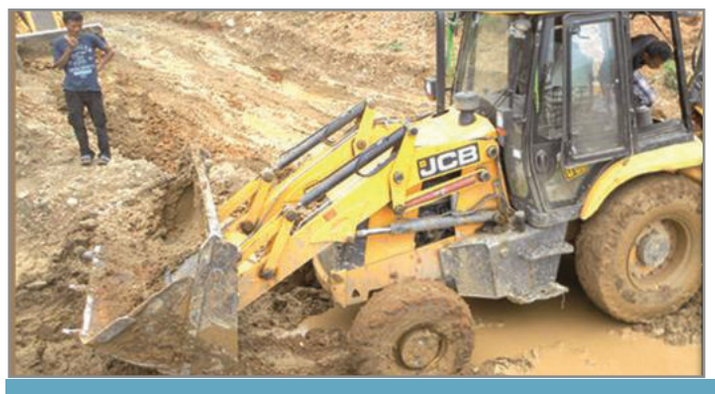

हैरानी की बात यह है कि प्रोजेक्ट शुरू होते ही इसकी लागत ढाई गुना बढ़ गई है. आईएल एंड एफएस और गायत्री प्रोजेक्ट्स पर आरोप है कि उन्होंने नगालैंड सरकार को 1,700 करोड़ रुपये की चपत लगाई. वर्ष 2010 में मेटास इंफ्रा और गायत्री प्रोजेक्ट्स को नगालैंड पीडब्ल्यूडी से 329 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का ठेका मिला था. मेटास इंफ्रा और गायत्री प्रोजेक्ट्स को 9 दिसंबर, 2010 को केंद्र की मंजूरी मिली थी. इसके बाद 3 फरवरी, 2011 को दोनों कंपनियों को पीडब्ल्यूडी नगालैंड ने ठेका दिया था. शर्त यह थी कि प्रोजेक्ट फरवरी 2014 तक पूरा हो जाना चाहिए. प्रोजेक्ट मिलने के नौ महीने के अंदर मेटास इंफ्रा का नाम बदल कर आईएल एंड एफएस इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड हो गया.

पश्चिम बंगाल निकाय चुनाव

ममता का जादू बरकरार

नवीन चौहान

अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमी-फाइनल समझे जा रहे पश्चिम बंगाल नगर निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने एक बार परचम लहरा दिया है. इस जीत से तृणमूल कांग्रेस ने अपने विरोधियों को संदेश दिया है कि राज्य की सत्ता से उसे बेदखल करना आसान नहीं है. ऐतिहासिक जीत के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि तृणमूल की जीत उन प्रतिद्वंद्वी ताकतों के लिए करारा जवाब है, जो उनकी और पार्टी की छवि खराब करने का अभियान चला रही हैं. लेकिन, वामदलों ने ममता बनर्जी के इस दावे को यह कहकर नकार दिया कि चुनावी नतीजे जनता की सही राय व्यक्त नहीं करते, क्योंकि इस चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली और हिंसा हुई है, मतदाताओं को मतदान करने से रोका गया है. वहीं ममता बनर्जी ने दावा किया कि राज्य में चुनाव पूरी तरह स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए. उन्होंने कहा कि मीडिया ने उनकी छवि बिगाड़ने का प्रयास करते हुए उन्हें और उनकी पार्टी को निशाना बनाया, उनके ऊपर व्यक्तिगत हमले किए गए. बकौल ममता, यदि ऐसा किसी अन्य राज्य में हुआ होता, तो उसका जाने क्या परिणाम होता.

कोलकाता नगर निगम सहित प्रदेश के 92 नगर निकायों के लिए हुए चुनाव में 71 पर तृणमूल कांग्रेस, पांच पर सीपीएम और चार पर कांग्रेस ने कब्जा किया, जबकि भाजपा एक भी नगर निकाय पर कब्जा नहीं कर सकी. 12 नगर निकायों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला. वर्ष 2010 में हुए निकाय चुनाव में तृणमूल ने 66 नगर निकायों पर कब्जा किया था. इसके बाद वह राज्य की सत्ता पर काबिज हुई थी. जबकि वामदल पिछली बार 25 नगर निकायों पर काबिज हुए थे, इस बार वे घटकर पांच के आंकड़े पर सिमट गए. कोलकाता नगर निगम (केएमसी) की 144 सीटों पर हुए चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 114 सीटों पर सफलता प्राप्त की. वहीं सीपीआई (एम) को 10, भाजपा को सात और कांग्रेस को पांच सीटों पर जीत हासिल हुई. तीन सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई. 2010 में कोलकाता नगर निगम के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को 95, सीपीआई (एम) को 33, कांग्रेस को आठ और भाजपा को तीन सीटों पर सफलता मिली थी. इस बार राज्य के कुल 2,090 वार्डों में से तृणमूल को 1425, वामदलों को 285, कांग्रेस को 186 और भाजपा को 85 में जीत हासिल हुई. कई नगर निकाय तो ऐसे हैं, जहां विपक्षी दलों का खाता भी नहीं खुल सका. तीन नगर पालिकाओं झालदा, जियागंज-अजीमगंज और बेलदंगा में तृणमूल कांग्रेस भी अपना खाता नहीं खोल सकी. हालांकि, वामदलों के लिए परिणाम निराशाजनक रहे, बावजूद इसके वे मुख्य विपक्षी पार्टी का तमगा हासिल करने में कामयाब रहे. वाममोर्चा को पांच निकायों सिलीगुड़ी नगर निगम, जंगीपुरा, दीनहाटा, ताहेरपुर और दाईहाट में बहुमत मिला. कांग्रेस को कालियागंज, इस्लामपुर, मुर्शिदाबाद और कांदी में बहुमत मिला. सिलीगुड़ी नगर निगम में सीपीआई (एम) ने 47 सीटों में से 23, तृणमूल ने 17, कांग्रेस ने पांच और भाजपा ने दो सीटों पर कब्जा किया, जबकि एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई.

चुनाव के बाद आए ज़्यादातर ओपिनियन पोल में तृणमूल को ही मजबूत दावेदार बताया गया था. इस ऐतिहासिक सफलता के बाद राज्य में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कद और बड़ा हो गया है. सारधा घोटाले की वजह से पार्टी की स्थिति चुनाव से पहले डांवाडोल लग रही थी और पूर्व महासचिव मुकुल रॉय जैसे कई बड़े नेता ममता बनर्जी से दूर हो गए थे. इसके अलावा पार्टी के कई नेताओं के नाम सारधा घोटाले में आने की वजह से तृणमूल कांग्रेस की साख को बहुत धक्का लगा था. ऐसे में ये निकाय चुनाव ममता बनर्जी के लिए व्यक्तिगत साख का सवाल बन गए थे. वहीं दूसरी तरफ़ सारधा घोटाले को लेकर भाजपा पश्चिम बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की पुरजोर कोशिश कर रही थी. अपनी वास्तविक स्थिति के आकलन के लिए उसके सामने निकाय चुनाव थे, लेकिन भाजपा एक भी नगर निकाय में बहुमत हासिल नहीं कर सकी. ऐसे निराशाजनक परिणाम से भाजपा को खासा झटका लगा है.

2014 में हुए लोकसभा चुनाव में राज्य की कुल 42 सीटों में से तृणमूल को 34, कांग्रेस को चार और भाजपा-सीपीआई (एम) को दो-दो सीटें हासिल हुई थीं. 42 लोकसभा क्षेत्रों में से 30 में भाजपा तीसरे और तीन में दूसरे स्थान पर रही थी तथा उसे राज्य में कुल 16.8 प्रतिशत वोट हासिल हुए थे. इसी तरह विधानसभा उपचुनाव में भी भाजपा ने बेहतर प्रदर्शन किया था. ऐसे में आशा की जा रही थी कि भाजपा विधानसभा चुनाव में राज्य में कमजोर होते वामदलों की जगह भरने में कामयाब होगी और वहां मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरेगी, लेकिन निकाय चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन भाजपा के सपनों पर कुठाराघात है. ताजा स्थिति ने भाजपा को विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति में आमूलचूल परिवर्तन करने को मजबूर कर दिया है. ग़ौरतलब है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पिछले दिनों पश्चिम बंगाल का दौरा करके पार्टी को मजबूत बनाने की पुरजोर कोशिश की थी, लेकिन उनकी सारी कवायद बेकार साबित हुई. राज्य के भाजपा कार्यकर्ता इस बात के लिए अपनी पीठ थपथपा सकते हैं कि 2010 के निकाय चुनाव में पार्टी को पूरे पश्चिम बंगाल में केवल 10 वार्डों में जीत हासिल हुई थी, लेकिन इस बार यह आंकड़ा बढ़कर 85 तक जा पहुंचा है. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिन्हा ने कहा कि चुनावी नतीजों से हम संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन इस चुनाव में भाजपा गेनर है और बाकी सब लूजर. उन्होंने कहा कि कोलकाता नगर निगम में पहले हमारी सीटें तीन थीं, अब सात हैं और हम 50 सीटों पर दूसरे स्थान पर रहे. यदि चुनाव निष्पक्ष होते, तो भाजपा को इतनी सीटें मिलतीं कि तृणमूल अकेले बोर्ड का गठन न कर पाती.

हालांकि, नगर निकाय चुनाव का वास्ता शहरी क्षेत्रों से होता है, तो ऐसे में पूरे राज्य के परिप्रेक्ष्य में इससे केवल भविष्य की राजनीतिक स्थितियों का आकलन किया जा सकता है. चुनाव से पहले वामदलों के वरिष्ठ नेताओं को पार्टी के बेहतर प्रदर्शन की आशा थी, लेकिन पार्टी एक बार फिर औंधे मुंह गिर पड़ी. वामदलों की पकड़ पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में है, शहरी क्षेत्रों में उनकी पकड़ कमजोर हुई है. ऐसे में वामदलों को अपने अस्तित्व की लड़ाई ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी लड़नी होगी. पश्चिम बंगाल के मुसलमानों का रुझान ज़्यादातर तृणमूल कांग्रेस की तरफ़ है. ऐसे में सीपीआई (एम) को राज्य में दमदार वापसी के लिए अपनी नीतियों में आधारभूत बदलाव करने होंगे और इसकी ज़िम्मेदारी अब नवनियुक्त महासचिव सीताराम येचुरी के कंधों पर है. वह वामदलों की डूबती नैया कैसे पार लगाते हैं, यह देखने वाली बात होगी. अगले विधानसभा चुनाव से पहले हुए निकाय चुनाव को सभी राजनीतिक दलों के लिए शक्ति परीक्षण का एक अहम मौक़ा माना जा रहा था. नतीजों से लोगों का तृणमूल कांग्रेस के प्रति विश्वास एक बार फिर जाहिर हुआ है. ममता बनर्जी ने कहा कि विपक्ष के तमाम कुप्रचार के बावजूद राज्य की जनता ने तृणमूल कांग्रेस पर भरोसा जताया. कुल मिलाकर चुनाव परिणाम बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का हरा रंग फिलहाल फीका पड़ता नहीं दिखाई देता और ममता बनर्जी का जादू अब भी बरकरार है. ■

navinonline@gmail.com

नगालैंड सड़क घोटाला

ऐसे होगा पूर्वोत्तर का विकास!

एस. बिजेन सिंह

पूर्वोत्तर के राज्य और वहां के लोग खुद को अलग-थलग पाते हैं. पूर्वोत्तर को विकास और देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास जारी हैं. लेकिन, शहरों और दिलों को जोड़ने का काम करने वाली सड़क के निर्माण में घोटाला किए जाने का मामला प्रकाश में आने से पूर्वोत्तर के लोगों को खासा झटका लगा है. नगालैंड के चार ज़िले एक-दूसरे से कटे हुए हैं. वहां के लोगों को दूसरे ज़िले में जाने के लिए दुर्गम पहाड़ों को पार करना पड़ता है. एनएच-39, जिसे वहां की लाइफ लाइन माना जाता है, का निर्माण कार्य कई वर्ष पहले शुरू हुआ था, जो आज तक जारी है. बरसात के मौसम में भू-स्खलन होने की वजह से आवागमन ठप हो जाता है. खाद्य सामग्री, एलपीजी, पेट्रोल-डीजल और दवाओं की आपूर्ति बाधित हो जाती है. इसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. मीडिया में भी इन समस्याओं की ख़बरें न के बराबर आती हैं. नगालैंड के इन ज़िलों में पेयजल के लिए लोग झरनों पर निर्भर रहते हैं. महिलाओं को पानी लाने के लिए दुर्गम पहाड़ों पर मीलों दूर जाना पड़ता है.

ऐसे में इन क्षेत्रों में सड़कों का महत्व भलीभांति समझा जा सकता है. लेकिन, यदि सड़क निर्माण कार्य में सैकड़ों करोड़ रुपये का घोटाला हो जाए, तो फिर क्या होगा? फिर कैसे विकसित भारत का सपना पूरा होगा? कैसे हम सुदूर पूर्वोत्तर को देश की मुख्य धारा से जोड़ सकेंगे? मामला नगालैंड का है, जहां लोंगलैंग- चांगटोंज़ा, मोन-तामलू-मेरांगकोंग, फेक-फूटजेरो और जूनहेबटो-चाकाबामा को एक-दूसरे से जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण कार्य में 1,700 करोड़ रुपये का घोटाला किए जाने का मामला प्रकाश में आया है.

उक्त पूरी धनराशि सरकारी खजाने से निकल गई, लेकिन निर्माण कार्य आज तक पूरा नहीं हो सका. ग़ौरतलब है कि यह प्रोजेक्ट चार अलग-अलग सेक्टरों का था, जिसे बाद में जोड़कर एक कर दिया गया. 329 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के निर्माण का ठेका मेटास इंफ्रा, जो आईएल एंड एफएस इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के नाम से जानी जाती है, को दिया गया था. मालूम हो कि मेटास इंफ्रा सत्यम घोटाले से जुड़ी कंपनी है. आईएल एंड एफएस कंपनी गायत्री प्रोजेक्ट्स के साथ 62 और 38 फ़ीसद हिस्सेदारी के साथ ज्वॉइंट वेंचर के तौर पर काम करती है.

हैरानी की बात यह है कि प्रोजेक्ट शुरू होते ही इसकी लागत ढाई गुना बढ़ गई है. आईएल एंड एफएस और गायत्री प्रोजेक्ट्स पर आरोप है कि उन्होंने नगालैंड सरकार को 1,700 करोड़ रुपये की चपत लगाई. वर्ष 2010 में मेटास इंफ्रा और गायत्री प्रोजेक्ट्स को नगालैंड पीडब्ल्यूडी से 329 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का ठेका मिला था. मेटास इंफ्रा और गायत्री प्रोजेक्ट्स को 9 दिसंबर, 2010 को केंद्र की मंजूरी मिली थी. इसके बाद 3 फरवरी, 2011 को दोनों कंपनियों को पीडब्ल्यूडी नगालैंड ने ठेका दिया था. शर्त यह थी कि प्रोजेक्ट फरवरी 2014 तक पूरा हो जाना चाहिए. प्रोजेक्ट मिलने के नौ महीने के अंदर मेटास इंफ्रा का नाम बदल कर आईएल एंड एफएस इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड हो गया. इस प्रोजेक्ट के प्रमोटर रामालिंगम राजू को हाल में सत्यम घोटाले में सात साल की सजा हुई है. प्रोजेक्ट शुरू होने के साल भर के अंदर आईएल एंड एफएस ने इसकी लागत रिवाइज्ड करके ढाई गुना बढ़ा दी. जानकारों के अनुसार, यह प्रोजेक्ट 1,296 करोड़ रुपये में पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन इसकी लागत बढ़ाकर 2,978 करोड़ रुपये कर दी गई.

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस निर्माणाधीन सड़क की लंबाई पहले 329 किलोमीटर तय की गई थी, जिसे बाद में घटाकर 313 किलोमीटर कर दिया गया. सवाल यह है कि जब निर्माणाधीन सड़क की लंबाई 16 किलोमीटर कम हो गई, तो लागत क्यों नहीं घटी? हैरानी की बात तो यही है कि लागत घटने के बजाय ढाई गुना बढ़ गई. इस प्रोजेक्ट की कॉन्ट्रैक्ट डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट नगालैंड के पीडब्ल्यूडी ने तैयार की थी और इसके बाद प्रस्ताव केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को भेजा गया, क्योंकि हाईवे प्रोजेक्ट की फंडिंग केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ही करता है, जबकि राज्य सरकारें वर्क कॉन्ट्रैक्ट देने का काम करती हैं. सूत्रों के अनुसार, आईएल एंड एफएस ने कम से कम 1,682 करोड़ रुपये से ज़्यादा रकम झटकने की योजना बनाई थी. यह योजना तब बनाई गई, जब सड़क की लंबाई 329 किलोमीटर तय की गई थी, जबकि बाद में सड़क की लंबाई घटाकर 313 किलोमीटर कर दी गई.

आईएल एंड एफएस ने सफ़ाई पेश की है कि लागत में इजाफ़ा ज़रूर हुआ है, लेकिन इसके पीछे ज़मीन की खुदाई में आने वाला खर्च है. कंपनी का कहना है कि डीपीआर (Detailed Project Report) में खामी थी और उसने निर्माण लागत बढ़ने की जानकारी पीडब्ल्यूडी-नगालैंड को दे दी थी तथा 2011 में नगालैंड सरकार को भी इस बारे में अवगत करा दिया था. सवाल यह है कि जब कंपनी को पता था कि उसे कितनी लंबी और कहां तक सड़क बनानी है, तो फिर क्या उसे यह पता नहीं था कि सड़क बनाने के लिए कितनी खुदाई करनी पड़ेगी और उस पर कितना खर्च आएगा? और, अगर डीपीआर में खामी थी, तो उसने यह मामला प्री-बिड मीटिंग में क्यों नहीं उठाया? राज्य सरकार को नौ माह बाद जानकारी क्यों दी गई? कंपनी द्वारा पेश की गई सफ़ाई कहीं से गले नहीं उतरती.

इस सड़क घोटाले से केंद्र सरकार हैरान है और वह इसकी जांच सीबीआई से कराने पर विचार कर रही है. जांच का बिंदु संभवत: यह होगा कि जब चारों ज़िलों के लिए अलग-अलग प्रोजेक्ट थे, तो उन्हें मिलाकर एक क्यों कर दिया गया? सूत्रों के मुताबिक, यह प्रोजेक्ट निरस्त होगा और फिर इसे नए सिरे से बनाया जाएगा. मजे की बात है कि जब रिवाइज्ड कॉस्ट पर सवाल उठे, तो सड़क परिवहन मंत्रालय ने कंसल्टेंसी कंपनी राइट्स को चार करोड़ रुपये बतौर शुल्क देकर प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन जांचने का ज़िम्मा सौंपा. राइट्स ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में रिवाइज्ड कॉस्ट पहले से 15 करोड़ रुपये ज़्यादा बताई. इस रिपोर्ट के बाद राइट्स की भी मंशा सामने आ गई. राइट्स की रिपोर्ट संगठित भ्रष्टाचार का जीता-जागता उदाहरण है. ■

sbijensngh@gmail.com

कमज़ोर पड़ता रमन राज

रमन सिंह को करीब से जानने वाले लोगों की माने तो मुख्यमंत्री इतने कमज़ोर कभी नहीं दिखे. आज आलम यह है कि हर पंद्रह दिन के बाद राजनीतिक गलियारों में उनके मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की सुबबुगाहट तेज हो जाती है. सरकार बनने के बाद रमन सिंह के साथ उनका लक नहीं है. तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद एक के बाद एक परेशानियां उनका पीछा कर रही हैं. एक छोड़ती हैं, तो दूसरी आ खड़ी होती है. दूसरी खत्म होती है, तो तीसरी. रमन सिंह मौजूदा वक्त में बुरी तरह से घिरे हुए हैं. जनता नाराज़ है. मीडिया, विपक्ष और सत्ता पक्ष के कई नेताओं के चक्रव्यूह में रमन सिंह घिरे दिखते हैं. हालांकि चुनाव में अभी साढ़े तीन साल बाकी हैं, लेकिन इन चक्रव्यूह से रमन सिंह कैसे निकलते हैं, ये बात देखने वाली होगी.

सुषमा गुप्ता

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को किस्मत का धनी माना जाता है. कहा जाता है कि दिलीप सिंह जूदेव, नंदकुमार साय, रमेश बैस और बृजमोहन जैसे दिग्गज नेताओं के रहते 2003 में मुख्यमंत्री का ताज उन्हें इसी किस्मत ने दिलाया था. जिस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हमेशा अपराजेय रही, वहां रमन सरकार के हैट्रिक बनने में जितनी भूमिका रमन सिंह के काम का था, उतनी ही उनके किस्मत की भी रही. इसे किस्मत नहीं तो और क्या कहा जाएगा कि गैर चुनावी सालों में जो कांग्रेस जोरदार तरीके से अपनी मौजूदगी दर्ज कराती है, वो चुनाव के समय सत्ता के नजदीक आकर फुस्स हो जाती है. कभी गुटबाज़ी के चलते तो कभी दरभा में नेताओं को गंवाने की वजह से कांग्रेस सत्ता से दूर ही रही, लेकिन बेहद मामूली बढ़त के साथ तीसरी बार सत्ता में आए रमन सिंह का गुडलक अब उनके साथ नहीं दिखता है.

रमन सिंह को करीब से जानने वाले लोगों की माने तो मुख्यमंत्री इतने कमज़ोर कभी नहीं दिखे. आज आलम यह है कि हर पंद्रह दिन के बाद राजनीतिक गलियारों में उनके मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की सुबबुगाहट तेज हो जाती है. सरकार बनने के बाद रमन सिंह के साथ उनका लक नहीं है. तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद एक के बाद एक परेशानियां उनका पीछा कर रही हैं. एक छोड़ती हैं, तो दूसरी आ खड़ी होती है. दूसरी खत्म होती है, तो तीसरी. रमन सिंह मौजूदा वक्त में बुरी तरह से घिरे हुए हैं. जनता नाराज़ है. मीडिया, विपक्ष और सत्ता पक्ष के कई नेताओं के चक्रव्यूह में रमन सिंह घिरे दिखते हैं. हालांकि चुनाव में अभी साढ़े तीन साल बाकी हैं, लेकिन इन चक्रव्यूह से रमन सिंह कैसे निकलते हैं, ये बात देखने वाली होगी.

सबसे पहले चर्चा करते हैं उन फैसलों की, जिसकी वजह से जनता के बीच में रमन सिंह सरकार की साख घटी है. रमन के मुश्किलों की शुरुआत लोकसभा चुनाव के बाद शुरू हुई, जब केंद्र में उन्हीं की पार्टी की सरकार बनी, लेकिन अपनी ही पार्टी की सरकार में रमन सिंह की मुश्किलें बढ़ती चली गईं. केंद्र सरकार ने चावल खरीद, बोनस और सब्सिडी पर कड़ा रुख अख्तियार किया और राज्य को मिलने वाली राशि में भारी कटौती कर दी, जिसके चलते मनरेगा, पीडीएस सिस्टम और धान खरीदी और किसानों को बोनस जैसी योजनाओं में राज्य पिछड़ता गया.

राज्य में बीजेपी की सरकार इस वादे के साथ आई थी कि वो सत्ता में आने के बाद धान का समर्थन मूल्य 21 सौ रुपये करने की पहल करेगी. सत्ता में आते ही उसने सबसे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को एक खत लिखकर पहल की भी, लेकिन जैसे ही केंद्र में मोदी की सरकार आई, ये पहल वहीं खत्म हो गई. रमन सिंह इस मसले पर घिर गए. चर्चाओं के मुताबिक, पहली कुछ मुलाकातों में ही केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री ने मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को इस बात से अवगत करा दिया कि जिन राज्यों में बोनस बांटा जाएगा, वहां एफसीआई धान की खरीदी नहीं करेगी. इसका असर हुआ कि बोनस के मुद्दे पर रमन सिंह की सरकार ने एक बार सांस तक नहीं लिया.

केंद्र से राज्य को मिलने वाली राशि में भारी कटौती के चलते सरकार को धान खरीदी में सीलिंग लगानी पड़ी. सरकार ने इस साल धान खरीदी की एक सीमा तय कर दी. प्रति एकड़ दस क्विंटल धान. फैसले का पूरे प्रदेश में जमकर विरोध भी हुआ. मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के साथ किसानों ने जगह-जगह इस फैसले के विरोध में सड़क पर उतरे. चक्का जाम से लेकर किसान संसद लगी. सरकार को झुकना पड़ा और खरीद की सीमा दस क्विंटल से बढ़ाकर 15 क्विंटल प्रति एकड़ करनी पड़ी, लेकिन विरोध नहीं रुका. सरकार के इस फैसले से जिन किसानों को बोनस की उम्मीद थी, वो उम्मीद सरकार के रुख से ही टूट गई. गांव में रहने वाली गरीब जनता मनरेगा को लेकर भी मुश्किल में रही. केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में राज्य

सरकार के खिलाफ सबसे मुखर आवाज़ बिलासपुर में हुए नसबंदी कांड पर उठी. इस घटना में 13 महिलाओं की मौत हुई थी. एक के बाद एक मौतें हो रही थीं, तब स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल मरहम लगाने की बजाय चैनलों पर मुस्कुरा-मुस्कुरा कर बातें कर रहे थे. अमर अग्रवाल के कार्यकाल में प्रदेश में इसी तरह के स्वास्थ्य शिविरों में महिलाओं के गर्भाशय निकाल लिए गए थे. मोतियाबिंद के ऑपरेशनों में लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन तमाम घटनाओं के मुद्दे पर सरकार ने दोषियों से निपटने में न तो सख्ती दिखाई और न ही अपनी व्यवस्था सुधारी.

की प्रस्तावित योजना राशि में करीब 1 हजार करोड़ रुपये से अधिक की कटौती कर दी. राज्य सरकार ने मनरेगा के लिए 27 सौ करोड़ रुपये की मांग की थी, लेकिन केंद्र ने सिर्फ 16 सौ करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं. इससे मनरेगा का काम पिछड़ गया और जब ये पैसे आए, तो कई जगह मज़दूर दूसरे प्रदेशों में मजदूरी के लिए पलायन कर चुके थे.

रमन सिंह ने एक और अप्रिय निर्णय लिया, वह था राशन कार्ड का सत्यापन. विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार ने करीब 70 लाख राशन कार्ड बनवाए थे. बीजेपी ये मानती है कि विधानसभा चुनाव के परिणाम उनके पक्ष में आने की बड़ी वजह ये राशन कार्ड ही थे, लेकिन नई सरकार बनते ही इसका हिसाब-किताब होने लगा कि कौन से कार्ड सही हैं और कौन से गलत. लाखों की संख्या में कार्ड से अनाजों का वितरण कुछ समय के लिए रोक दिया गया.

सरकार के खिलाफ सबसे मुखर आवाज़ बिलासपुर में हुए नसबंदी कांड पर उठी. इस घटना में 13 महिलाओं की मौत हुई थी. एक के बाद एक मौतें हो रही थीं, तब स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल मरहम लगाने की बजाय चैनलों पर मुस्कुरा-मुस्कुरा कर बातें कर रहे थे. अमर अग्रवाल के कार्यकाल में प्रदेश में इसी तरह के स्वास्थ्य शिविरों में महिलाओं के गर्भाशय निकाल लिए गए थे. मोतियाबिंद के ऑपरेशनों में लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन तमाम घटनाओं के मुद्दे पर सरकार ने दोषियों से निपटने में न तो सख्ती दिखाई और न ही अपनी व्यवस्था सुधारी. ऊपर से स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल के गैर जिम्मेदाराना रवैया और संवेदनहीनता ने लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया. इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री की जवाबदेही पर पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री रमन सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री ऑपरेशन नहीं करते हैं, कहकर मुसीबत मोल ले ली. अब तक राज्य में मीडिया उनकी छवि के अनुरूप मुख्यमंत्री पर सीधा हमला करने से बचता था, लेकिन उनके बेतुके बयान ने उन्हें भी सीधे निशाने पर ले लिया. मीडिया के सवालों से बचने के लिए स्वास्थ्य मंत्री अपना निर्वाचन क्षेत्र बिलासपुर छोड़कर कहीं और चले गए. कई दिनों तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया वहां डटा रहा और सरकार की उदासीनता की जमकर फजीहत हुई. सरकारी महकमों ने सच बताने की बजाय छिपाने की कोशिश की और मीडिया ने इस बात को भी जमकर दिखाया. चर्चा इस बात की भी है कि मीडिया देखने वाले लोगों ने खबरों को रुकवाने की कोशिश की थी, जिसके बाद मीडिया की नाराज़गी और बढ़ गई. राज्य में इस दौरान कई बार नक्सली हमले हुए. इन हमलों में मुख्यमंत्री का रटा-रटाया जवाब भी उनके खिलाफ गया. सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई चुटकुले वायरल हुए. मीडिया में भी सवाल उठे. पार्टी के अंदर और बाहर तमाम नेता ये आरोप लंबे समय से लगाते रहे हैं कि रमन सिंह का अधिकारियों पर कोई लगाम नहीं है. राज्य में तमाम बड़ी घटनाओं के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई न होने से ये आरोप साबित भी होते रहे हैं. इसका सबसे बुरा परिणाम

छत्तीसगढ़ के नागरिक आपूर्ति निगम यानी नान घोटाले में सामने आया. छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम यानी नान के दफ्तर में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए ढाई करोड़ से ज्यादा नकद राशि जब्त की. प्रदेश में पहली बार किसी सरकारी कार्यालय से ढाई करोड़ रुपये नकद जब्त किए गए. ये पैसे फील्ड के संग्रहण केंद्र से लेकर चावल की क्वालिटी, चावल की बोरी में मात्रा और बोरे की क्वालिटी में गड़बड़ी के एवज में लिए जाते हैं. इसे लेकर हुई प्रेस कांफ्रेंस में एडीजी मुकेश गुप्ता ने कहा कि इसमें एक डायरी भी बरामद हुई, जिसमें उन लोगों के नाम हैं, जिनको ये पैसे पहुंचते थे. डायरी की बात ही सरकार के गले की फांस बन गई. कांग्रेस और दूसरे सामाजिक संगठन डायरी को सार्वजनिक करने की मांग पर अड़ गई. जब इसे सार्वजनिक नहीं किया गया, तो कांग्रेस ने खुद दिल्ली जाकर इसके कुछ पन्ने सार्वजनिक कर दिए. इन पन्नों में बड़े अधिकारियों के साथ मंत्रियों और सीएम हाउस का जिक्र था. कई नाम कोड में थे. सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इसे लेकर राजनीतिक दांव-पेच चलते रहे. इसी बीच एक न्यूज़पेपर ने इस मामले में एक स्टिंग ऑडियो जारी कर दिया. दावा किया गया कि ये एक पत्रकार और मुख्य आरोपी शिवशंकर भट्ट की बातचीत का ऑडियो है. बातचीत में जो कोड कांग्रेस द्वारा जारी डायरी के पन्नों में लिखा है, उसकी डिकोडिंग है. इसमें खाद्य मंत्री पुन्नूलाल मोहले से लेकर सीएम के रसोइये और सीएम मैडम का जिक्र है, लेकिन बाद में खुद शिवशंकर भट्ट ने इस ऑडियो में अपनी बातचीत को खारिज कर दिया था और पत्रकार पर ब्लैकमेलिंग का आरोप जड़ दिया था. हालांकि उनके इंकार तक ये ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हो चुका था और सरकार की साफ छवि धूमिल हो चुकी थी.

इन तमाम मुद्दों को विपक्ष ने जमकर भुनाया. सदन हो या सड़क, उसने सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा. सरकार को सदन से लेकर सड़क में घेरा. भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के नेतृत्व ने यहां कांग्रेस के लगातार तीन चुनाव हारने के बाद भी हतोत्साहित होकर टूटने-बिखरने नहीं दिया और लगातार आंदोलन करते हुए कांग्रेस को चार्ज किए रहे, जिसका नतीजा है कि स्थानीय निकायों में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया और नगरीय निकाय चुनावों में बीजेपी पर जीत दर्ज की, लेकिन रमन सिंह के लिए मुश्किल कांग्रेस नहीं है, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी को अगले विधानसभा चुनाव से पहले नहीं हिला सकती. असली मुश्किल हैं पार्टी के अंदर के उनके विरोधी, जो रायपुर से लेकर दिल्ली तक सक्रिय हैं. राज्य में राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडेय के अलावा बृजमोहन अग्रवाल, रमेश बैस, प्रेम प्रकाश पांडेय दिल्ली में लगातार सक्रिय हैं. जब-जब उनकी सक्रियता बढ़ती है, सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट तेज़ हो जाती है. रमन के विरोधी खेमे के कई नेता दबी जुबान में रमन के बदलने की भविष्यवाणी करते रहते हैं. जब बीजेपी के वरिष्ठ सांसद रमेश बैस को केंद्रीय कैबिनेट में जगह नहीं मिली, तब ये चर्चा जोरों पर थी कि उन्हें रमन सिंह की जगह बिठाया जाएगा. दूसरी बार ये चर्चा तब छिड़ी, जब गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर को केंद्र बुलाया गया. उसके बाद नसबंदी कांड और नान घोटाले के समय भी ऐसी चर्चाओं को बल मिला. इन चर्चाओं के सिर्फ अफवाह न होने की बड़ी वजह है कि शिवराज सिंह और रमन सिंह अगर तीन बार अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे, तो भविष्य में आज के पीएम नरेंद्र मोदी को पीएम पद के लिए दावेदार बनकर चुनौती देंगे. लिहाज़ा, मोदी और शाह की जोड़ी दोनों को केंद्र में बुलाकर अपने मातहत रख सकते हैं. इन चर्चाओं को तब और बल मिला है, जब उनके विरोधी समझे जाने वाले नेताओं की सक्रियता दिल्ली में बढ़ गई. केंद्र में एनडीए की सरकार आने के बाद रमन विरोधी नेता अमूमन हर दो हफ्ते में किसी न किसी कारण दिल्ली घूम ही आते हैं. माना जाता है कि रमन सिंह को लोकप्रियता के गिरते ग्राफ के पीछे अफसरशाही का अराजक और मनमाना होना है. रमन सिंह पर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने अपने अधिकारियों को खुली छूट दे रखी है. वो उनके हर गुनाह माफ करते हैं. यह आरोप सिर्फ विपक्षी नेता नहीं, सरकार के मंत्री और विधायक तक लगाते हैं. अब ये बात मोटे तौर पर स्थापित सत्य बन चुकी है.

विपरीत परिस्थितियों में अफसरशाही रमन सिंह के लिए भारी पड़ रहा है. उनके अधिकारियों के प्रति नरम रुख को लेकर रमन सिंह पर विपक्ष के साथ-साथ उनकी पार्टी के लिए भी हमला कर रहे हैं. विपक्ष खुलकर कर रहा है, तो सहयोगी दबे-छिपे. चर्चा है कि सरकार के खिलाफ खबरों को मैनेज करने के लिए जिस तरीके से जनसंपर्क विभाग के कुछ अधिकारी दखल देने की कोशिश करते हैं, उससे मीडिया के एक बड़े तबके में असंतोष है. समय-समय पर यह असंतोष जाहिर भी होता है.

इस बार प्रदेश में लोक सुराज अभियान चलाया जा रहा है. इससे पहले तक ग्राम सुराज अभियान चलता था, जिसमें मंत्री और मुख्यमंत्री किसी नीयत जगह पर जाते थे और वहां लोगों की सुनते थे. जहां ये लोग जाते थे, वहां आसपास के गांव में मुनादी होती थी. दो-चार गांव के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन इस बार औचक दौरे बिना मुनादी के हो रहे हैं. पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी कहते हैं कि ऐसा सरकार ने विरोध से बचने के लिए किया है, क्योंकि पहले से मुनादी करने पर मंत्री और मुख्यमंत्री चावल का कोटा कम करने और धान खरीदी का समर्थन मूल्य न बढ़ाने की वजह से घिरेंगें. अभी रमन सिंह के कार्यकाल को साढ़े तीन साल और बचा है, लेकिन बड़ा दिलचस्प सवाल है कि वो अपना कार्यकाल पूरा करके मोदी का रिकॉर्ड तोड़ेंगें? ■

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

मीडिया अपनी आलोचना के लिए भी तैयार रहे

मैं समझता हूं कि मीडिया को अपने लिए कुछ मानक स्थापित करने चाहिए, जो उसकी नीति, उसके कंटेंट, तथ्यों और कार्यान्वयन से जुड़े होने चाहिए. किसी की शैक्षणिक योग्यता जैसी वजह से या अन्य छोटे मुद्दों के लिए सरकार का उपहास करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए. चाहे फिर स्मृति ईरानी हों या आप सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर. मैं नहीं समझता कि शैक्षिक योग्यता एक सांसद या मंत्री के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए प्रासंगिकता रखती है.

मौजूदा समय की सबसे बड़ी ख़बर नेपाल में आया भूकंप है. त्रासदी बहुत बड़ी है और मृतकों की संख्या का अभी तक अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन यह दस हज़ार से अधिक ही होगी. इस उप-महाद्वीप के लिए इससे बड़ी त्रासदी और क्या होगी? निकटतम पड़ोसी के रूप में भारत जो कुछ भी राहत सामग्री भेजने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए हर कोई आभारी है. ऐसी आपदा के मौक़े पर प्रभावित लोगों की मदद के लिए हर देश, हर संस्था, हर संगठन को आगे आना चाहिए. मैं आश्वस्त हूं कि नेपाल के लोग इस त्रासदी से उबरेंगे और एक बार फिर उठ खड़े होंगे, जैसा कि वे 80 साल पहले आया भूकंप झेल कर आगे बढ़े थे. हमें आशा करनी चाहिए कि आने वाले समय में नेपाल फिर से आगे बढ़ेगा.

राज्यसभा में स्वामी रामदेव द्वारा एक दवा की बिक्री, जिसके बारे में माना जाता है कि वह बेटा पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, पर सवाल उठा. इस दवा से बेटी की जगह बेटा पैदा होता है. यह हास्यास्पद और दु:खद है. देश में कई नीम हकीम काम कर रहे हैं, लेकिन बाबा रामदेव की स्थिति अलग है. वह सरकार के भरोसेमंद हैं, सरकार की गुडलिस्ट में हैं और वास्तव में भाजपा चुनाव के लिए उन पर निर्भर करती है. यह दु:खद होगा, यदि भारतीय जनता पार्टी ऐसी दवा का समर्थन करती है या ऐसी दवा की बिक्री पर चुप्पी साध लेती है. बाबा रामदेव ने साफ़ किया है कि यह दवा गर्भ धारण करने में अक्षम महिलाओं में निर्माण प्रक्रिया आरंभ करती है, बजाय पुरुष या महिला सेक्स का निर्धारण करने के. अब जो भी हो, हमारे देश में ऐसी चीजों के लिए कोई जगह नहीं हो सकती. जितनी जल्दी सरकार इस पर कार्रवाई करे, उतना ही बेहतर होगा.

एक अन्य विषय, जो थोड़ा हास्यास्पद है. अपने उत्साह में भारतीय जनता पार्टी सदस्य संख्या के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनना चाहती है. सदस्यों का दाखिला सुनिश्चित करने के लिए उसने कई फोन नंबर मुहैया कराए हैं, जिन पर मात्र मिस्ड कॉल करने से आप सदस्य बन जाएंगे. क्या इससे भी अधिक हास्यास्पद कुछ हो सकता है! एक मिस्ड कॉल के लिए पैसे की भी ज़रूरत नहीं है, तो कोई भी बिना सत्यापन के एक नंबर प्रेस कर सकता है. कल को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यह दावा कर सकती है कि पूरी चीनी आबादी उसकी सदस्य है. फिर तब तो भाजपा सबसे बड़ी पार्टी नहीं बन सकती. चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी रहेगी. भाजपा को लोकतंत्र का मज़ाक बनाना बंद कर देना चाहिए. ठीक है कि वह 282 सांसदों के साथ सत्ता में आ गई है, उसे अपना काम करना चाहिए और सबसे बड़ी पार्टी बनने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे वह फिर से सत्ता में आ सके. लेकिन, इसके लिए उसे ऐसा मज़ाकिया काम नहीं करना चाहिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा. उसे गंभीरता से घर-घर, मुहल्ले-मुहल्ले जा कर लोगों से मिलकर अपनी विचारधारा समझानी चाहिए और तब गंभीरता से सदस्यों की भर्ती करनी चाहिए. स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी ने ऐसा किया, लेकिन बाद में धीरे-धीरे यह सब कमज़ोर होता चला गया. अभी भाजपा सरकार में है. एक मौक़ा मिला है. उसे मेहनत से काम करना चाहिए, न कि ऐसी मिमिक्री की आवश्यकता है.

किसी कारण से मीडिया लगातार अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार के ख़िलाफ़ लगातार लिख रहा है. सरकार दो महीने से सत्ता में है. उसने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है, जिससे आलोचना हो, लेकिन फिर भी आलोचना हो रही है.

राज्यसभा में स्वामी रामदेव द्वारा एक दवा की बिक्री, जिसके बारे में माना जाता है कि वह बेटा पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, पर सवाल उठा. इस दवा से बेटी की जगह बेटा पैदा होता है. यह हास्यास्पद और दु:खद है. देश में कई नीम हकीम काम कर रहे हैं, लेकिन बाबा रामदेव की स्थिति अलग है. वह सरकार के भरोसेमंद हैं, सरकार की गुडलिस्ट में हैं और वास्तव में भाजपा चुनाव के लिए उन पर निर्भर करती है. यह दु:खद होगा, यदि भारतीय जनता पार्टी ऐसी दवा का समर्थन करती है या ऐसी दवा की बिक्री पर चुप्पी साध लेती है.

आलोचना के कारण क्या हैं, इसे समझना कठिन है, लेकिन अनुमान लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है. मीडिया केजरीवाल के ख़िलाफ़ उतर गया है. केजरीवाल ने कुछ नए प्रतिमान स्थापित करने की कोशिश की. जैसे, बैंक खाते के ज़रिये पैसा इकट्ठा करना, पारदर्शिता आदि. ऐसे में, बजाय उनकी ग़लतियां सुधारने के मीडिया उनका मज़ाक बना रहा है, उनकी आलोचना कर रहा है. इस तरह से मीडिया कांग्रेस और भाजपा के अपारदर्शी तरीकों को प्रोत्साहित कर रहा है. असल में, मीडिया को पारदर्शिता की बात करनी चाहिए और इसलिए यह आलोचना बिल्कुल सही है कि मीडिया खुद ही अपारदर्शी बन गया है. केंद्र सरकार के एक मंत्री ने मीडिया को प्रेस्टीट्यूट कहा, तो मीडिया बहुत गुस्सा हुआ. मीडिया आम आदमी पार्टी के सदस्यों को आपटार्ड कहता है. यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि यह शब्द कहां से आया है. अगर मीडिया इस तरह के शब्द का इस्तेमाल दूसरों के लिए करता है, तो उसे खुद भी ऐसे शब्दों के लिए तैयार रहना चाहिए.

मैं समझता हूं कि मीडिया को अपने लिए कुछ मानक स्थापित करने चाहिए, जो उसकी नीति, उसके कंटेंट, तथ्यों और कार्यान्वयन से जुड़े होने चाहिए. किसी की शैक्षणिक योग्यता जैसी वजह से या अन्य छोटे मुद्दों के लिए सरकार का उपहास करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए. चाहे फिर स्मृति ईरानी हों या आप सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर. मैं नहीं समझता कि शैक्षिक योग्यता एक सांसद या मंत्री के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए प्रासंगिकता रखती है. एक ग़रीब देश में शैक्षिक योग्यता एक पैमाना नहीं हो सकती, अन्यथा केवल अमीर लोगों का ही देश पर नियंत्रण रहेगा. फिर यह एक बनाना रिपब्लिक हो जाएगा. कई ग़रीब एवं अर्द्धशिक्षित लोगों ने बेहतर प्रदर्शन किया है. मीडिया को समझना चाहिए कि एक नेता के लिए क्या गुण हों, क्या योग्यता हो, एक नेता से आपको क्या चाहिए? क्या आप यह चाहते हैं कि सिर्फ़ डिग्रीधारी ही सांसद या मंत्री बनें? क्या आप भू-मालिकों या पूंजीपतियों को सांसद-मंत्री बनते देखना चाहते हैं?

हमारे देश के संस्थापकों ने तो ऐसा नहीं चाहा था. उन्होंने तो सिर्फ़ यह सोचा था कि लोगों को नैतिक एवं दिमागी रूप से स्वस्थ होना चाहिए, नीयत साफ़ होनी चाहिए और देश सेवा का जज्बा होना चाहिए. इसका मतलब था कि विधायिका, सरकार में शामिल होने के लिए दरवाजा हर किसी के लिए खुला हुआ है. यदि आप शिक्षित नहीं हैं, तो भी आप का स्वागत है. अब आप इस सबको बदलना चाहते हैं. गंभीर बहस की जगह मीडिया उन कुछ लोगों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा चला रहा है, जो किसी वजह से शैक्षणिक योग्यता हासिल नहीं कर सके. मैं यह याद नहीं दिलाना चाहता कि दुनिया में धर्मों की स्थापना करने वाले दुनिया के सबसे बड़े लोग कभी कॉलेज नहीं गए. न गुरु नानक, न वेद व्यास, न पैगंबर मुहम्मद और न हिंदू शास्त्रों को लिखने वाले लोग. तो क्या हुआ? इन लोगों ने ऐसा कुछ लिखा, जो सदियों से चला आ रहा है. शैक्षिक योग्यता प्रतिभा या सफलता निर्धारित करने वाला मापदंड नहीं हो सकती. इसे जितनी जल्दी हम समझ सकें, उतना ही अच्छा होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

एक औघड़ लीक से हटकर-3

साधक, सेवक और मार्गदर्शक

आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं, नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिता: नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती है कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह करना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं.

भगवान राम एक परमहंस की सलाह लेकर साधना की अगली कड़ी पूरी करने के लिए काशी चल पड़े. सावन बदी 8 (सन् 1951) की सुबह पंद्रह वर्ष की अवस्था में भगवान राम विश्वनाथ के दर्शन के लिए दशाश्वमेघ घाट पर खड़े थे कि एक वृद्धा आई और उसने उन्हें स्नान करने का आदेश दिया तथा बाद में ले जाकर भगवान विश्वनाथ के दर्शन कराए और फिर अन्नपूर्णा मंदिर ले गई. वहां अंदर जाकर वह गायब हो गई. आगे डेढ़सी के पुल पर वह वृद्धा फिर दिखाई दी, तो भगवान राम को आश्चर्य हुआ. उस महिला ने कहा, यहां से अस्सी की ओर जाओ. रास्ते में परमहंस साधकों का मठ है, वहीं तुम्हारा अभीष्ट सिद्ध होगा. भगवान राम हरिश्चंद्र घाट की ओर बढ़े. कुछ आगे जाने पर उन्हें क्रीं कुंड पर श्री किनाराम स्थल मिला. साढ़े सात बजे थे. बाबा रामेश्वर राम जी सो रहे थे. भगवान राम वहीं दालान में बैठ गए.

बाबा रामेश्वर राम जी से भेंट हुई. उन्होंने कुछ काम भगवान राम को सौंपे, जिन्हें संपन्न करने के पश्चात बाबा रामेश्वर राम ने उन्हें दीक्षा दी. इन्हीं दिनों सूर्योदय के समय हनुमान घाट पर आकंठ गंगा में खड़े रहकर भगवान राम ने मंत्र जाप किया. एक दिन वह धूनी के पास ही आश्रम में अर्द्धनिद्रित अवस्था में पड़े थे. उन्हें ऐसा भास हुआ कि किसी दिव्य पुरुष ने खड़ाऊं समेत अपने पैर उनकी छाती पर रख दिए और कुछ मंत्रोच्चार किया. भगवान राम ने आंतरिक प्रेरणावश वह मंत्र दोहराया और वह उन्हें याद हो गया. कुछ दिनों पश्चात बाबा किनाराम की समाधि पर भगवान राम झाड़ू लगा रहे थे कि उन्हें दक्षिण दिशा की ओर से स्पष्ट रूप से वही मंत्र फिर सुनाई दिया. साथ ही यह दिव्य आदेश मिला कि तुम इसी मंत्र का जाप किया करो. कुछ काल तक भगवान राम यहीं रहे. इसके बाद भगवान राम ने अज्ञात साधना की. इतना निश्चित है कि विंध्याचल में अष्टभुजा देवी के सानिध्य में कुछ दिनों तक भगवान राम ने कठोर साधना की.

बाबा ने सबसे महत्वपूर्ण काम 1962 में कुष्ठ सेवा आश्रम की स्थापना करके किया. जिस जगह उन्होंने कुष्ठ आश्रम बनाया, वहीं अपने रहने के लिए निवास स्थान भी चुना. इसके पूर्व बाबा का कहीं कोई स्थायी निवास नहीं था. बाबा का मानना है कि कोढ़ियों को समाज सबसे घृणा की दृष्टि से देखता है, अत: उनकी सेवा होनी चाहिए. इस समय केवल वाराणसी आश्रम में 60 शैय्याओं वाले अस्पताल का निर्माण हो गया है.

एकांत साधना पूरी होने के साथ ही भगवान राम को औघड़ पद की प्राप्ति हो गई. साथ ही उन्होंने तय किया कि अब मुझे लोकहित के काम करने चाहिए. महड़ौरा श्मशान में कुछ भक्तों को बाबा ने प्रथम दर्शन दिया. यहीं बाबा ने भक्तों के आग्रह पर विष्णु यज्ञ कराया. जब उसकी पूर्णाहुति हुई, तब सभी खर्च निकाल कर भी कुछ धनराशि बची हुई थी. बाबा की प्रेरणा से उससे गणेश मंदिर की स्थापना की गई. धीरे-धीरे वह स्थान अधिक प्रसिद्ध हो गया तथा वहां बड़ी भीड़ एकत्र होने लगी. इसलिए बाबा वहां से चल पड़े और हरिहरपुर गांव में तालाब के किनारे एक बेल वृक्ष के नीचे रहने लगे. गांव वालों का कहना था कि इस स्थान पर ब्रह्म-राक्षस रहता है. अत: वे दिन में भी इधर नहीं आते थे. यहां गांव वालों ने एक कुटिया बनवा दी. रात में अब भी किसी के जाने का निषेध था. यहां भी बाबा ने कठोर साधना प्रारंभ की. जेठ की दोपहरी में सूखे ताल में जाकर वह पड़े रहते थे. यहां रहकर कई कठिन यज्ञ भी बाबा द्वारा कराए गए.

औघड़ भगवान राम ने 21 सितंबर, 1961 को काशी में अपने भक्तों एवं साधकों के बीच सर्वेश्वरी समूह की स्थापना की. इसकी लगभग 80 शाखाएं देश के प्राय: हर भाग में स्थापित हो चुकी हैं. हर शाखा बच्चों की शिक्षा, जन्म-मरण तथा विवाह संस्कारों में रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध, सुगम विवाह पद्धति से बिना तिलक-दहेज के शादी कराना, विधवा विवाह कराने आदि के प्रयास कर रही है. हर शाखा गोष्ठियों का आयोजन करके कुरीतियों और धर्म के नाम पर चलने वाली कुपरंपराओं के विरुद्ध वातावरण बना रही है. छुआछूत, वर्ण व्यवस्था आदि के भेदभाव को दूर करने एवं सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बनाने हेतु समूह ने अपने संस्थापक औघड़ भगवान राम के निर्देशन में सहभोज, लंगर प्रथा, चक्रपूजन एवं सामूहिक पूजन की व्यवस्था की है. हर शाखा अपनी क्षमता के अनुकूल चिकित्सा व्यवस्था भी करती है.

बाबा ने सबसे महत्वपूर्ण काम 1962 में कुष्ठ सेवा आश्रम की स्थापना करके किया. जिस जगह उन्होंने कुष्ठ आश्रम बनाया, वहीं अपने रहने के लिए निवास स्थान भी चुना. इसके पूर्व बाबा का कहीं कोई स्थायी निवास नहीं था. बाबा का मानना है कि कोढ़ियों को समाज सबसे घृणा की दृष्टि से देखता है, अत: उनकी सेवा होनी चाहिए. इस समय केवल वाराणसी आश्रम में 60 शैय्याओं वाले अस्पताल का निर्माण हो गया है. महिला रोगियों के लिए 10 शैय्याओं का अलग कक्ष भी है. उनका इलाज आयुर्वेदिक पद्धति से होता है. आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि बाबा द्वारा बताई गई जड़ी-बूटियों का चमत्कारिक असर होता है. आश्रम में कुष्ठ पीड़ितों को खेती, गोशाला आदि की देखभाल स्वयं करनी होती है. अत: उनमें आत्मविश्वास जागृत होता है. बाबा कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी दिलवाते हैं.

बाबा के आश्रम में राजनीतिज्ञों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा वैज्ञानिकों का तांता लगा रहता है. सभी को ग़रीबों की भलाई में लगे रहने के लिए बाबा कहते रहते हैं. बाबा माला-कंठी या पूजा-पाठ को प्रोत्साहित नहीं करते. उनका मानना है कि यदि दुर्गा या काली की पूजा करनी है, तो जन को संगठित करना होगा, क्योंकि जनशक्ति ही दुर्गा और काली हैं. दुखियों के आंसू पोंछना तथा उनके हक़ की लड़ाई में खड़े रहना ही भगवती की पूजा है. बाबा के बारे में, उनकी सहृदयता के बारे में, उनकी भविष्यवाणियों के बारे में, उनके चमत्कारों के बारे में बहुत-से लोगों के पास बहुत-से अनुभव हैं. मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर, कर्ण सिंह, दिनेश सिंह, डॉ. सरोजनी महिषी, हनुमंतैया, बीपी कोइराला जैसे लोगों को जहां बाबा ने समय-समय पर सहायता पहुंचाई, वहीं यज्ञ नारायण चतुर्वेदी, सागर सिंह, कतवारू राम, केडी सिंह, देव कुमार चौबे, मोहन तिवारी, बुल्लार जी मिस्त्री, अघोरी कृष्णदेव, अघोरी सुरेंद्र नाथ, वैद्य शिवकुमार शास्त्री, सज्जन कुमार कनोडिया जैसे लोगों को भी रास्ता दिखाया है. बाबा के आश्रम की देखभाल में लगे युवक हरी जी ने कहा कि बाबा का सबसे बड़ा चमत्कार यदि कोई है, तो यही है कि इतनी बड़ी ताकतों को अपने अधिकार में रखने के बावजूद वह हमारे जैसे लोगों से बातें करते हैं, हमारी समस्याएं सुलझाते हैं तथा हमें अपना प्यार देते हैं.

क्रमश:

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

माननीयों, इतिहास आपको माफ़ नहीं करेगा

संसद अपने आप में लोकतंत्र का न केवल चेहरा है, बल्कि लोकतंत्र का पैमाना भी है और जिस तरह से हमारी संसद देश के हितों के प्रति असंवेदनशील हो गई है, उसे देखकर लगता है कि देश की चिंता से ज़्यादा सांसदों को अपनी चिंताएं हैं. हम उदाहरण के लिए भूमि अधिग्रहण बिल या किसानों की समस्याओं पर इन दिनों होने वाली बहसों को देख सकते हैं. संसद में कहीं यह चर्चा मजबूती के साथ नहीं हो रही है कि किसान क्यों अर्थव्यवस्था का अंग नहीं है? किसान को केंद्र में रखकर क्यों नीतियां नहीं बनाई जाती हैं?

संसद के सत्र में और सरकार के चलाने के तरीके को लेकर, खासकर सरकार के अंगों के भीतर उसकी साख को लेकर ऐसे चिन्ह नज़र आने लगे हैं, जो चिंताएं पैदा करते हैं. सबसे पहले हम लोकसभा और राज्यसभा को लेते हैं. आम तौर पर लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य सिर्फ़ और सिर्फ़ टेलीविजन के समाचारों पर ही निर्भर रहते हैं. उनके सारे सवाल या ज़्यादातर सवाल या ज़्यादातर भाषण टेलीविजन के समाचारों या टेलीविजन पर होने वाली बहसों के तर्कों से प्रभावित रहते हैं. उनका खुद का पढ़ना-लिखना या उनका खुद का समाचार-पत्रों को भी पढ़ना कितना सार्थक होता है, यह पता नहीं, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर होने वाली बहसों में या सवालों में इसकी झलक नहीं दिखाई देती.

पहले के नेताओं को याद करें, जो इन्हीं दोनों सदनों के सदस्य रहे हैं, तो उनके मुकाबले आज के दोनों सदनों के सदस्य काफी बौने नज़र आते हैं. एक संदेह पैदा हो रहा है कि राज्यसभा ऐसे लोगों का चेहरा ज़्यादा देख रही है, जिनका काम सिर्फ़ और सिर्फ़ मंत्रियों और सत्ता से मिलकर स्वयं से जुड़े निहित स्वार्थों की पूर्ति करना है. दूसरी तरफ़ लोकसभा में ऐसे लोग हैं, जिनका देश की समस्याओं से संबंध है ही नहीं, उनका अपने क्षेत्र की समस्याओं से भी संबंध नहीं है. हमें नहीं याद कि पिछले दस से पंद्रह वर्षों में किसी ऐसी बहस की शुरुआत किसी सांसद ने की हो, जिसका रिश्ता देश की समस्याओं से हो. शायद ये सांसद पुस्तकालय में जाकर मधु लिमये, नाथ पाई, अटल बिहारी वाजपेयी, भूपेश गुप्ता, राज नारायण, चंद्रशेखर जैसों के संसद में दिए भाषणों को पढ़ते भी हैं या नहीं पढ़ते. यह संदेह इसलिए पैदा होता है, क्योंकि हमारी संसद के दोनों सदनों के सदस्य देश की समस्याओं से सर्वथा विपरीत दिशा की तरफ़ सोचते हैं और बोलते भी हैं. उन्हें नहीं लगता कि संसद देश में समस्याओं की जड़ और समस्याओं की तलाश पर बहस करने की जगह है, न कि राजनीतिक पैंतरेबाजी की. अपना चेहरा भले काला हो, लेकिन दूसरे का चेहरा भी काला करो, इसकी जगह तो संसद नहीं है, पर संसद का इस्तेमाल ज़्यादातर इसी के लिए हो रहा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों देश के प्रशासनिक अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित किया. उनके संबोधन के बाद दोपहर के खाने पर जब उक्त अधिकारी मिले, तो जो अधिकारी जैसी भाषा जानता था, उस भाषा में उसने प्रधानमंत्री के कार्यकलापों की आलोचना की. मैंने इसे कम से कम चार अधिकारियों से चेक किया. और, चारों ने एक ही बात कही कि नौकरशाही में नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीके को लेकर गुस्सा भी है, असंतोष भी है. दरअसल, नरेंद्र मोदी ने यह तरीका अपनाया हुआ है कि वह राजनीतिक ज़िम्मेदारी देने की जगह प्रशासनिक अधिकारियों को टारगेट दे रहे हैं और उन्हें वे चीजें समझाते हैं, जिन्हें सुनना ये अधिकारी पसंद नहीं करते. इन अधिकारियों को लगता है कि अगर प्रशासन को उनके तरीके से नहीं चलाया गया, तो एक कयास, एक अंतर्विरोध पैदा हो जाएगा और जिसका परिणाम पॉलिसी पैरालाइज के रूप में निकलेगा. एक वरिष्ठ अधिकारी ने तो मुझसे कहा कि मनमोहन सिंह के समय जिस पॉलिसी पैरालाइज की बात होती थी, वह उस समय तो नज़र नहीं आता था, सिर्फ़ आरोप था, लेकिन आज पॉलिसी पैरालाइज दिखाई दे रहा है. मैं उस वरिष्ठ अधिकारी की बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि मुझे इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन उस वर्ग में, जिस पर पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने या प्रशासनिक दस्ते में, जिसके ऊपर नीतियों को लागू करने की ज़िम्मेदारी हो, जब यह भावना घर करने लगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सोचने का वक्त खड़ा हो जाता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों देश के प्रशासनिक अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित किया. उनके संबोधन के बाद दोपहर के खाने पर जब उक्त अधिकारी मिले, तो जो अधिकारी जैसी भाषा जानता था, उस भाषा में उसने प्रधानमंत्री के कार्यकलापों की आलोचना की. मैंने इसे कम से कम चार अधिकारियों से चेक किया. और, चारों ने एक ही बात कही कि नौकरशाही में नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीके को लेकर गुस्सा भी है, असंतोष भी है. दरअसल, नरेंद्र मोदी ने यह तरीका अपनाया हुआ है कि वह राजनीतिक ज़िम्मेदारी देने की जगह प्रशासनिक अधिकारियों को टारगेट दे रहे हैं और उन्हें वे चीजें समझाते हैं, जिन्हें सुनना ये अधिकारी पसंद नहीं करते. इन अधिकारियों को लगता है कि अगर प्रशासन को उनके तरीके से नहीं चलाया गया, तो एक कयास, एक अंतर्विरोध पैदा हो जाएगा और जिसका परिणाम पॉलिसी पैरालाइज के रूप में निकलेगा.

संसद अपने आप में लोकतंत्र का न केवल चेहरा है, बल्कि लोकतंत्र का पैमाना भी है और जिस तरह से हमारी संसद देश के हितों के प्रति असंवेदनशील हो गई है, उसे देखकर लगता है कि देश की चिंता से ज़्यादा सांसदों को अपनी चिंताएं हैं. हम उदाहरण के लिए भूमि अधिग्रहण बिल या किसानों की समस्याओं पर इन दिनों होने वाली बहसों को देख सकते हैं. संसद में कहीं यह चर्चा मजबूती के साथ नहीं हो रही है कि किसान क्यों अर्थव्यवस्था का अंग नहीं है? किसान को केंद्र में रखकर क्यों नीतियां नहीं बनाई जाती हैं? बल्कि, किसान को कैसे थोड़ी-सी सुविधाएं दे दी जाएं, ताकि वह अगले दो वर्षों के लिए चुप हो जाए, अपनी तकलीफों को भूल जाए, इस पर बात होती है. और, इस बात को लेकर किसी भी सांसद के मन में न कोई चिंता होती है, न गुस्सा आता है.

दरअसल, हमारे देश के केंद्र में किसान है ही नहीं. हालांकि, ज़्यादातर सांसद गांवों से आते हैं, जिनका रिश्ता खेती से है, पर उन्हें शायद किसानों की बात करना अपने स्तर के अनुकूल नहीं लगता. उन्हें लगता होगा कि वे अगर इस बात को उठाएंगे, तो लोग उन्हें प्रगतिशील नहीं समझेंगे और आज प्रगतिशीलता की निशानी बड़े-बड़े उद्योगों, बड़े-बड़े पूंजीपतियों, बड़े-बड़े सम्मान समारोहों में जाकर मौजूदा अर्थव्यवस्था के पक्ष में बोलना है. पर यह अर्थव्यवस्था किसानों के प्रति कितनी संवेदनशील है, इसकी बहस इस संसद में नहीं होती और मुझे लगता है, शायद भविष्य में होगी भी नहीं.

आख़िर में जो सबसे बड़ा दु:ख का सवाल है, वह यह है कि जब हम राज्यसभा और लोकसभा टीवी के ऊपर संसद में बैठी उपस्थिति को देखते हैं, तो हमें मुश्किल से दोपहर के बाद यानी एक बजे के बाद, जब सबसे महत्वपूर्ण विधेयक पेश होते हैं या सबसे महत्वपूर्ण चर्चाएं होती हैं, तो सिर्फ़ 20 या 25 सांसद, चाहे इस सदन में हों या उस सदन में, बैठे हुए नज़र आते हैं. लोकसभा और राज्यसभा के अधिकारियों ने टेलीविजन कैमरामैनों को यह हिदायत दे रखी है कि वे कभी भी वाइड एंगल से पूरी लोकसभा या पूरी राज्यसभा का चित्र न दिखाएं, जब तक बहुत आवश्यक न हो. उनके कैमरे का केंद्र सिर्फ़ वह व्यक्ति होना चाहिए, जो किसी भी सदन में भाषण दे रहा है, अपनी बात कह रहा है. परिणाम स्वरूप आप जब भी लोकसभा या राज्यसभा टेलीविजन देखेंगे, कैमरा आपको बाकी लोगों की तरफ़ नहीं दिखाएगा, क्योंकि बाकी सीटें खाली रहती हैं. कैमरा सिर्फ़ बोलने वाले व्यक्ति पर केंद्रित होता है. लोकसभा और राज्यसभा केवल सिर्फ़ शून्यकाल में भरी दिखाई देती हैं और शून्यकाल के बाद दोपहर का भोजनावकाश होता है, लंच होता है. उसके बाद लोग सदन में आने की जगह अपने घर जाना पसंद करते हैं.

क्या यह भारत जैसे समस्याओं से घिरे लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का प्रतिनिधितत्व करने वाली संसद है? बहस हो सकती है, पर मुझे यह कहने में कोई दिक्कत नहीं कि शायद ऐसा नहीं है. यह भावना सिर्फ़ मेरी नहीं है, यह भावना इस देश के अधिकांश वर्गों की है, जिनकी तकलीफों, जिनके दर्द और जिनके दु:ख का कोई बयान इस संसद में नहीं होता. हल तो कभी नहीं निकलता. क्या हमारे राजनीतिक दलों के लिए यह सोचने का विषय नहीं है कि क्यों उनके प्रति लोगों में अनादर बढ़ रहा है, क्यों उनकी बेरुखी बढ़ रही है और क्यों वे उनकी इज्जत नहीं करते, जिन्हें वोट देकर संसद में भेजते हैं?

मत सोचिए माननीय सांसदों, माननीय लोकसभा और माननीय राज्यसभा, मत सोचिए. कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता. लेकिन, इतिहास आपके ऊपर व्यंग्य से लिखेगा कि आप उस लोकतांत्रिक देश के प्रतिनिधि हैं, जिसे लोकतंत्र में पूरी आस्था नहीं है, सिर्फ़ आंशिक आस्था है. ■

editor@chauthiduniya.com

लोगों की ज़िंदगियों से मत खेलिए

उपेक्षा और विषम नीतियों के चलते बड़े किसानों को फ़ायदा हुआ. जैसे-जैसे उनकी उपज बढ़ी, वे राजनीतिक तौर पर भी मुखर होते गए. उन्हें रासायनिक खाद, बिजली एवं पानी पर सब्सिडी मिलती रही और वे मिट्टी की उर्वरता और ज़मीन का जल स्तर तबाह करते रहे. उसके बाद साल दर साल बढ़ने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य का भी लाभ उन्हें मिलता रहा. यह यूपीए-2 के समय में क़ीमतों में वृद्धि का एक बड़ा कारण था. बड़े किसान अधिक उपज लेने लगे. अब ऐसे किसानों की सब्सिडी धीरे-धीरे ख़त्म कर देनी चाहिए और छोटे किसानों को बेहतर सहूलियतें दी जानी चाहिए.

मेघनाद देसाई

भारत का संसदीय लोकतंत्र पिछले दिनों अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया. गजेंद्र सिंह नामक किसान ने एक पेड़ से लटक कर जान दे दी. उसकी लाश पेड़ से उतार कर आगे की कार्रवाई होती, उससे पहले ही उसे राजनीतिक फुटबॉल बनाकर राजनीतिक खींचा-तानी शुरू हो गई. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार कॉरपोरेट्स के प्रभाव में फ़ैसले ले रही है, रैली करना आम आदमी पार्टी का सबसे पसंदीदा शगल है, इसलिए गजेंद्र की आत्महत्या के बावजूद आप की रैली जारी रही. सरकार ने खेद प्रकट किया. दूसरे दिन दूसरा संकट, हंगामे के चलते संसद का एक और स्थगन, लेकिन ज़िंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही. भूमि अधिग्रहण विधेयक पर बहस, बेमौसम की बरसात और सूखे की भविष्यवाणी ने कई लोगों को भ्रमित कर दिया. सूखा और राहत कार्य एक तात्कालिक समस्या है, लेकिन भूमि अधिग्रहण दीर्घकालिक विकास की योजना पर आधारित एक रणनीति है. किसानों का संकट कोई नया संकट नहीं है.

किसानों की आत्महत्या आज से दस साल पहले एक बड़ी समस्या थी. यह समस्या जानी-बूझी है. खेती पर आश्रित किसान आम दिनों में भी आर्थिक तंगी की कगार पर खड़े रहते हैं. ऐसे किसानों को यदि एक वैकल्पिक रोज़गार मिलता है, तो वे इससे लाभांवित होंगे. यदि चीज़ें सही दिशा में बढ़ती हैं, तो छोटे किसानों को अतिरिक्त आमदनी का एक ज़रिया मिल जाएगा. छोटे किसान ऋण लेकर खेती करते हैं और फसल बेचकर ऋण अदा करते हैं. यदि फसल बर्बाद हो गई, तो उन्हें बहुत नुक़सान उठाना पड़ता है. गजेंद्र का मामला जिस बात को ज़ाहिर करता है, वह यह है कि अधिकारी केवल क़ानून का पालन करते हैं. फसल का 33 प्रतिशत से कम नुक़सान का मतलब है कि कोई मुआवज़ा नहीं. ऐसे क़ानून पर किसी को पुनर्विचार का ख्याल क्यों नहीं आया? मुझे मालूम है, अकबर ने ऐसे मामलों में अधिक उदारता दिखाई थी.

जब यूपीए-1 के दौरान आख़िरी बार आत्महत्या एक बड़ा मुद्दा थी, सारा ध्यान अत्यधिक ब्याज पर था. 45 साल पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की कमी दूर की जा सके, लेकिन उसके बावजूद आज भी वही समस्या बरक़रार है. अभी सियासी दांव-पेंच के बजाय किसानों के लिए सरकारी मापदंडों से कम खराब हुई फसल के लिए एक यूनिवर्सल फसल बीमा की आवश्यकता है. भारतीय कृषि के एक बड़े भाग में अत्यधिक कम उपज होती है. किसानों को बहुत ही कम आमदनी पर जीवनयापन करना पड़ता है, क्योंकि औद्योगिक विकास की धीमी गति उनकी आमदनी के लिए कोई विकल्प मुहैया कराने में असमर्थ रही. देश के 60 प्रतिशत लोग राष्ट्रीय आय में केवल 20 प्रतिशत के भागीदार हैं. जो ज़ाहिर करता है कि कृषि के कायाकल्प की ज़रूरत है.

हालांकि, राजनीतिक वाद-विवाद सांसदों का पसंदीदा काम है, लेकिन देश को इस मानवीय त्रासदी का हल चाहिए. ऐसा करने के लिए हर किसान से उसकी ज़मीन छीनने की आवश्यकता नहीं है, न देश के किसानों की होने वाली दु:खद आत्महत्या रेखंकित करने और बाद में उन्हें भूल जाने की. दस साल पहले कुछ जांच रिपोर्टें आई थीं, जिनमें योजना आयोग के सदस्य नरेंद्र जाधव की एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट शामिल थी. खेती का मौसम जाते ही उस रिपोर्ट को धूल खाने के लिए किसी आलमारी में रख दिया गया. एक बार फिर राजनेता किसानों की आत्महत्या को राजनीतिक फुटबॉल बना रहे हैं. कृषि में एक लंबे समय से सुधार की आवश्यकता है. आज़ादी के 45 वर्षों बाद तक सारी की सारी योजनाएं भारी उद्योगों के विकास पर केंद्रित थीं, अन्य सभी क्षेत्रों को नज़रअंदाज कर

दिया गया था. 1992 में जब डब्ल्यूटीओ के गठन पर बहस चल रही थी, ठीक उसी समय अशोक गुलाटी ने कहा था कि खाद्य आत्मनिर्भरता के बहाने भारतीय किसानों पर निगेटिव टैरिफ लगाया जाता रहा और इस दौरान उद्योगों को प्रशुल्क संरक्षण दिया जाता रहा, जिसकी वजह से आज उद्योग बदहाल हैं.

उपेक्षा और विषम नीतियों के चलते बड़े किसानों को फ़ायदा हुआ. जैसे-जैसे उनकी उपज बढ़ी, वे राजनीतिक तौर पर भी मुखर होते गए. उन्हें रासायनिक खाद, बिजली एवं पानी पर सब्सिडी मिलती रही और वे मिट्टी की उर्वरता और ज़मीन का जल स्तर तबाह करते रहे. उसके बाद साल दर साल बढ़ने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य का भी लाभ उन्हें मिलता रहा. यह यूपीए-2 के समय में क़ीमतों में वृद्धि का एक बड़ा कारण था. बड़े किसान अधिक उपज लेने लगे. अब ऐसे किसानों की सब्सिडी धीरे-धीरे ख़त्म कर देनी चाहिए और छोटे किसानों को बेहतर सहूलियतें दी जानी चाहिए. यही वजह है कि भूमि अधिग्रहण ज़रूरी है. भारत को छोटे किसानों, लेकिन एक मज़बूत कृषि की ज़रूरत है. खेतिहर मज़दूरों एवं छोटे किसानों को उद्योगों में रोज़गार देने की ज़रूरत है. इसका कॉरपोरेट हित से कोई संबंध नहीं है. ग़रीबों को ग़रीब रखने की कोई वजह नहीं है, जैसा कांग्रेस रखना चाहती है. ग़रीबों को उद्योगों एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में नौकरी की ज़रूरत है. और, इसका समाधान भूमि अधिग्रहण विधेयक में हो सकता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

> गर्मी में विटामिन ए और बी का अधिक मात्रा में लेना चाहिए. खाने में हरी सब्जियां जैसे पालक, गाजर, बथुआ, सरसों, अंकुरित अनाज आदि ज्यादा खाएं. आंखों के भरपूर आराम के लिए नींद बहुत ज़रूरी है. कम से कम छह से आठ घंटे की नींद रोजाना जरूर लेनी चाहिए. दिन में कम से कम दो लीटर या अधिक से अधिक पानी पिएं ताकि आपके शरीर की नमी बनी रहे, जो कि आंखों के लिए भी जरूरी है. पलकों को लगातार झपकाते रहना आंखों को तरोताजा बनाये रखने और उस पर पड़ने वाले दबाव को कम करने का कारगर तरीका है.

गर्मियों में आंखों का रखें खास ख्याल

मोनिशा भटनागर

गर्मी के मौसम में सेहत का ख्याल करने के साथ–साथ आंखों को भी खास देखभाल की जरूरत होती है. गर्मियों में होने वाली आंखों की परेशानियों को अनदेखा नहीं करना चाहिए. गर्मी में आंखों पर सूरज की तेज़ किरणों का बेहद दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है. आंखों की कई बीमारियां जैसे फ्लू, सूजी और थकी लाल आंखें, शुष्क आंखें, आदि गर्मियों में अधिक देखने को मिलती हैं. गर्मियों में बढ़ते हुए प्रदूषण से आंखों में कई तरह के इन्फेक्शन होने का भी खतरा रहता है. सूरज की किरणों में मौजूद अल्ट्रा वायलेट किरणों की वजह से अक्सर धूप में ज्यादा समय तक बाहर रहने पर आंखों में खुजली या जलन होने लगती है. तेज़ धूप की किरणें आंखों के लिए काफी घातक साबित हो सकती हैं. तेज धूप में सूरज की किरणों में मौजूद अल्ट्रा वायलेट (यूवी) रेडिएशन आंखों पर पड़ने से रेटिना को नुकसान होने का खतरा होता है. इससे मोतियाबिंद जैसी आंखों की समस्या होने का सामना भी करना पड़ सकता है. सर्दियों की तुलना में गर्मी में यूवी रेडिएशन तीन गुना ज्यादा होता है. धूप में अल्ट्रावॉयलट किरणें आपकी आंखों पर सीधे तौर से असर करती हैं इसीलिए धूप में धूप का चश्मा यानि सनग्लासेस या छतरी का उपयोग आवश्यक है जिससे आंखों का धूप से बचाव हो सके. ऐसे में सनग्लासेस लेते वक़्त कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए. चश्मे के शीशे हमेशा उच्च गुणवत्ता के होने चाहिए. फोटोक्रोमेटिक लैंस, जो प्रकाश के घटने और बढ़ने के साथ–साथ हल्के और गहरे रंग के होते हैं और डबलशेड यानी ऊपर से गहरे रंग और नीचे से हल्के रंग वाले चश्मे आंखों के लिए सही माने जाते है.साथ ही हमेशा ऐसा सनग्लास पहनें जो कि आपकी आंखों को अल्ट्रावायलट किरणों से बचा सके. जो लोग यू.वी. प्रोटेक्टिव कांटैक्ट लैंस पहनते हैं उन्हें भी सनग्लासेज पहनने की जरूरत है जिससे कि लेंस द्वारा कवर न किए जाने वाले आंखों के हिस्सों की भी रक्षा की जा सके. पावर लेंस लगाने वाले लोगों को भी सनग्लास पहनने चाहिए, ताकि अल्ट्रावायलट किरणें आपकी आंखों को नुकसान न पहुंचा सकें.

आंखों से जुड़ी आम परेशानियों में से एक है कंजक्टिवाइटिस. कंजक्टिवाइटिस गर्मियों में आंखों से जुड़ी सबसे आम बीमारी है. इसके दौरान आंखें सूज जाती हैं और कीचड़ से भर जाया करती हैं. आंखों में बराबर दर्द बना रहता है यहां तक की पलकें झपकने पर भी दर्द होता है. कंजक्टिवाइटिस के प्रमुख लक्षणों में आंखें लाल होना, अत्यधिक खुजली, आंख से गाढ़े तरल बहना और लगातार पानी आना शामिल हैं. इनमें से कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत आंखों के विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए. आंखों की यह बीमारी बहुत तेजी से आसपास के लोगों में फ़ैल सकती है इसलिए अपनी और अपने आसपास के लोगों की भलाई के लिए आंखों के किसी भी संक्रमण से प्रभावित होने के बाद साफ–सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए. कंजक्टिवाइटिस संक्रमित व्यक्ति से क्लोज कांटेक्ट में आने से या इन्फेक्टेड हाथों के आंखों पर लगने से हो सकता है. ऐसे में रोगी को इन बातों का ख्याल रखना चाहिए. आंखों को बार–बार हाथ से न छुएं और न ही रगड़ें, बार–बार हाथ धोएं, काला चश्मा पहन कर रखें और अपना चश्मा किसी और को पहनने के लिए न दें. साथ ही बीमार व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की हुई किसी भी चीज को अपने संपर्क में न लाएं. आंखों में तकलीफ होने पर दिन में तीन–चार बार आंखें साफ़ पानी से साफ करें. आंख में खुजली होने पर कभी आंख न मलें. ज्यादा खुजली होने पर साफ और मुलायम कपड़े से आंख सहलाएं पर हल्के हाथ से.

> आंखों से जुड़ी आम परेशानियों में से एक है कंजक्टिवाइटिस. कंजक्टिवाइटिस गर्मियों में आंखों से जुड़ी सबसे आम बीमारी है. इसके दौरान आंखें सूज जाती हैं और कीचड़ से भर जाया करती हैं. आंखों में बराबर दर्द बना रहता है यहां तक की पलकें झपकने पर भी दर्द होता है. कंजक्टिवाइटिस के प्रमुख लक्षणों में आंखें लाल होना, अत्यधिक खुजली, आंख से गाढ़े तरल बहना और लगातार पानी आना शामिल हैं. इनमें से कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत आंखों के विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए.

इसके अलावा गर्मियों में आंखों का ख्याल रखने के लिए आंखों पर दिन में कई बार ठंडे पानी के छींटे मारें, आंखों को ठंडे पानी से निरंतर साफ करें और आंखों को मलने से परहेज करें. थकी हुई आंखों को आराम देने के लिए खीरे के टुकड़े आंखों पर रखें.आंखों के आस–पास की त्वचा बहुत सॉफ्ट होती है. बाहर की तेज रोशनी और गर्मी की चमक त्वचा के साथ आंखों को हानि पंहुचा सकती है. ऐसे में धूप से अन्दर आने के बाद कुछ देर के लिये आंखें बन्द कर बैठ जायें ताकि आंखों का तापमान सामान्य हो सके. साथ ही आंखों पर खीरे के टुकडे या रुई के फाहे में गुलाब जल डालकर रखने से आंख के आस–पास की त्वचा को आराम मिलता है. साथ ही इससे आंखों को ताजगी भी मिलेगी. स्वस्थ और तेज़ आंखों के लिए पौष्टिक भोजन और अच्छी नींद दोनों ही बेहद आवश्यक हैं. गर्मी में विटामिन ए और बी का अधिक मात्रा में लेना चाहिए. खाने में हरी सब्जियां जैसे पालक, गाजर, बथुआ, सरसों, अंकुरित अनाज आदि ज्यादा खाएं. आंखों के भरपूर आराम के लिए नींद बहुत ज़रूरी है. कम से कम छह से आठ घंटे की नींद रोजाना जरूर लेनी चाहिए. दिन में कम से कम दो लीटर या अधिक से अधिक पानी पिएं ताकि आपके शरीर की नमी बनी रहे, जो कि आंखों के लिए भी जरूरी है. पलकों को लगातार झपकाते रहना आंखों को तरोताजा बनाये रखने और उस पर पड़ने वाले दबाव को कम करने का कारगर तरीका है. साथ ही आंखों में कोई तकलीफ न होने पर भी वर्ष में कम से कम एक बार आंखों की जांच जरूर करवानी चाहिए. इससे आंखों से जुड़े कई तत्वों की जांच भी हो जाती है और साथ ही कई संभावित रोगों का समय से इलाज भी किया जा सकता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

रूप बदलने में माहिर थी सारा एडमंड

अरुण तिवारी

> विकॉनफेडरेट सेना के कैंप में जाने के लिए सारा ने एक नीग्रो आदमी का रूप धरा था. इसके लिए उन्होंने अपने चमड़ी सिल्वर नाइट्रेट के जरिये काली कर ली थी और बालों में घुंघराला काला विग लगाया हुआ था. उन्होंने अपना नाम कफ रखा था. एक बार ऐसा हुआ था कि वे कॉनफेडरेट आर्मी में महिला बनकर फल बेचती रहती थीं और गोपनीय सूचनाएं संघीय सेनाओं को पहुंचाया करती थीं.

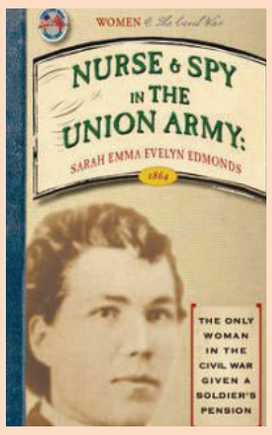

नाटक की दुनिया के बेताज बादशाह कहे जाने वाले विलियम शेक्सपियर की कृतियों का जब मंचन किया जाता था तो महिलाओं के वेश के लिए भी पुरुष ही रूप बदलकर मंचन करते थे. महिलाओं को उस समय नाटक में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता था. यह सोलहवीं सदी की पश्चिमी सभ्यता थी.वक्त बदला तो 18वीं सदी में अमेरिका में एक ऐसी महिला भी आई जिसने पुरुषों का रूप धारण कर अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान संघीय सेनाओं की काफी मदद की थी.

सारा एमा एडमंड कनाडाई युवती थीं जिन्हें अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान पुरुष वेश में युद्ध लड़ने के कारण याद किया जाता है. उन्हें रूप बदलने का महारथी माना जाता था. उनके कारनामों के बारे में'नर्स एंड स्पाई इन द यूनियन आर्मी' नामक किताब में काफी विस्तृत रूप से बताया गया है. उनके इन्हीं कारनामों की वजह से साल 1992 में सम्मानस्वरूप मिशिगन वीमेन्स हॉल ऑफ फेम में उन्हें जगह दी गई थी. दरअसल अपने रूप बदलने की कला की वजह से पुरुष बन सारा विरोधी खेमें में भी शामिल हो जाती थीं और गोपनीय सूचनाएं संघीय सेनाओं तक पहुंचा दिया करती थीं.

सारा बचपन से साहसी कारनामें किया करती थीं. साहस के शुरुआती बीज सारा में तब पड़े जब उन्होंने मैटूरिट मूरे बलाउ की किताब फैनी कैंबेल पढ़ी. इस किताब में फैनी कैंबेल, जो महिला समुद्री डाकू थी, के बारे में बताया गया था कि आखिर कैसे वह समुद्री जहाजों को रूप बदल कर लूटा करती थी. उस किताब में फैनी का वर्णन एक पुरुष के रूप में ही किया गया था जबकि वह एक महिला थी. फैनी और भी दूसरे साहसिक कार्य पुरुषों के वेश में ही किया करती थी. यहीं से सारा के दिमाग में भी पुरुष वेश धारण करने का विचार कौंधा था.

अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान सारा की भी इच्छा हुई कि वे इस युद्ध में हिस्सा लें. इसके लिए मिशिगन इंफैंट्री में आवेदन किया लेकिन उन्हें नहीं लिया गया. उन्होंने फिर दूसरा प्रयास किया. वे चयनित हो गईं. दोनों ही बार उन्होंने अपनी पहचान एक पुरुष के रूप में रखी और पुरुषों के जैसा रूप भी बनाया हुआ था. दरअसल उस समय अमेरिकी संघीय सेना की तरफ से गृह युद्ध में हिस्सा लेने के लिए सेना स्वयंसेवकों की तलाश कर रही थीं. सारा ने उसी के तहत आवेदन किया था. उन्होंने आवेदन फॉर्म में अपना नाम फ्रैंकलिन फ्लिंट थांपसन रखा था. शुरुआत में उन्हें पुरुष नर्स के तौर पर सेना में नौकरी दी गई थी और उन्हें इसी काम के लिए सेवा का मौका भी दिया गया.

फ्रैंकलिन थांपसन का रूप धरे सारा को जल्दी ही अपनी काबिलियत साबित करने का मौका मिला जब वर्जिनिया में लड़ाई के दौरान उनके मित्र की पहचान जासूस के रूप में विरोधी सेनाओं ने कर ली. उनके मित्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई. सारा ने अपने आलाधिकारियों से संपर्क साधा और उन्हें बताया कि जासूस मित्र की मौत हो चुकी है. उसे विरोधी सेनाओं ने मौत के घाट उतार दिया है. संघीय अधिकारियों के लिए भी यह किसी चुनौती से कम नहीं था कि किसी व्यक्ति को वे तुरंत जासूस के रूप में वर्जिनिया में नियुक्त करें. सारा ने इस पद के लिए आवेदन किया और अपने अधिकारियों को इस बात का भरोसा दिलाया कि वे जासूस के रूप में बेहतर काम कर सकती हैं. इस तरह फैंकलिन का रूप धरे सारा को विरोधियों के खिलाफ जा–सूसी करने का काम मिल गया जो उनके लिए किसी सपने के पूरा होने से कम नहीं था.विरोधी खेमे में जासूसी के दौरान सारा को अपना रूप कई बार बदलना पड़ा. ऐसा पहला वाकया तब हुआ जब सारा को कॉनफेडरेट आर्मी के बीच पड़ा. कॉनफेडरेट राज्य अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान वे राज्य थे जिन्होंने अमेरिकी संघ के विरुद्ध बगावत की थी. कॉनफेडरेट सेना के कैंप में जाने के लिए सारा ने एक नीग्रो आदमी का रूप धरा था. इसके लिए उन्होंने अपने चमड़ी सिल्वर नाइट्रेट के जरिये काली कर ली थी और बालों में घुंघराला काला विग लगाया हुआ था. उन्होंने अपना नाम कफ रखा था. इसके अलावा भी कई मौकों पर उन्होंने कॉनफेडरेट आर्मी को चकमा दिया था. एक बार ऐसा हुआ था कि वे कॉनफेडरेट आर्मी में महिला बनकर फल बेचती रहती थीं और गोपनीय सूचनाएं संघीय सेनाओं को पहुंचाया करती थीं.

सारा के करियर में मुश्किल मोड़ तब आया जब उन्हें मलेरिया हो गया था. उन्हें इस बात का भय हो गया कि अगर वे वापस अपने कैंप लौटती हैं तो उन्हें मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाएगा. जहां जांच के दौरान यह बात सबके सामने खुल जाएगी कि वे एक महिला हैं न कि पुरुष. इस भय से उन्होंने एक प्राइवेट नर्सिंग होम में अपना इलाज करवाया. लेकिन सबसे दुखद बात तो यह हुई कि जब वे वापस लौटीं तो हर तरफ इस बात के पोस्टर लगे हुए कि फ्रैंकलिन एक भगोड़ा है. तब उन्होंने यह निश्चय किया वे सेना के लिए काम नहीं करेंगी क्योंकि अगर वे फ्रैंकलिन के रूप में सेना के कैंप में वापस लौटतीं तो इस बात का खतरा था कि उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता. उन्होंने दूसरा रास्ता निकाला और एक महिला नर्स के रूप में वाशिंगटन में ही काम करना शुरू कर दिया.

हालांकि फ्रैंक के रूप में सारा के काम की उनके कई सहकर्मियों ने काफी प्रशंसा की. कई सहकर्मियों की किताबो में इस बात का जिक्र किया गया कि फ्रैंक एक बेहतरीन जासूस और सैनिक था. गृह युद्ध के बाद सारा ने एक कनाडाई नागरिक से शादी की जिनसे उन्हें तीन बच्चे हुए. सारा पर एक किताब भी आई जो बेस्ट सेलर साबित हुई. सारा को अमेरिकी सरकार की तरफ से पेंशन भी दी जाती थी. उनके कारनामों को लोगों के बीच कई सालों तक याद रखा गया. आज भी अमेरिकी गृह युद्ध में हिस्सा लेने के लिए सारा को अमेरिकी इतिहास में गर्व के साथ याद किया जाता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

मुर्सी को सज़ा

फैसला न्याय पर आधारित या राजनीतिक खेल

वसीम अहमद

मिस्र की अदालत ने देश के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को 20 वर्ष कैद की सज़ा सुनाई है. यह पहली बार हुआ है कि मोहम्मद मुर्सी को निष्कासित किए जाने के बाद उन्हें सज़ा सुनाई गई है. पूर्व राष्ट्रपति मुर्सी पर आरोप है कि उन्होंने 2012 में राष्ट्रपति भवन के बाहर होने वाले प्रदर्शन में अपने समर्थकों के द्वारा प्रदर्शनकारियों पर नियंत्रण के लिए बल प्रयोग किया और उसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी. मोहम्मद मुर्सी पर कुल तीन आरोप लगाए गए थे. प्रदर्शनकारियों की हत्या व उत्पीड़न, न्यायालय की अवमानना और राष्ट्रीय ख़ुफ़िया जानकारियां दूसरे देशों को देना. पहले आरोप का निर्णय आ चुका है. इस निर्णय में मोहम्मद मुर्सी के अलावा 12 अन्य उख़्वानियों को 20–20 वर्ष की सज़ा दी गई है. शेष दो मुक़दमों का निर्णय मई तक आने की संभावना है. जिन आरोपियों के ख़िलाफ़ निर्णय आया है, उनमें मोहम्मद मुर्सी के अलावा उख़्वानी प्रमुख मोहम्मद बल्ताजी, वरिष्ठ नेता वजदी और उख़्वानी मुबल्लिग़ अस्साम अरबान शामिल हैं.

अदालत के इस फैसले में कितनी पारदर्शिता बरती गई है. इस पर पूरी दुनिया में चिंता देखने को मिलती है. चिंता का कारण यह है कि इस पूरे मुक़दमे में एक तो मुर्सी को अपनी सफ़ाई और सबूत उपलब्ध करने के लिए मौक़ा नहीं दिया गया और दूसरे इस मुक़दमे को देखने के लिए जिस प्रकार से एक जज को क्राइम कोर्ट में नियुक्त किया गया, इसमें पूरा राजनीतिक खेल नज़र आ रहा है मुर्सी के इस मुक़दमे को क़ाहिरा क्राइम कोर्ट के क़ाज़ी अहमद सबरी यूसुफ देख रहे थे. वह पिछले वर्ष रिटायर होने वाले थे, लेकिन न्याय मंत्रालय की ओर से 27 दिसंबर को एक विशेष आदेश के द्वारा उनकी कार्यावधि को बढ़ा दिया गया, ताकि वह इस मुक़दमे को देख सकें. उनकी इस नियुक्ति के सिलसिले में अनातोलिया के न्यायिक सूत्रों का कहना है कि 6 माह पूरे होने के बाद 30 जून को उन्हें प्रोन्नति देकर अगले दो वर्षों के लिए सुप्रीम जूडिशियल कॉन्सिल का सदस्य बनाया जा सकता है. इसके बाद उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा. अगर अनातोलिया सूत्रों पर विश्वास किया जाए तो बात बिल्कुल साफ़ हो जाती है कि इस नियुक्ति के पीछे पूरा राजनीतिक खेल है और क़ाज़ी यूसुफ़ को उच्च पद का लालच देकर मन मुताबिक फैसला करवाया गया है. वैसे भी पिछले कुछ वर्षों में मिस्र की अदालतों को जिस प्रकार से राजनीतिक अखाड़ा बना दिया गया है, उसे देखते हुए इन संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है कि फैसले में कहीं न कहीं राजनीतिक दांव–पेंच खेला गया है. वरना क्या कारण है कि एक ही तरह के दो मुक़दमों में दो पूर्व राष्ट्रपति यानी होस्नी मुबारक और मोहम्मद मुर्सी के ख़िलाफ़ अलग–अलग फैसले आते हैं. 2011 में जब होस्नी मुबारक राष्ट्रपति थे तो तहरीर स्क्वायर के प्रदर्शनकारियों पर स्टेट मिशनरी ने ज़रबदस्त हिंसा की थी और इसमें सैंकड़ों इंसानों को निर्दयता से मौत के घाट उतार दिया गया था. इन आरोपों की बुनियाद पर 2012 में क़ाज़ी अहमद रफ़त ने उनको कैद की सज़ा भी सुनाई थी. इस समय सरकार मोहम्मद मुर्सी की थी, लेकिन अलसीसी सरकार आने के बाद मिस्री अदालत ने होस्नी मुबारक को सभी आरोपों से बरी कर दिया है. इस एहसान के बदले होस्नी मुबारक अब अलसीसी सरकार के समर्थन में बयान दे रहे हैं. अभी हाल ही में सीना की 33वीं आज़ादी के एक प्रोग्राम के मौक़े पर एक चैनल को बयान देते हुए होस्नी मुबारक ने कहा कि मिस्र इस समय नाज़ुक दौर से गुज़र रहा है और इस नाज़ुक दौर में अब्दुल फतह अलसीसी के समर्थन में मदद करना न केवल मिस्र की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि पूरे अरब क्षेत्र की सुरक्षा के लिए आवश्यक है.

बहरहाल, निर्णय दबाव में दिया गया हो या स्वतंत्र, लेकिन जिन 13 लोगों के ख़िलाफ़ यह निर्णय सुनाए गए हैं, इस फैसले ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है और यह संदेह पैदा कर दिया है कि वहां की अदालतें सेना के दबाव में अपना काम कर रही हैं. ऐसा सोचने का एक कारण यह भी है कि मोहम्मद मुर्सी को अपने ऊपर लगाए गए आरोप के ख़िलाफ़ सफ़ाई देने और सबूत उपलब्ध करने का मौक़ा नहीं दिया गया. इस सिलसिले में एमनेस्टी इंटरनैशनल ने सवाल उठाया है कि बिना किसी आरोप के गिरफ्तार करना, तीन हफ्तों तक बिना कोई आरोप साबित किए उन्हें हिरासत में रखना मिस्री संविधान के ख़िलाफ़ है. संस्था ने यह भी कहा है कि मिस्र की सेना ने उन्हें न तो अपनी बात रखने का अवसर दिया और न ही अपने लिए सबूत उपलब्ध करने की मोहलत दी. ऐसे में फैसले को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है. क़ानून सबको अपनी बेगुनाही साबित करने का मौक़ा देता है और यह हर नागरिक का मूल अधिकार है, जिसे मिस्र की सैन्य अदालत ने नज़रअंदाज़ कर दिया है. आश्चर्य की बात तो यह है कि मुर्सी को अपने वकील से मिलने का भी मौक़ा नहीं दिया जाता है. मुर्सी के वकील इस पूरे मुक़दमे की पैरवी के दौरान नबंवर 2013 में केवल एक बार मुलाक़ात कर पाए हैं. ऐसी स्थिति में किसी के लिए न्यायोचित फैसला सुनाए जाने की उम्मीद कैसे की जा सकती है. यह फैसला पूरी तरह पक्षपातपूर्ण है.

मुर्सी सरकार के ख़ात्मे के बाद अलसीसी प्रशासन ने 15 हज़ार उख़्वानियों से अधिक को गिरफ्तार कर लिया था और इनमें से सैंकड़ों को मौत की सज़ा सुनाई गई. हालांकि अभी तक मौत की सज़ा पर अमल नहीं हुआ है, लेकिन वह सब जेलों में बंद हैं.

मिस्री अदालत के इस फैसले पर मशहूर धार्मिक विद्वान यूसुफ़ क़रज़ावी ने ट्वीट किया है कि मिस्र की अदालत पूर्ण रूप से सेना की प्रतिनिधि बनी हुई है और वह फौजी दबाव में फैसले सुनाती हैं. इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनैशनल स्ट्रैटजिक रिलेशंस ने मिस्री अदालतों के फैसले को राजनीति से प्रभावित बताया है. तुर्की के विदेश मंत्रालय ने अपने एक बयान में मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को 20 वर्ष कैद का आदेश सुनाए जाने से संबंधित कहा है कि मिस्री अदालत का यह फैसला वहां की जनता से मज़ाक और अंतर्राष्ट्रीय क़ानूनों का उल्लंघन है, जो कि मिस्र के लोकतांत्रिक भविष्य को प्रभावित भी करेगा. यूरोपीय यूनियन ने भी इस सिलसिले में कहा है कि मिस्री अदालत का यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय क़ानूनों के उलट है और हमारी मिस्री अदालतों से मांग है कि वह मुक़दमा चलाते समय मानवाधिकारों का ख़्याल रखें. व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जोश अर्नेस्ट ने इस फैसले के हवाले से कहा है कि मिस्री न्याय व्यवस्था को अन्य आरोपियों की तरह मुर्सी को भी अपनी सफ़ाई पेश करने का पूरा मौक़ा देना चाहिए. मुर्सी सरकार के ख़ात्मे के बाद अलसीसी प्रशासन ने 15 हज़ार उख़्वानियों से अधिक को गिरफ्तार कर लिया था और इनमें से सैंकड़ों को मौत की सज़ा सुनाई गई. हालांकि अभी तक मौत की सज़ा पर अमल नहीं हुआ है, लेकिन वह सब जेलों में बंद हैं. जहां तक मोहम्मद मुर्सी की बात है, तो अभी विश्वास के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता है कि मई में आने वाले फैसले में अदालत का रुख़ क्या और कैसा होगा. अगर दूसरे देशों को राष्ट्रीय गुप्त संदेश देने का आरोप साबित हो जाता है, तो उन्हें मौत की सज़ा भी हो सकती है. कहा जाता है कि मोहम्मद मुर्सी ने अपने शासनकाल में जिस देश को गुप्त जानकारियां उपलब्ध कराई थी, वह क़तर है. मोहम्मद मुर्सी ने अपने शासनकाल में कुछ गलतियां की हैं कि लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित होने के बावजूद उन्होंने जो तरीक़ा अपनाया था, उसमें कहीं न कहीं यह अहसास होता था कि वह मिस्र में एक इस्लामी कट्टरवादी सरकार स्थापित करना चाहते हैं. ज़ाहिर है कि एक लोकतांत्रिक देश के लिए यह ठीक नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सरकार का तख़्तापलट करके सरकार का मकान सेना के हवाले कर दी जाए, जैसा कि मिस्र में हुआ. ■

feedback@chauthiduniya.com

बगदादी की मौत : हक़ीक़त या अफवाह?

शफ़ीक आलम

आईएसआईएस या इस्लामिक स्टेट के सरगना और स्वयंभू खलीफा अबूबक्र अल–बगदादी, जिसके सिर पर अमेरिका ने 1 करोड़ डॉलर का इनाम रखा है, की मौत की खबर एक बार फिर दुनिया भर के समाचार माध्यमों की सुर्ख़ियों में है. इस बार इस खबर का श्रोत रेडियो ईरान है. रेडियो ईरान के वेबसाइट पर यह खबर दो इराकी समाचार एजेंसीयों अल–गद प्रेस और अल–यौम अल–समेन और मोसुल में एक इराकी अधिकारी के हवाले से प्रकाशित की गई है. इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि इजराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट के किसी अस्पताल में अल–बगदादी का इलाज हो रहा था. उसका इलाज कर रहे इजराइली सर्जन ने उसे मृत घोषित कर दिया है. हालांकि इस रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि वह कब मरा, लेकिन यह ज़रूर कहा गया है कि इस संगठन ने अब्दुल रहमान अल शिज्लर उर्फ़ अबू अल–अफ़्री को अपना नया मुखिया चुन लिया है. बगदादी की मौत की पिछली सभी अफवाहों की तरह इस बार भी न तो इराकी सरकार ने और न ही आईएसआईएस ने या किसी अन्य तीसरे पक्ष ने इस खबर की पुष्टि की है. पिछले दिनों आईएसआईएस के एक सूत्र के हवाले से यह खबर भी आई कि 18 मार्च को अमेरिका द्वारा किए गए एक हवाई हमले में बगदादी गंभीर रूप से ज़ख़्मी हो गया है. साथ में यह खबर भी आई कि बगदादी का आईएसआईएस के रोजाना की कार्रवाई पर नियंत्रण नहीं है. रेडियो ईरान ने जिन ज़ख्मों की वजह से बगदादी की मौत की खबर चलाई थी, उसी खबर के हवाले से न्यूयॉर्क के अख़बार डेली न्यूज़ ने यह खबर प्रकाशित की कि अब बगदादी अपने ज़ख्मों से उबर आया है. दरअसल, एक बार फिर अटकलों का बाज़ार गर्म है. बहरहाल, बगदादी के गंभीर रूप से ज़ख़्मी होने और संगठन की कार्रवाई पर नियंत्रण नहीं होने की बात को अगर सच मान लिया जाए और उसकी मौत के बाद भी उसके संगठन के क्रियाकलापों में कोई तब्दीली नहीं आई और यह भी सच मान लिया जाए कि आईएसआईएस का ऑपरेशन पहले जैसा ही चल रहा है तो इससे ज़ाहिर होता है कि बगदादी के जिंदा रहने या नहीं रहने से इस संगठन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा. आईएसआईएस के ऑपरेशन उसी वक़्त बंद हो सकते हैं, जब इसका पूरा तंत्र ख़त्म हो जाए, तो फिर यह सवाल उठना लाज़मी हो जाता है कि बार–बार बगदादी की मौत की खबर सुर्ख़ियों में क्यों आ जाती है? क्या ये ख़बरें किसी रणनीति के तहत फैलाई जाती हैं? एक सवाल यह भी है कि रेडियो ईरान द्वारा चलाई गई खबर में इजराइल का नाम जानबुझ कर नहीं डाला गया?

आईएसआईएस या इस्लामिक स्टेट का नाम दुनिया के सामने आने के बाद से ही यह संगठन एक पहेली बना हुआ है. इसके बारे में यह कहा गया कि यह इराक में अल्पसंख्यक सुन्नियों का संगठन है, जिसमें सद्दाम हुसैन की सेना के जवान शामिल हैं. यह भी कहा गया कि इसे सऊदी अरब द्वारा क्षेत्र में शियायों के बढ़ते हुए असर व रसूख को कम करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाद में सऊदी एयर फ़ोर्स आईएसआईएस के ठिकानों पर हमले करती नज़र आई. हालांकि यह अलग सवाल है कि सऊदी अरब के हमलों का आईएसआईएस पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ा या नहीं. आईएसआईएस के खिलाफ हवाई हमलों में जॉर्डन भी शामिल था, जिसका एक लड़ाकू विमान मार गिराया गया और पायलट को जिंदा जला दिया गया. कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो इस संगठन को इजराइली षड़यंत्र का नतीजा करार देता है. रेडियो ईरान की खबर को इसी नजरिये से देखना चाहिए. इन अफवाहों में एक अफवाह यह भी है कि बगदादी के कम से कम चार हमशक्ल हैं, इसलिए उसको मारना आसान नहीं होगा.

बगदादी के ज़ख़्मी होने के बाद उसके इलाज के दो ठीकानों की खबरें हैं. पहली खबर बरतानवी अख़बार द गार्डियन की है, जिसके अनुसार वह मोसुल से 200 मील दूर अल–बाज के मुकाम पर आराम कर रहा है. अखबार के मुताबिक, उसने इस इलाके को इसलिए चुना है, क्योंकि यहां अमेरिकियों की पहुंच बहुत कम है. साथ ही यह सुन्नी बहुल इलाका है, जो सद्दाम हुसैन के शासनकाल में भी सरकरी पहुंच से बाहर था. इसलिए यह इलाका 2004 के बाद जिहादियों के लिए एक महफूज़ पनाहगाह बना हुआ है. रेडियो ईरान के मुताबिक, बगदादी की मौत इजराइल के कब्जे वाले गोलन हाइट के किसी अस्पताल में हुई. दरअसल, यह खबर ईरान के इस दावे से मेल खाती है, जिसमें पिछले साल नवम्बर महीने में ईरान के उपविदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने यह आरोप लगाया था कि इजराइल ने न केवल आईएसआईएस को खड़ा किया है, बल्कि इजराइली खुफिया एजेंसी मोसाद अब भी उसकी मदद कर रही है.

दरअसल, इजराइल अरब दुनिया में अत्यधिक अलोकप्रिय देश है. इसलिए ईरान की यह कोशिश है कि आईएसआईएस को इजराइल से जोड़ कर उसे जितना अलोकप्रिय बनाया जा सकता है, बनाया जाए. रेडियो ईरान कि खबर में बगदादी के इजराइली अस्पताल में इलाज को उसी सिलसिले की कड़ी के रूप में देखा जाना चाहिए. दूसरी तरफ यह माना जाता है कि आतंकवादी संगठनों के सरगना की मौत पूरे संगठन पर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालती है और ख़ुफ़िया एजेंसियां कभी–कभी ऐसे सरगनाओं की खोज के लिए भी इस तरह की अफवाहें फैलाती हैं. जैसे, अलकायदा नेता ओसामा बिन लादेन की मौत की कई बार ख़बरें आईं और हर खबर के बाद उसकी तरफ से कोई न कोई ऑडियो पैगाम आ जाता था. यहां भी शायद इन देशों की खुफिया एजेंसियां अल बगदादी का सुराग खो चुकी हैं. इसलिए हो सकता है कि खुफिया एजेंसियां इस उम्मीद में हों कि अफवाह के बाद उसकी तरफ से कोई बयान आए, जिसके ज़रिये उसकी स्थिति का पता लगाया जा सके.

दरअसल, इसमें कोई शक नहीं कि आईएसआईएस द्वारा ऐसे कायरतापूर्ण कारनामे अंजाम दिए गए हैं, जिसे देख कर इंसानियत शर्मिंदा हो जाए और जिसकी वजह से इस संगठन को दुनिया का सबसे खौफनाक आतंकी संगठन माना गया है. जहां तक इस संगठन के सरगना की मौत की खबर की बात है, तो जब तक इराकी सरकार, अमेरिका या खुद आईएसआईएस की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हो जाती है, तब तक इसे किसी रणनीति का हिस्सा समझा जाना चाहिए या कोरी अफवाह. ■

feedback@chauthiduniya.com

कर्म और भाग्य तीसरी बार आए तो उन्होंने भिखारी को फिर भीख मांगते देखा. भाग्य को बड़ा क्रोध आया. बोला, कितना भी भला कर लो, यह दरिद्र का दरिद्र ही रहेगा! लेकिन इस बार कर्म के मन में दया आ गई. वह भिखारी से बोला–हट्टे–कट्टे हो, तुम कोई काम क्यों नहीं करते? भीख मांगकर कब तक गुजारा चलेगा? भिखारी बोला–काम–धंधे के लिए पास में कुछ पैसे भी तो हों!' कर्म ने कहा–देखो, मैं तुम्हें एक ठेली फल देता हूं. तुम इन्हें बेच कर धंधा करो. भिखारी खुश हो गया.

साई बाबा संत शिरोमणि हैं

चौथी दुनिया ब्यूरो

साई बाबा भक्तों पर स्नेह करने वाले दया के सागर हैं तथा निर्गुण होकर भी भक्तों के प्रेमवश ही जिन्होंने स्वेच्छापूर्वक मानव शरीर धारण किया, जो भक्त उनकी शरण में आते हैं उनके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसे श्री साईनाथ महाराज को हम सभी को नमन करना चाहिए. श्री साई, जो सन्त शिरोमणि हैं, उनका तो मुख्य ध्येय ही यही है. जो उनके श्री–चरणों की शरण में जाते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर निश्चित ही दिन–प्रतिदिन उनकी प्रगति होती है.

एक बार दादासाहेब खापर्डे सहकुटुम्ब शिरडी आये और कुछ मास वहीं ठहरे. दादा कोई सामान्य व्यक्ति न थे. वे एक धनाढ्य और अमरावती(बरार) के सुप्रसिद्ध वकील तथा केन्द्रीय धारा सभा(दिल्ली) के सदस्य थे. वे विद्वान और वक्ता भी थे. इतने गुणवान होते हुए भी उन्हें बाबा के समक्ष मुंह खोलने का साहस न होता था. अधिकांश भक्तगण तो बाबा से हर समय अपनी शंका का समाधान कर लिया करते थे. केवल तीन व्यक्ति खापर्डे, नूलकर और बूटी ही ऐसे थे, जो सदैव मौन धारण किये रहते तथा अति विनम्र और उत्तम प्रकृति के व्यक्ति थे. दादासाहेब, विघारण्य स्वामी द्वारा रचित पंचदशी नामक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रन्थ, जिसमें अद्वैतवेदान्त का दर्शन है, उसका विवरण दूसरों को तो समझाया करते थे, परन्तु जब वे बाबा के समीप मस्जिद में आये तो वे एक शब्द का भी उच्चारण न कर सके. यथार्थ में कोई व्यक्ति, चाहे वह जितना वेद वेदान्तों में पारंगत क्यों न हो, परन्तु ब्रह्मपद को पहुंचे हुए व्यक्ति के समक्ष उसका शुष्क ज्ञान प्रकाश नहीं दे सकता. दादा चार मास तथा उनकी पत्नी सात मास वहां ठहरी. वे दोनों अपने शिरडी–प्रवास से अत्यन्त प्रसन्न थे. श्री मती खापर्डे श्रद्धालु तथा पूर्ण भक्त थी, इसलिये उनका साई चरणों में अत्यन्त प्रेम था. प्रतिदिन दोपहर को वे स्वयं नैवेघ लेकर मस्जिद को जातीं और जब बाबा उसे ग्रहण कर लेते, तभी वे लौटकर आपना भोजन किया करती थीं. बाबा उनकी अटल श्रद्धा की झांकी का दूसरों को भी दर्शन कराना चाहते थे. एक दिन दोपहर को वे सांजा, पूरी, भात, सार, खीर और अन्य भोज्य पदार्थ लेकर मस्जिद में आई. और दिन तो भोजन प्रायः घंटों तक बाबा की प्रतीक्षा में पड़ा रहता था, परन्तु उस दिन वे तुरंत ही उठे और भोजन

श्री मती खापर्डे श्रद्धालु तथा पूर्ण भक्त थी, इसलिये उनका साई चरणों में अत्यन्त प्रेम था. प्रतिदिन दोपहर को वे स्वयं नैवेघ लेकर मस्जिद को जातीं और जब बाबा उसे ग्रहण कर लेते, तभी वे लौटकर आपना भोजन किया करती थीं. बाबा उनकी अटल श्रद्धा की झांकी का दूसरों को भी दर्शन कराना चाहते थे.

के स्थान पर आकर आसन ग्रहण कर लिया और थाली पर से कपड़ा हटाकर उन्होंने रुचिपूर्वक भोजन करना आरम्भ कर दिया. तब शामा कहने लगे कि यह पक्षपात क्यों. दूसरो की थालियों पर तो आप दृष्टि तक नहीं डालते, उल्टे उन्हें फेंक देते है, परन्तु आज इस भोजन को आप बड़ी उत्सुकता और रुचि से खा रहे हैं. आज इस बाई का भोजन आपको इतना स्वादिष्ट क्यों लगा. यह विषय तो हम लोगों के लिये एक समस्या बन गया है. तब बाबा ने इस प्रकार समझाया. सचमुच ही इस भोजन में एक विचित्रता है. पूर्व जन्म में यह बाई एक व्यापारी की मोटी गाय थी, जो बहुत अधिक दूध देती थी. पशुयोनि त्यागकर इसने एक माली के कुटुम्ब में जन्म लिया. उस जन्म के उपरान्त फिर यह एक क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हई और इसका ब्याह एक व्यापारी से हो गया. दीर्घ काल के पश्चात इनसे भेंट हुई है. इसलिये इनकी थाली में से प्रेमपूर्वक चार ग्रास तो खा लेने दो. ऐसा बतला कर बाबा ने भर पेट भोजन किया और फिर हाथ मुंह धोकर और तृप्ति की चार–पांच डकारें लेकर वे अपने आसन पर पुनः आ बिराजे. फिर श्रीमती खापर्डे ने बाबा को नमन किया और बाबा का पांव दबाने लगीं. बाबा उनसे वार्तालाप करने लगे और साथ–साथ उनके हाथ भी दबाने लगे. इस प्रकार परस्पर सेवा करते देख शामा मुस्कुराने लगा और बोला कि देखो तो, यह एक अदभुत दृश्य है कि भगवान और भक्त एक दूसरे की सेवा कर रहे है. उनकी सच्ची लगन देखकर बाबा अत्यन्त कोमल तथा मृदु शब्दों मे अपने श्रीमुख से कहने लगे कि अब सदैव राजाराम, राजाराम का जप किया करो और यदि तुमने इसका अभ्यास क्रमबद्ध किया तो तुम्हे अपने जीवन के ध्येय की प्राप्ति अवश्य हो जायेगी. तुम्हें पूर्ण शान्ति प्राप्त होकर अत्यधिक लाभ होगा. आध्यात्मिक विषयों से अपरिचित व्यक्तियों के लिये यह घटना साधारण–सी प्रतीत होगी, परन्तु शास्त्रीय भाषा में यह शक्तिपात के नाम से विदित है, अर्थात गुरु द्वारा शिष्य में शक्तिसंचार करना.

कितने शक्तिशाली और प्रभावकारी बाबा के वे शब्द थे, जो एक क्षण में ही हृदय–कमल में प्रवेश कर गये और वहां अंकुरित हो उठे. यह घटना गुरु–शिष्य सम्बन्ध के आदर्श की घोतक है. गुरु–शिष्य दोनों को प्रेम और एक दूसरे की सेवा करनी चाहिये, क्योंकि उन दोनों में कोई भेद नहीं है. वे दोनों अभिन्न और एक ही है, जो कभी पृथक नहीं हो सकते. शिष्य गुरुदेव के चरणों पर मस्तक रख रहा है, यह तो केवल बाह्य दृश्यमान है. आन्तरिक दृष्टि से दोनों अभिन्न और एक ही है तथा जो उनमें भेद समझता है, वह अभी अपरिपक्व और अपूर्ण ही है. ■

feedback@chauthiduniya.com

साई के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुःख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वही नहीं है दूर.
10. मुझमें लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य-धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन–201301
ई–मेल feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

बिहार में भाजपा की चिंता

राजद सहित छः दलों की महाविलय की एकजुटता देख भाजपा का दम घुटने लगा है. भाजपा की तमाम अटकलबाजियां धरी–की–धरी रह गयी, दलितों–महादलितों का शतरंजी चौपड़ उनका फेल होता दिख रहा है. क्योंकि बिहार में दलित महादलित समुदाय भाजपा की हर नाटकीय अंदाज, छलावा, साजिशर्पूण गुमराह करने की तरकीब, लुभावने वादों से तंग आ चुकी है. भाजपा के हाथ कुछ आता न देख भाजपाई हताश व निराश हो गए हैं. बिहार में भाजपा की स्थिति खराब है. जनाधार कमजोर हो चुका है और जनता अब झूठे वादों के चक्कर में फसने वाली नहीं है. मिथ्या प्रचार–प्रसार कर देश के जनता को दिगभ्रमित कर रही है. भाजपा बड़े–बड़े वादों, घोषणाओं, योजनाओं का ऐलान तो किया पर सरजमी पर कहीं भी कुछ नहीं दिख रहा है, उल्टे किसानों की जमीन छीनने पर सरकार अड़ी हुई है. बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी से देश की जनता परेशान है. भाजपा की यह तमाम वादाखिलाफी और जनता के साथ झूठे वादों का असर बिहार के विधानसभा चुनाव पर निश्चित पड़ेगा.

–निर्भय अम्बेडकर, ई–मेल के द्वारा.

मोदी ने मान बढ़ाया

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की विदेश नीति के बाद नरेन्द्र दामोदर दास मोदी की विदेश नीति की चर्चा जोरों पर है. मोदी की नीति को देश में बेहतर कारोबारी संबंधों के लिए विवादित मुद्दों को दरकिनार कर नए रिश्तों का दौर शुरू करने की कोशिश की तरह देखा जा रहा है. सजगता, जवाबदेही और पारदर्शिता का पता चला है. उदाहरण के तौर पर जापान समेत कई देशों को कारोबार के लिए निमंत्रण देना और मेक इन इंडिया का हिस्सा बनने के लिए बुलाना और आश्वासन देना की लालफीता शाही को खत्म किया जाएगा. यह एक नई सुधार प्रक्रिया को दर्शाता है. हमारे राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता और मर्यादा अपने आप में अनूठी है. अब यह उम्मीद जाग उठी है कि मोदी के कार्यकाल में कारोबार प्रगति करेगा, जिसका असर समावेशी विकास पर दिखेगा. अब हमे पिछली विकृतियों को छोड़कर एक नए राष्ट्र के निर्माण में लग जाना चाहिए.

–अशोक निर्मोही, दरभंगा, बिहार.

यह कदम देशहित के खिलाफ है

कवर स्टोरी–आधार कार्ड खतरनाक है(20 अप्रैल–26 अप्रैल 2015) पढ़ा. बेहद प्रभावित किया. मनीष कुमार से मैं सहमत हूं कि क्या अब इस देश में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का कोई महत्व नहीं रह गया है? क्योंकि सुप्रीमकोर्ट के बार–बार आधार कार्ड को अनिवार्य न बनाने के आदेश देने के बाद भी सरकार गैस सिलेंडर सब्सिडी से लेकर कई चीजों के लिए आधार कार्ड को बना दिया है. लेकिन सबसे चौकाने वाली बात यह भी है कि सुप्रीमकोर्ट सब कुछ देखते हुए भी चुप है. ऐसा नहीं हो सकता कि सुप्रीमकोर्ट को सरकार के इस कदम के बारे में जानकारी न हों. सरकार सुप्रीमकोर्ट के आदेश की ही अवहेलना कर रही है, फिर भी सुप्रीमकोर्ट चुप है. हमारे देश के लोगों की सारी जानकारियां दूसरे देशों के पास जा रही है. सांसद को हम संसद में अन्य चीजों पर हंगामा मचाते तो खूब देखते हैं, लेकिन सासंद भी लोकसभा या राज्यसभा में यह मुद्दा नहीं उठाते हैं. सरकार का यह कदम देशहित के खिलाफ है.

–रवि रंजन सिंह, लखनऊ, उत्तर प्रदेश.

साख बचानी होगी

आलेख–मीडिया आलोचना से परे नहीं है (20 अप्रैल–26 अप्रैल 2015)पढ़ा. काफी विचारोत्तजेक है. कमल मोरारका ने सही कहा है कि यमन से देशवासियों को सुरक्षित निकाल लाना यह सरकार और विदेश मंत्रालय के लिए एक बड़ी उपलब्धी है. मीडिया में कुछ लोग ऐसे हैं, जो व्यक्तिगत रूप से जनरल वीके सिंह के खिलाफ हैं. मीडिया ने उनके पाकिस्तान डे के मौके पर पाकिस्तानी दूतावास में जाने पर भी विवाद खड़ा किया था. बी के सिंह भी मीडिया में उनके खिलाफ खबरें चलाए जाने से नाराज दिखे, उन्होंने मीडिया में उन लोगों के खिलाफ प्रेस्टीट्यूट शब्द का इस्तेमाल किया जो उनके खिलाफ लगातार खबरें चला रहे थे.कमल मोरारका ने बिल्कुल सहा कि वे भी एक कॉरपोरेट घराने से आते हैं और बार–बार कहा जाता है कि कॉरपोरेट घराने ब्लैक मनी, ब्लैक मार्केटिंग और टैक्स चोरी में शामिल होते हैं. लेकिन, वो कभी इससे आहत नहीं तो, क्योंकि ये आरोप उनके ऊपर लागू नहीं होते थे और इसलिए वह आहत नहीं होते थे. बी के सिंह ने भी सबके लिए उस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था जो उन्होंने स्वयं कहा था. कुछ लोगों के कारण पूरी मीडिया पर सवाल खड़े होते हैं जो मीडिया की साख के लिए ठीक नहीं है.

–अश्वनी उपाध्याय, पालम, दिल्ली.

केजरीवाल की माफ़ी

होना था जो हो गया,
अब काहे का द्वन्द
माफ़ी भी तो मांग ली,
करो कहानी बंद करो कहानी बंद,
मौत पर किसका वश है मैं ठहरा मतिमंद,
यही पर शाश्वत सच है मित्र केज़रीवाल,
खेल फिर वो ही खेलो चलो सियासी चाल,
राय जनता की ले लो.

–पं रामखेलावन गर्ग, कटनी, मध्यप्रदेश.

कहानी

श्रम की गरिमा

भाग्य और कर्म धरती की सैर कर रहे थे. घूमते–घूमते उनकी नजर एक भिखारी पर पड़ी. भाग्य के मन में दया उपजी और उसने अपनी उंगली से उतारकर सोने की अंगूठी उसे दे दी. अंगूठी बेचकर भिखारी ने कुछ दिन सुख से बिताए. अगली बार जब कर्म और भाग्य दोबारा उधर से गुजरे तो भिखारी को फिर भीख मांगते देखा. इस बार भाग्य ने अपने गले से उतारकर सोने का हार उसे दे दिया. भिखारी के थोड़े दिन और सुख से बीत गए.

कर्म और भाग्य तीसरी बार आए तो उन्होंने भिखारी को फिर भीख मांगते देखा. भाग्य को बड़ा क्रोध आया. बोला, कितना भी भला कर लो, यह दरिद्र का दरिद्र ही रहेगा! लेकिन इस बार कर्म के मन में दया आ गई. वह भिखारी से बोला–हट्टे–कट्टे हो, तुम कोई काम क्यों नहीं करते? भीख मांगकर कब तक गुजारा चलेगा? भिखारी बोला–काम–धंधे के लिए पास में कुछ पैसे भी तो हों!' कर्म ने कहा–देखो, मैं तुम्हें एक ठेली फल देता हूं. तुम इन्हें बेच कर धंधा करो. भिखारी खुश हो गया.

बहुत दिनों के बाद जब कर्म और भाग्य घूमते–घूमते फिर उस नगर में आए तो उन्होंने खूब ढूंढा, पर उस भिखारी के दर्शन नहीं हुए. अंत में जब वे मुख्य बाजार से गुजरे तो देखा भिखारी तो अब फलों का बड़ा व्यापारी बन चुका था. भाग्य उसे देखता रह गया. कर्म ने मुस्कराते हुए कहा, देखा, तुमने इसे भीख में सोना दिया और मैंने इसे श्रम की गरिमा से परिचित कराया. सोना पाकर तो यह निठल्ला बना रहा, लेकिन श्रम का महत्व समझते ही काम में मन लगाकर फलों का इतना बड़ा व्यापारी बन गया. भाग्य उसकी बात का मर्म समझ गया. ■

feedback@chauthiduniya.com

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर–11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन–201301

अपनों–अपनों को दे...

अनंत विजय

मशहूर व्यंग्यकार और हिंदी साहित्य जगत के अपने तरह के अनूठे रचनाकार हरिशंकर परसाईं ने साहित्य और नंबर दो का कारोबार में लिखा है, मैं भी सांस्कृतिक क्रांति के दौर से गुजर लिया. पहले अपना कमाया पैसा भी अपना नहीं लगता था. अब सिर्फ़ दूसरों का खाया पैसा ही अपना कमाया लगता है. सारे मूल्यों में क्रांति हो गई. पहले समारोहों में फूल माला पहनते खुशी होती थी, अब वह गर्दन में लटका फालतू बोझ मालूम होती है. सांस्कृतिक क्रांति ने फूलों की सुगंध छीन ली है और मैं माला पहनते हिसाब लगाता रहता हूं कि अगर हर फूल की जगह नोट होता, तो इस वक्त कितने रुपये मेरे गले में लिपटे होते. मैं माला से उस लिफाफे की रकम का अंदाज़ लगाता रहता हूं, जो कि बाद में दिया जाएगा. मुझे गुलाब की माला पहनाओ, चाहे गेंदे की, चाहे भटकटैया की, सब एक ही हैं. फूल की पंखुड़ी सिक्के का एहसास देती है. बीच में मूल्यों का विघटन हो गया था. अब वे सिक्कों से जुड़ गए हैं. अपना मूल्यहीनता का युग समाप्त. जिनका चल रहा है, वो इस पुरानी बीमारी का इलाज कराएं. साहित्य में अच्छे–अच्छे अनुभवी हकीम मौजूद हैं.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नैतिकता की दुहाई देते नहीं थकते, लेकिन इतने बड़े आयोजन में नैतिकता की धज्जियां उड़ीं और उनका पूरा अमला खामोशी के साथ देखता रहा. बिहार संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष और क्रांतिवीर आलोक धन्वा इसका बचाव करते हुए मार्ग्रेट थैचर का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को लाइसेंस दिया था, क्योंकि वह योग्य था. यहां आलोक धन्वा पता नहीं क्यों ब्रिटेन चले गए, बल्कि उन्हें तो इंदिरा गांधी और संजय गांधी का उदाहरण देना चाहिए था, क्योंकि जिस क्रांति की विचारधारा के वह समर्थक हुआ करते थे, उसने इमरजेंसी में इंदिरा गांधी का समर्थन किया था.

बिहार के कला संस्कृति और युवा विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय हिंदी कथा समारोह के बारे में जानकर परसाईं जी की उक्त पंक्तियां शिद्दत से याद आईं. बिहार में मूल्यहीनता का युग समाप्त हो चुका है. वहां साहित्य के एक से एक अच्छे और अनुभवी हकीमों ने मूल्यहीनता का एक ऐसा वातावरण बना दिया है कि फूल की पंखुड़ी सिक्कों से जुड़ती चली जा रही है. बिहार में साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में पिछले दिनों जिस तरह से विवाद हुए और गिरावट आई, उससे कम से कम इस धारणा की पुष्टि अवश्य होती है. हालिया उदाहरण है, अखिल भारतीय हिंदी कथा समारोह के आयोजन का. 25 से 27 अप्रैल तक हुए तीन दिनों के इस कथा समारोह में लेखकों के चयन को लेकर साहित्यिक हकीमों ने जबरदस्त खेल खेला. इस आयोजन की ज़िम्मेदारी जेडीयू कोटे से विधान परिषद के सदस्य राम बचन राय, एक जमाने में क्रांति की कविता लिखने वाले आलोक धन्वा, हाल में पद्मश्री से सम्मानित ऊषा किरण खान के अलावा सूबे के सांस्कृतिक कार्य निदेशालय के निदेशक, संगीत नाटक अकादमी बिहार के सचिव और संस्कृति विभाग के सहायक निदेशक को सौंपी गई. सबसे पहली गड़बड़ी इसके सहभागियों के चयन को लेकर हुई. आयोजन समिति के दो सदस्यों ने अपने रिश्तेदारों को प्रतिभागी बना दिया. राम बचन राय की पत्नी इंदु मौआर को बतौर कहानीकार प्रतिभागी बना दिया गया और ऊषा किरण खान की बेटी कनुप्रिया को अपनी मां द्वारा लिखित रचना पर नाटक के मंचन की ज़िम्मेदारी दी गई.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नैतिकता की दुहाई देते नहीं थकते, लेकिन इतने बड़े आयोजन में नैतिकता की धज्जियां उड़ीं और उनका पूरा अमला खामोशी के साथ देखता रहा. बिहार संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष और क्रांतिवीर आलोक धन्वा इसका बचाव करते हुए मार्ग्रेट थैचर का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को लाइसेंस दिया था, क्योंकि वह योग्य था. यहां आलोक धन्वा पता नहीं क्यों ब्रिटेन चले गए, बल्कि उन्हें तो इंदिरा गांधी और संजय गांधी का उदाहरण देना चाहिए था, क्योंकि जिस क्रांति की विचारधारा के वह समर्थक हुआ करते थे, उसने इमरजेंसी में इंदिरा गांधी का समर्थन किया था. इंदु मौआर का चयन वह नामवर सिंह और काशीनाथ सिंह के उदाहरण से सही ठहराने की कोशिश करते हैं, लेकिन आलोक धन्वा यह भूल जाते हैं कि इंदु मौआर जी का कहानीकार के रूप में हिंदी के वृहत्तर जगत से परिचय होना शेष है. एक और राजनेता पद्माशा को भी कथाकार बना दिया गया. उसी तरह हिंदी के मशहूर कथाकार और साहित्यिक पत्रिका तद्भव के यशस्वी संपादक अखिलेश को समीक्षक बनाकर आमंत्रित किया गया. यह एक कथाकार का अपमान और चयन समिति के सदस्यों की अज्ञानता है, क्योंकि अखिलेश को डॉ. खगेंद्र ठाकुर, रविभूषण, तरुण कुमार जैसे आलोचकों के साथ रखा गया है. हालांकि, कुछ लोगों का कहना है कि यह किसी तरह से एडजस्ट करने का मामला भी है.

दरअसल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों सियासी उलझनों में फंसे हुए हैं और साहित्य, कला–संस्कृति को उन्होंने आलोक धन्वा, राम बचन राय और ऊषा किरण खान के हवाले कर दिया है. कथा समारोह में कथाकारों और समीक्षकों के चयन में गड़बड़ियों के लिए ज़िम्मेदारी तय हो पाएगी, इसमें संदेह है. इसके अलावा जब पूरा बिहार भूकंप के खौफ में था, उस वक्त पटना के तारा मंडल में इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही थी. एक तरफ़ लाशें निकाली जा रही थीं, तो दूसरी तरफ़ नाटक हो रहा था. साहित्यकारों की संवेदना को मरते देखा लोगों ने. इसी तरह पहले राजभाषा पुरस्कारों को लेकर विवाद हुआ था. उस विवाद की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि अब वहां कला पुरस्कारों के लिए चयन को लेकर सवाल खड़े हो गए. कला पुरस्कार के लिए चयनित वरिष्ठ कथाकार एवं रंग–समीक्षक हृषिकेश सुलभ ने ऐलान के बाद पुरस्कार ठुकरा दिया. सुलभ के पुरस्कार ठुकराने के बाद चयन पर ही सवाल खड़े होने लगे. संस्कृति कर्मियों ने इस पुरस्कार के ऐलान के बाद इसके ख़िलाफ़ हस्ताक्षर अभियान चला रखा है. बिहार के रंगकर्मी कला पुरस्कारों में हुई धांधली के आरोपों की जांच की मांग कर रहे हैं. कला पुरस्कारों की चयन समिति में भी आलोक धन्वा, ऊषा किरण खान हैं. उनके अलावा परवेज अख्तर और आनंदी बादल हैं.

कला पुरस्कारों के चयन पर उठे विवादों की पृष्ठभूमि बहुत दिलचस्प है. निर्णायक मंडल ने नियमों को शिथिल करते हुए रेवड़ियां बांटने का फ़ैसला लिया. बिहार के कला पुरस्कारों के चयन का नियम यह है कि रंगकर्मी या कलाकार अपने बॉयोडाटा के साथ आवेदन करते हैं और उस आवेदन के साथ अनुशंसाएं भी नत्थी करते हैं. कला पुरस्कार की चयन समिति के सदस्य उन आवेदनों पर विचार करते हैं और फिर उनमें से नामों का चयन होता है. इस बार इन नियमों को दरकिनार कर पुरस्कार देने की बातें सामने आई हैं. कला पुरस्कार ठुकराते हुए हृषिकेश सुलभ ने लिखा, बिहार में कला–संस्कृति और राजभाषा विभागों के पुरस्कारों का बंटवारा दिनोंदिन अश्लील होता जा रहा है. बिहार में सरकारें हमेशा संस्कृति और साहित्य को लेकर असंवेदनशील रही हैं. सरकार को चाहिए कि वह रेवड़ियां बांटना बंद करे. सुलभ ने आगे लिखा, मैंने न तो इस पुरस्कार के लिए आवेदन किया था और न अपना बॉयोडाटा भेजा था. सरकार को पुरस्कार घोषित करने से पहले मुझसे स्वीकृति लेनी चाहिए थी. बहुत संभव है कि चयन समिति को योग्य लोगों के आवेदन न मिले हों, लेकिन क्या पुरस्कार देना इतना ज़रूरी था?

इसी तरह की गड़बड़ी रंगकर्मी अनीश अंकुर के साथ की गई. उनके नाम का ऐलान जूनियर पुरस्कार के लिए कर दिया गया, जबकि उनकी उम्र ज़्यादा है. यह कलाकारों का अपमान भी है. चयन समिति के सदस्य पुरस्कारों को अपनी ज़मींदारी की तरह चलाते प्रतीत होते हैं और पुरस्कारों को खैरात की तरह बांटते. यह सामंती मानसिकता है. फिल्मों की समीक्षा पर दिए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए भी आवेदन मंगाए जाते हैं. वहां कभी ऐसा नहीं होता है कि नियमों में ढील देकर किसी को पुरस्कृत कर दिया जाए. अगर श्याम बेनेगल ने भी आवेदन न किया हो, तो उन्हें पुरस्कार नहीं दिया जाता है. फिर बिहार के कला पुरस्कारों में नियमों को शिथिल कर लेखकों–कलाकारों को अपमानित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हो सकता है कि नियमों में यह प्रावधान हो कि स्तरीय आवेदन न मिलने पर निर्णायक समिति की अनुशंसा को मानते हुए पुरस्कारों के लिए नामों का ऐलान हो. अगर ऐसा है, तो यह बात साफ़ होनी चाहिए कि जिन्होंने आवेदन किया था, उनके नाम स्तरीय नहीं थे. किस आधार पर उनके आवेदन को खारिज किया गया? सामने तो वे परिस्थितियां भी आनी चाहिए, जिसमें चयन समिति के चारों सदस्यों में से किसने किसके नाम की सिफारिश की और सब उस पर एकमत हो गए?

दरअसल, बिहार के वर्तमान साहित्यिक परिदृश्य में सरकारी विभागों में जबरदस्त अराजकता है. मुख्यमंत्री की प्राथमिकता सूची में साहित्य–संस्कृति नहीं है, क्योंकि इनका कोई वोट बैंक होता नहीं है. लेकिन, नीतीश कुमार जैसे समझदार नेता शायद यह भूल गए हैं कि इन चीजों से परसेप्शन बनता है. परसेप्शन की इस दौड़ में वह पिछड़ते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि साहित्य और संस्कृति की कमान उन्होंने जिन दो–तीन नामों के हाथों में सौप रखी है, वे अपनी भूमिका के निर्वहन में लगातार नाकाम होते नज़र आ रहे हैं और चुनाव की आहट ने उन्हें बेलगाम भी कर दिया है. बिहार के इन साहित्यिक हकीमों को इस बात का अंदाज़ है कि नीतीश कुमार इन दिनों अपनी खोई सियासी ज़मीन वापस हासिल करने में जुटे हैं. लिहाजा ये हकीम अपनी मनमानी करके नीतीश को नुक़सान पहुंचाने में जुटे हुए हैं. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

रिश्तों की सोंधी खुशबू

महेंद्र अवधेश

वरिष्ठ पत्रकार संजय सिन्हा की नवीनतम कृति–रिश्ते पर कोई बात करने से पहले वरिष्ठ कवि एवं गीतकार प्रमोद तिवारी के एक गीत की दो पंक्तियां प्रस्तुत हैं– राहों में भी रिश्ते बन जाते हैं, वे रिश्ते मंजिल तक भी जाते हैं. हम उन रिश्तों की फेरी सिर पर रखकर, गलियों–गलियों आवाज़ लगाते हैं...सच है, सिर्फ़ खून के रिश्ते ही रिश्ते नहीं होते. रिश्ते कहीं भी बन सकते हैं, किसी से भी बन सकते हैं, किसी स्तर तक बन सकते हैं. रिश्तों की कोई सीमा नहीं है, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं. रिश्ते सिर्फ़ अपनापन चाहते हैं, ईमानदारी चाहते हैं, साफ़गोई चाहते हैं. रिश्तों की इमारत इसी गारे से तैयार होती है. हमारा, आपका, सबका जीवन रिश्तों पर ही टिका है. बिना रिश्ते हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते.

अपनी कृति–रिश्ते में संजय सिन्हा ने आभासी दुनिया समेत जीवन के विभिन्न रिश्तों पर अपनी कलम चलाई है. फेसबुक के माध्यम से जुड़ने वाले दोस्तों, वरिष्ठों एवं कनिष्ठों के रिश्ते संजय को किस हद तक प्रभावित करते हैं, किस तरह संजय उन्हें जीते हैं और वे सारे रिश्ते उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, आदि बिंदुओं पर उनके बेबाक लेखन का नतीजा है–रिश्ते. संजय बताते हैं कि रिश्तों का उनका यह संसार कैसे बना, कौन इसके लिए उनका प्रेरक बना. कौन–से रिश्ते ने क्या सबक दिया, क्या संदेश दिया और वह सबक–संदेश कितने लोगों से जाकर जुड़ता है, इसे बहुत ही सहज तरीके से पाठकों के सामने रखने में वह सफल रहे हैं. किसी शैली विशेष, किसी सजावट और किसी भूमिका के बिना उन्होंने बड़ी से बड़ी घटना को छोटी–छोटी कहानियों के ज़रिये प्रस्तुत कर पाठकों तक उसका पूरा निचोड़ पहुंचाने का प्रयास किया. उनकी यह खूबी बताती है कि वह किसी के लिए भी लिख सकते हैं यानी कोई भी उनका लिखा हुआ पढ़ सकता है, समझ सकता है. यही किसी लेखन की सार्थकता है और लेखक की सफलता भी.

कृति–रिश्ते में छोटी–छोटी कहानियों में सिमटी बड़ी–बड़ी अर्थपूर्ण घटनाओं की एक लंबी फेहरिस्त है. सबका ज़िक्र तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ के बारे में यहां कहना–बताना ज़रूरी है. एक घटना के अंतर्गत लेखक ने बताया कि अभिनेता शाहरुख खान दिल्ली आने पर अपनी मां से मिलने ज़रूर जाते हैं, उनकी मजार पर और वह भी देर रात. वजह, दिन में उन्हें प्रशंसकों से घिर जाने का डर रहता है. उस दिन भी शाहरुख रात के ढाई बजे घने कोहरे और कड़ाके की ठंड में अपनी मां से मिलने गए, उनकी मजार पर.

कृति–रिश्ते में छोटी–छोटी कहानियों में सिमटी बड़ी–बड़ी अर्थपूर्ण घटनाओं की एक लंबी फेहरिस्त है. सबका ज़िक्र तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ के बारे में यहां कहना–बताना ज़रूरी है. एक घटना के अंतर्गत लेखक ने बताया कि अभिनेता शाहरुख खान दिल्ली आने पर अपनी मां से मिलने ज़रूर जाते हैं, उनकी मजार पर और वह भी देर रात. वजह, दिन में उन्हें प्रशंसकों से घिर जाने का डर रहता है. उस दिन भी शाहरुख रात के ढाई बजे घने कोहरे और कड़ाके की ठंड में अपनी मां से मिलने गए, उनकी मजार पर. सच है, मां से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता इस संसार में...रिश्ता क्या, मां से बड़ा कुछ भी नहीं होता. शाहरुख का एक और किस्सा. बकौल लेखक, आमिर खान जब दिल्ली आते हैं, तो सखा नामक टैक्सी की सेवा लेते हैं, तड़क–भड़क से बहुत दूर रहकर वह दिल्ली का अंदरूनी सफर तय करते हैं. वहीं शाहरुख को बड़ी–महंगी गाड़ियों का शौक है. संयोग से दोनों साथ दिल्ली आए, तो शाहरुख ने आमिर की खातिर सखा में सफर किया होटल तक.

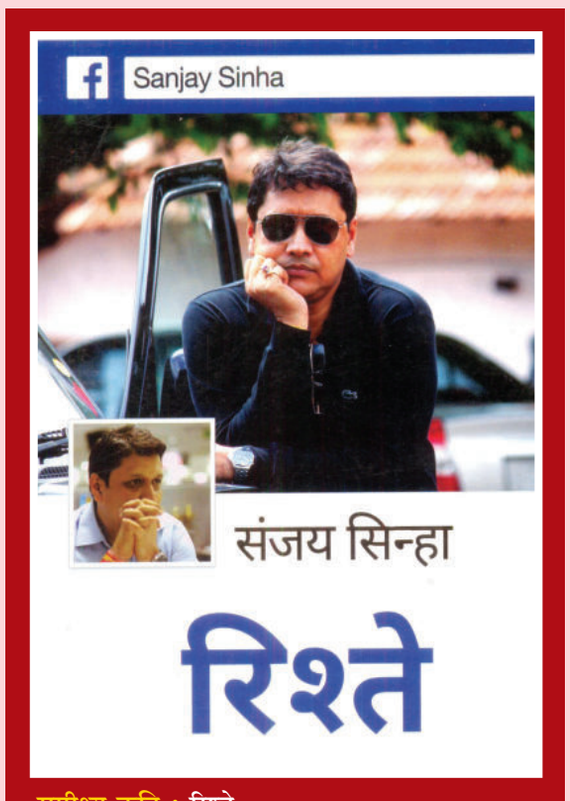

समीक्ष्य कृति : रिश्ते
लेखक : संजय सिन्हा
प्रकाशक : प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली
मूल्य : 245 रुपये

ख़बरों की दुनिया में एक लंबा समय व्यतीत कर चुके संजय सिन्हा इस पेशे से जुड़े लोगों की दिक्कतों, द्वंद्वों से भलीभांति परिचित हैं. अपनी कृति–रिश्ते में लेखक ने अपने दफ्तर में काम करने वाले कई लोगों के जीवन से जुड़े वाकए बयान किए, जो कहीं न कहीं हम सबके जीवन में कभी न कभी देखने को मिले होंगे अथवा मिल सकते हैं. कई सहकर्मियों की दिक्कतों ने संजय को बहुत झकझोरा और नतीजा यह हुआ कि वह खुद भी उन दिक्कतों से न केवल जुड़े, बल्कि उन्होंने उनका सुखद समाधान भी खोजा. ऐसी कई घटनाओं का ज़िक्र है, जिनके संदेश, जिनके सबक हमारे–आपके बहुत काम आ सकते हैं. उम्मीद है, संजय सिन्हा की यह श्रेष्ठ कृति पाठकों को रिश्तों के असीम संसार में ले जाएगी और उन्हें रिश्तों को समझने में मदद करेगी. ■

mahendra.awdhesh@gmail.com

कंपनी ने स्क्रैम्बलर रेंज में 4 अलग–अलग बाइक स्क्रैंबलर आईकॉन, स्क्रैंबलर अरबन एन्दुरो, स्क्रैंबलर फुल थ्रोत्तले और स्क्रैंबलर क्लासिक को लॉन्च किया था. डुकाटी इंडिया ने इस रेंज में सबसे सस्ती बाइक स्क्रैंबलर आईकॉन की प्रीबुकिंग शुरू कर दी है. बाइक की बुकिंग 50 हजार रुपये में शुरू की गई है.

ऑडी की स्पोर्ट्स कार टीटी का नया मॉडल

जर्मनी की लग्जरी कार निर्माता ऑडी ने अपनी स्पोर्ट्स कार ऑडी टीटी का नया मॉडल लॉन्च किया है. कंपनी भारत के लग्जरी कार बाजार में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखने की कोशिश में है. नई तकनीक से लैस नई ऑडी टीटी को कंपनी सिर्फ एक पेट्रोल इंजन के साथ उतारा है. जो 4 सिलेंडर वाला 2 लीटर का इंजन है. महज 5.3 सेकेंड में यह 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है. इसका अधिकतम स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा है. इसकी स्टीयरिंग व्हील मल्टीफंक्शनल होगी. एलॉय व्हील के साथ कंपनी ने इसमें एलईडी हेडलैंप, एमएमआई टच इंटरफेस, ऑडी वर्चुअल कॉकपिट, स्पीड लिमिट फंक्शन के साथ क्रूज कंट्रोल, ऑडी ड्राइव सेलेक्ट, लेदर की सजावट, टरबाइन जैसा एयरकंडीशनर सुराख, कंट्रोल नॉब पर डिजिटल डिस्प्ले, ब्लूटुथ कनेक्टिविटी और 2एसडी कार्ड रिडर्स के साथ ऑडी साउंड सिस्टम इत्यादि की सुविधा है. इसके साथ ही एलईडी मेट्रिक्स हेडलैंप भी इसके अन्य फीचर्स में प्रमुख हैं. 4.18 मीटर की यह कार काफी लंबी–चौड़ी है. इसके लगेज कंपार्टमेंट में 305 लीटर तक सामान रखे जाने की क्षमता है. इस कार की कीमत 60.34 लाख रुपये है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

श्याओमी का एमआई 4आई स्मार्टफोन लॉन्च

श्याओमी ने अपना नया स्मार्टफोन एमआई 4आई लॉन्च किया है. इस स्मार्टफोन को ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकता है. यह फोन Mi.com पर भी मिलेगा. इस फोन में एंड्रॉयड 5.0 लॉलीपॉप है. इसमें 64 बिट ओक्टा कोर स्नैपड्रैगन 615 प्रोसेसर है. इसमें 2 जीबी रैम है और यह ड्यूल सिम फोन है. इसमें 4 जी एलटीई कनेक्टिविटी सपोर्ट है. इसमें

5 इंच की फुल एचडी स्क्रीन है. इसका रियर कैमरा 13 मेगापिक्सल है और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है. इसमें 16 जीबी मेमोरी उपलब्ध है. इसमें 6 भारतीय भाषाएं– हिंदी, बंगाली, कन्नड, तेलगू, मलयालम और तमिल की सुविधा दी गई है. यह फोन ब्लैक, व्हाइट, ऑरेंज, लाइट ब्लू और पिंक कलर में मिलेगा. इसकी बैटरी 3120 एमएएच की है. इस फोन की भारत में कीमत 12,999 रुपये है. ■

आपके बजट में 16जीबी स्टोरेज वाली पेन ड्राइव

कम्प्यूटर और लैपटॉप इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को अक्सर पेन ड्राइव की जरूरत होती है. जिससे हम अपने डाटा को एक लैपटॉप या कम्प्यूटर से आसनी से दूसरे लैपटॉप या कम्प्यूटर में ला सकते हैं. मार्केट में 2जीबी, 4जीबी, 8जीबी, 16जीबी, 32जीबी, 64जीबी, 128जीबी और इससे भी ज्यादा स्टोरेज वाली पेन ड्राइव मौजूद हैं. हालांकि, ड्राइव जितनी ज्यादा स्टोरेज वाली होगी, उसकी कीमत भी उतनी अधिक होगी. ऐसे में हम आपको 16जीबी की ऐसी ही पांच पेन ड्राइव के बारे में बता रहे हैं, जो लो बजट हैं और उन्हें ऑनलाइन आसानी से खरीदा भी जा सकता है.

स्ट्रोंटीअम 16जीबी ऐमो

इस स्ट्रोंटीअम ब्रांड की 16जीबी स्टोरेज वाली पेन ड्राइव को ऑनलाइन 438 रुपये में खरीदा जा सकता है. स्टाइलिश लुक वाली ये पेन ड्राइव एक की–चेन की तरह है. ये ड्राइव विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा, विंडो 7, मैक ओएस पर आसानी से काम करती है. पेन ड्राइव में यूएसबी 2.0 पोर्ट है, जिसकी स्पीड औसत होती है. इसकी बॉडी मेटेलिक है, जो सिल्वर कलर में आती है. इस ड्राइव का डायमेंशन 41.8 गुणा 11.2 गुणा 3.4 एमएम है. ■

पीएनव्याई (PNY)

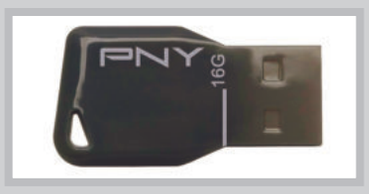

PNY ब्रांड की इस 16जीबी स्टोरेज वाली पेन ड्राइव को ऑनलाइन 473 रुपये में खरीदा जा सकता है. छोटी सी दिखने वाली यह पेन ड्राइव स्टाइलिश लुक में आती है. यह ड्राइव विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा, विंडो 7, मैक जेड पर आसानी से काम करती है. पेन ड्राइव में यूएसबी 2.0 पोर्ट है, जिसकी स्पीड औसत होती है. ये 24 MB/s से रीड और 8 MB/s से राइट करती है. इसकी बॉडी मेटेलिक है, जो ग्रे कलर में है. साथ ही, ये वाटर रिजिस्टेंट रेजिस्टेंट भी है. इसका डायमेंशन 24.2 गुणा 12.3 गुणा 4.6 एमएम है. इसका वजन 2.8 ग्राम है. ■

सेनडिस्क

सेनडिस्क ब्रांड की इस 16जीबी स्टोरेज वाली पेन ड्राइव को ऑनलाइन 381 रुपये में खरीदा जा सकता है. सेनडिस्क ब्रांड की ये पेन ड्राइव विंडो 2000, विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा, विंडो 7, मैक ओएस पर आसानी से काम करती है. पेन ड्राइव में यूएसबी 2.0 पोर्ट है, जिसकी स्पीड औसत होती है. इसकी बॉडी मेटेलिक है, जो ब्लैक और रेड कॉम्बिनेशन में आती है. ये 4 सेंमी लंबी है, जिसका वजन 2.50 ग्राम है. ■

एचपी

एचपी ब्रांड की इस 16जीबी स्टोरेज वाली पेन ड्राइव को ऑनलाइन 489 रुपये में खरीदा जा सकता है. एचपी ब्रांड की ये पेन ड्राइव स्टाइलिश लुक में है. मेटेलिक बॉडी वाली ये ड्राइव गोल्ड–ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन में आती है. ये विंडो 2000, विंडो एक्पी, विंडो विस्टा, विंडो 7, मैक ओएस पर आसानी से काम करती है. इस ड्राइव में यूएसबी 2.0 पोर्ट है, जिसकी स्पीड औसत होती है. ये वाटरप्रूफ ड्राइव है, जिसका डायमेंशन 42.4 गुणा 17.6 गुणा 7 एमएम है. वहीं इसका वजन 4.4 ग्राम है. ■

मोजरबियर स्विवल

मोजरबियर ब्रांड की इ 16 जीबी वाली पेन ड्राइव को ऑनलाइन 499 रुपये में खरीदा जा सकता है. ये पेन ड्राइव लेड इंडिकेटर के साथ आती है. प्लास्टिक बॉडी वाले ये ड्राइव व्हाइट–रेड कलर काम्बिनेशन में आती है. ये विंडो 2000, विंडो एक्पी, विंडो विस्टा, विंडो 7, मैक ओएस पर आसानी से काम करती है. इस ड्राइव में यूएसबी 2.0 पोर्ट है. ये 20 MB/s से रीड और 8MB/s से राइट करती है. डायमेंशन 57 गुणा 21 गुणा 11 एमएम है. ■

डुकाटी स्क्रैंबलर बाइक की बुकिंग शुरू

इटली की बाइक कंपनी डुकाटी ने 2014 इंटरमोट कलोन शो के दौरान अपनी नई रेंज स्क्रैम्बलर को पेश किया था. कंपनी ने स्क्रैम्बलर रेंज में 4 अलग–अलग बाइक स्क्रैंबलर आईकॉन, स्क्रैंबलर अरबन एन्दुरो, स्क्रैंबलर फुल थ्रोत्तले और स्क्रैंबलर क्लासिक को लॉन्च किया था. डुकाटी इंडिया ने इस रेंज में सबसे सस्ती बाइक स्क्रैंबलर आईकॉन की प्रीबुकिंग शुरू कर दी है. बाइक की बुकिंग 50 हजार रुपये में शुरू की गई है. यह सिर्फ रेड कलर में उपलब्ध होगी. डुकाटी स्क्रैंबलर 803 सीसी, एयरकूल्ड, एल ट्विन इंजन पर दौड़ती है. यह 75 बीएचपी की अधिकतम पावर देती है. इसमें 6 स्पीड गियरबॉक्स का इस्तेमाल किया गया है. इसकी कीमत लगभग 6.67 लाख रुपये है. ■

डुकाटी इंडिया ने इस रेंज में सबसे सस्ती बाइक स्क्रैंबलर आईकॉन की प्रीबुकिंग शुरू कर दी है. बाइक की बुकिंग 50 हजार रुपये में शुरू की गई है. यह सिर्फ रेड कलर में उपलब्ध होगी. डुकाटी स्क्रैंबलर 803 सीसी, एयरकूल्ड, एल ट्विन इंजन पर दौड़ती है.

आईसीएल 2.0 की तैयारियां शुरू!

आईसीएल(इंडियन क्रिकेट लीग) के आयोजक एक और विद्रोही क्रिकेट लीग लाने की तैयारी में हैं. इस बार इसका नया अवतार लोगों के सामने आ सकता है. एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के अनुसार सुभाष चंद्रा का एसेल ग्रुप एक बार फिर क्रिकेट की ओर रुख कर सकता है. इस दिशा में एक कदम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आईसीसी के अन्य सदस्य देशों में कंपनियां रजिस्टर्ड करना है. आईपीएल आईसीएल के फॉर्मेट की हूबहू कॉपी है. बीसीसीआई के पूर्व अधिकारी ललित मोदी ने भी कहा था कि वे ऐसेल ग्रुप के इस कदम से डर गए थे. यह खबरें भी आ रही हैं कि आईपीएल के पूर्व प्रमुख ललित मोदी को नई लीग के आयोजन की जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन बाद में इस बात का खंडन कर दिया गया. जब कंपनी के अधिकारियों से इस बारे में जानकारी मांगी गई तो उन्होंने कंपनी रजिस्टर करने की बात को सही बताया और कहा कि सब कुछ अभी बिलकुल शुरूआती दौर में है. लेकिन जैसे ही इसका कोई स्वरूप बनेगा तो निश्चित तौर पर यह जानकारी साझा की जायेगी. आयोजन की तैयारियों से जुड़े लोगों का कहना है कि उन्हें आईसीएल के अनुभव का निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा, पिछले अनुभवों से हमें बेहतर तैयारी करने की मदद मिलेगी. अब हमें मालूम है कि अपनी रक्षा और बचाव कैसे करना है.. ■

feedback@chauthiduniya.com

क्रिस रिकॉर्ड गेल

कुछ दिन पहले ही गेल ने आईपीएल में 200 छक्के पूरे किये थे. गेल अब तक 201 टी-20 मैच खेल चुके हैं. इस दौरान उन्होंने 4896 गेंदों का सामना किया और 7194 रन बनाए हैं. उनका औसत 42.07 का है. टी-20 क्रिकेट की सबसे लंबी पारी (175) का रिकॉर्ड भी गेल के ही नाम दर्ज है.*

जब से टी–20 क्रिकेट खेली जाने लगी है, तब से क्रिस गेल और रिकॉर्ड्स का एक अनोखा रिश्ता बन गया है. वह जितनी आसानी से मैदान पर चौके–छक्के लगाते हैं. वह उतनी ही आसानी से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के रिकॉर्ड भी बनाते जाते हैं. वेस्टइंडीज के विध्वंसक बल्लेबाज गेल ने टी–20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के मारने का अनोखा रिकॉर्ड कायम किया है. उनके नाम अब टी–20 क्रिकेट में 500 छक्के दर्ज हो गए हैं. आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुक़ाबले में गेल के बल्ले का जादू नहीं चल सका लेकिन छोटी सी पारी में उनके नाम 500 छक्के जड़ने का अनोखा रिकॉर्ड दर्ज हो गया. गेल ने यह उपलब्धि करियर के 201 वें टी–20 मैच में हासिल की है. गेल के बाद टी–20 मैचों में सबसे ज्यादा छक्के वेस्टइंडीज के ही कीरॉन पोलार्ड के नाम दर्ज हैं. उन्होंने अब तक 348 छक्के लगाये हैं. कुछ दिन पहले ही गेल ने आईपीएल में 200 छक्के पूरे किये थे. गेल अब तक 201 टी–20 मैच खेल चुके हैं. इस दौरान उन्होंने 4896 गेंदों का सामना किया और 7194 रन बनाए हैं. उनका औसत 42.07 का है. टी–20 क्रिकेट की सबसे लंबी पारी (175*) का रिकॉर्ड भी गेल के ही नाम दर्ज है. वह टी–20 में 569 चौके भी लगा चुके हैं.वह टी–20 में अब तक 13 शतक और 47 अर्धशतक लगा चुके हैं. ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है.■

भारतीय फुटबॉलर ने इतिहास रचा

इंडियन सुपर लीग(आईएसएल) में जलवा बिखेर चुके पंजाब के युवा फुटबॉलर गुरप्रीत सिंह संधू ने टॉप यूरोपीय फुटबॉल क्लब की ओर से मैच खेलकर नया इतिहास रच दिया है. इससे पहले कोई भी भारतीय फुटबॉलर शीर्ष यूरोपीय क्लब की ओर से प्रतिस्पर्धी फुटबॉल नहीं खेल सका था. नॉर्वे के फुटबॉल क्लब स्टेबीक की ओर से गुरप्रीत ने अपना पहला मैच खेलकर इतिहास बदल दिया है. उन्होंने पिछले साल स्टेबीक के साथ करार किया था, उन्हें आइवरी कोस्ट के गोलकीपर सेयुम्बा मांदे की जगह क्लब में शामिल किया गया था. लेकिन वह एक भी मैच नहीं खेल सके थे. 23 वर्षीय गुरप्रीत ने नॉर्वे के क्लब रुनार के खिलाफ अपना डेब्यू मैच खेला. इसके बाद गुरप्रीत ने कहा कि मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं मांग सकता. मैं खुश हूं कि मेरे कोच(बॉब ब्रेडल) और गोलकीपिंग कोच(एस्प्रेन ग्रानली)ने मुझ पर भरोसा जताया. गुरप्रीत पिछले साल ईस्ट बंगाल क्लब से स्टेबीक गये थे. गौरतलब है कि गुरप्रीत से पहले मोहम्मद सलीम, बाइचुंग भूटिया, सुनील छेत्री और सुब्रतो पॉल ने यूरोपियन टीमों की ओर से खेलने की कोशिश की थी लेकिन इनमें से गुरप्रीत के अलावा अन्य कोई अपनी जगह बनाने में सफल नहीं हो सका. छह फीट छह इंच लंबे इस भारतीय खिलाड़ी का कद भारतीय फुटबॉल में अब और ज्यादा ऊंचा हो गया है.■

मेसी का नया धमाका

फुटबॉल के सुपर स्टार लियोनल मेसी ने अपने फुटबाल करियर में एक और मील का पत्थर पार कर लिया है. उन्होंने ला–लीगा में बार्सिलोना क्लब के लिए अपना 400 वां गोल किया. उनके बेहतरीन गोल की बदौलत बार्सिलोना ने वैलेंसिया को 2–0 के अंतर से पराजित किया. यह मेसी का बार्सिलोना के लिए 471 वां मैच था. यह ला–लीगा में उनका 278 वां गोल था. चैंपियंस लीग में मेसी बार्सिलोना की ओर से 75 गोल कर चुके हैं. जबकि इस सीजन में मेसी 46 मैचों में 46 गोल कर चुके हैं. कुछ समय पहले मेसी ने स्पेनिश क्लब के खिलाड़ी द्वारा सभी प्रतियोगिताओं में सबसे ज्यादा हैट्रिक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया. यह रिकॉर्ड पहले टेल्मो जारा के नाम दर्ज था. इसके अलावा वर्तमान सीजन में ला–लीगा में सबसे ज्यादा हैट्रिक के क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रिकार्ड को तोड़कर मेसी ने नया रिकॉर्ड कायम किया है. उनके नाम ला लीगा में 24 हैट्रिक हैं. जबकि बार्सिलोना के लिए कुल 32 हैट्रिक उन्होंने लगाई हैं.■

मेसी के 400 गोल

ला–लीगा	278
चैंपियंस लीग	75
स्पेनिश कप	32
स्पेनिश सुपर कप	10
यूरोपियन सुपर कप	01
क्लब वर्ल्ड कप	04

भारत नहीं करेगा 2024 ओलंपिक का दावा

कयास लगाये जा रहे थे कि भारत साल 2024 के ओलंपिक के आयोजन के लिए अपनी दावेदारी पेश करेगा. लेकिन अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई मुलाकात के बाद यह स्पष्ट हो गया कि भारत ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए फिलहाल अपनी दावेदारी पेश नहीं करेगा. पहले ऐसी खबरें आ रहीं थीं कि भारत ओलंपिक की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश करेगा और अहमदाबाद मुख्य मेजबान शहर होगा. हालांकि, इस संबंध में भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) या खेल मंत्रालय की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया था. ऐसा कहा जा रहा था कि बाक और मोदी की मुलाकात के बाद ही इस बारे में कुछ भी साफ तौर पर कहा जा सकेगा. आईओए अधिकारियों और मोदी से मुलाकात के दौरान बाक ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की. इसमें मेजबानी की दावेदारी और ओलंपिक में शामिल खेलों के विकास लिए भारत को और अधिक धन देने से जुड़ा मुद्दा प्रमुख है. गौरतलब हो कि, साल 2020 में ओलंपिक खेल जापान में होना है. वर्ष 1960 के बाद से ओलंपिक खेल लगातार एक ही महाद्वीप में आयोजित नहीं हुए हैं. बावजूद इसके भारत द्वारा ओलंपिक खेलों की मेजबानी की दावेदारी की बातें सामने आ रही थीं. खेल सचिव (भारत सरकार) अजित शरण इसकी पुष्टि की थी कि आईओए प्रमुख नारायण रामचंद्रन और शरण इस साल स्विटजरलैंड के लुसाने स्थित आईओसी के मुख्यालय गए थे और वहां आईओसी प्रमुख से मुलाकात की थी. बाक के भारत दौरे को लेकर आईओए प्रमुख ने राज्य ओलंपिक संघों के नाम जो पत्र जारी किया था, उसमें भी भारत द्वारा ओलंपिक की मेजबानी की दावा किए जाने का कोई जिक्र नहीं था. इसमें इतना जरूर कहा गया था कि बाक 27 अप्रैल को जब भारत आएंगे, तब वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर भारत में ओलंपिक स्पर्धाओं के विकास को लेकर चर्चा करेंगे. उल्लेखनीय है कि ओलंपिक चार्टर में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि ओलंपिक के दो संस्करण लगातार एक ही महाद्वीप में आयोजित नहीं हो सकते हैं,लेकिन आईओसी 1960 के रोम ओलंपिक के बाद से यह सुनिश्चित करता आया है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन अलग–अलग महाद्वीपों में हो.■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

स्टारडम से दूर अरशद वारसी

अरशद को राजकुमार हीरानी की सुपरहिट फिल्म पीके में काम करने का ऑफर मिला था, लेकिन उस वक्त वह डेढ़ इश्किया की शूटिंग में व्यस्त थे. हालांकि उन्हें पीके छोड़ने का अफसोस है लेकिन उस वक्त डेढ़ इश्किया की शूटिंग की वजह से पीके में काम करना उनके लिए संभव नहीं था. लेकिन उन्होंने राजकुमार हीरानी की मुन्नाभाई सीरीज की अगली फिल्म के लिए पहले से ही वक्त निकाल रखा है

अभिनेता अरशद वारसी स्टारडम से धीरे–धीरे दूर होते जा रहे हैं. इन दिनों वह गुड्डू रंगीला, वेलकम टू कराची, द लीजेंड ऑफ माइकल मिश्रा, जैसी कई फिल्मों में काम कर रहे हैं, बावजूद इसके वह सुर्खियों से कोसों दूर हैं. माना जा रहा है कि बड़ी फिल्मों को ज्यादा तवज्जो न देने की वजह से उनके हाथ से स्टारडम फिसलती जा रही है. अरशद को मल्टी स्टारर फिल्मों में बहुत वाहवाही मिल रही है. उन्होंने गोलमाल, डबल धमाल, हलचल, जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया. इसके बाद उन्होंने कुछ अलग हट के फिल्मों में काम करने का मन बनाया. जॉली–एलएलबी इस राह का पहला मील का पत्थर साबित हुई. अरशद को राजकुमार हीरानी की सुपरहिट फिल्म पीके में काम करने का ऑफर मिला था, लेकिन उस वक्त वह डेढ़ इश्किया की शूटिंग में व्यस्त थे. हालांकि उन्हें पीके छोड़ने का अफसोस है लेकिन उस वक्त डेढ़ इश्किया की शूटिंग की वजह से पीके में काम करना उनके लिए संभव नहीं था. लेकिन उन्होंने राजकुमार हीरानी की मुन्नाभाई सीरीज की अगली फिल्म के लिए पहले से ही वक्त निकाल रखा है.

अरशद की पहचान फिल्म इंडस्ट्री के उन कलाकारों में है जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर फिल्म जगत में एक अलग पहचान बनाई है. वह उन कलाकारों में से हैं जिन्होंने फिल्म जगत में पिछले दरवाजे से एंट्री नहीं की है. बहुत कम लोगों को यह मालूम नहीं है कि अरशद एक ट्रेंड डांसर हैं. उन्होंने डांस के कई अवार्ड भी जीते हैं. इसके साथ ही उन्होंने डांस स्कूल भी चलाया है. अरशद लंबे समय तक थियेटर से भी जुड़े रहे हैं. वह आज जो कुछ भी हैं अपनी मेहनत के बल पर हैं. अरशद का मानना है कि आगे बढने के लिए आपको प्रचार का उतना ही सहारा लेना चाहिए जितना जरूरी हो. ऐसे भी वह पूछने पर सिर्फ अपने काम के बारे में बात करते हैं.

यदि उनके अच्छ काम की तारीफ होती है तो वह अपनी खराब फिल्मों के लिए हुई आलोचना का भी सामना करते हैं.इस पर अरशद का कहना है कि मेरी कई फिल्मों को प्रशंसकों ने सिरे से खारिज कर दिया. बावजूद इसके मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा. लेकिन मेरे जैसे छोटे कलाकार के लिए अपने प्रशंसकों को यह बताना जरूरी होता है कि मैं फिलहाल में क्या कर रहा हूं. मेरी मुश्किल यह है कि मैं दो टूक कहता हूं, जो कई लोगों को पसंद नहीं आता है. मैं बड़े कलाकारों के काम की और उनके इंडस्ट्री के प्रति व्यवहार की खुलकर आलोचना करता हूं.■

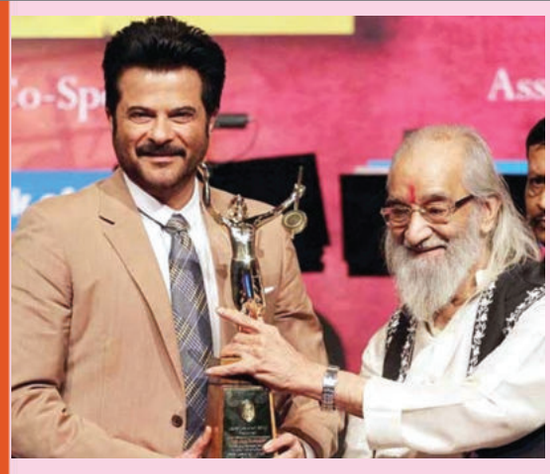

अनिल कपूर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित

जाने–माने कलाकार अनिल कपूर को प्रतिष्ठित दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. यह पुरस्कार हर साल मशहूर गायिका लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर की याद में दिया जाता है. यह पुरस्कार किसी कलाकार अथवा अपने क्षेत्र के किसी सम्मानित व्यक्ति को दिया जाता है. इस सम्मान को पाकर अनिल कपूर काफी खुश हैं. उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्राप्त कर और महाराष्ट्र के सीएम देवेन्द्र फडणवीस से मुलाकात कर धन्य हूं. इस समारोह में अनिल कपूर की पत्नी और बेटी सोनम कपूर भी मौजूद थीं. यह पुरस्कार का 73 वां संस्करण है. अनिल कपूर के अलावा मराठी अभिनेता दिलीप प्रभाकर को भी सम्मनित किया गया है. अनिल कपूर को उनकी जिंदादिली के लिए जाना जाता है. वह इन दिनों जोया अख्तर की फिल्म दिल धड़कनें दो की शूटिंग में व्यस्त हैं. अनिल इस फिल्म को लेकर खासा उत्साहित हैं. फिल्म में अनिल के अलावा प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा, फरहान अख्तर, रणवीर सिंह और शेफाली शाह मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म में एक पंजाबी परिवार की कहानी है. इसके अलावा अनिल अंतरराष्ट्रीय वयस्क एनिमेशन टीवी शो फैमिली गाइ में अतिथि भूमिका की डबिंग कर रहे हैं. अनिल अपनी इस भूमिका को लेकर भी बेहद रोमांचित हैं. यह शो ग्रिफिन परिवार के ईद–गिर्द घूमता है. इससे पहले भी अनिल स्लमडॉग मिलिनेयर और मिशन इंपॉसिबल जैसी अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं में काम कर चुके हैं.■

सपोर्टिंग एक्टर के रूप में काम करके खुश हैं जिमी शेरगिल

फिल्म अभिनेता जिमी शेरगिल का कहना है कि यदि उन्हें एक सपोर्टिंग एक्टर के रूप में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है, तो उन्हें इस तरह की भूमिकाएं करने में खुशी होती है. जिमी ने कहा, मुझे अच्छी सहायक भूमिकाएं मिल रही हैं, इसलिए मैं कर रहा हूं. आजकल एक नायक वाली फिल्में भला कौन कर रहा है? अब हर फिल्म में दो से तीन मुख्य किरदार होते हैं. बॉलीवुड में बहुत सी चीजें बदल चुकी हैं. मोहब्बतें, यहां, लगे रहो मुन्नाभाई, अ वेडनेसडे जैसी सफल फिल्मों में काम कर चुके जिमी ने कहा कि, जब मैं सहायक भूमिकाओं के माध्यम से भी अपनी प्रतिभा दिखा सकता हूं, तो वो भूमिकायें क्यों न करूं? मुझे अच्छी और सशक्त भूमिकाएं मिल रही हैं. मैं यह नहीं देखता कि यह मुख्य भूमिका है या कुछ और. जिमी जल्द ही निर्देशक आनंद एल. राय की आने वाली फिल्म तनु वेड्स मनु रिर्टन्स में कंगना रनौत और आर. माधवन के साथ दिखाई देंगे. तनु वेड्स मनु रिटर्न्स में काम करने की वजह पर जिमी ने बताया कि लोग तनु वेड्स मनु के मेरे किरदार को आज भी याद करते हैं. यह उस फिल्म की अगली कड़ी है. सिर्फ सीक्वल बनाने के लिहाज से यह फिल्म नहीं बनाई गई है. मैं इस फिल्म में अपनी भूमिका से पूरी तरह संतुष्ट हूं. फिल्म में अभिनेत्री कंगना रनौत डबल रोल में हैं.■

मैरीकॉम सर्वश्रेष्ठ फिल्म

बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपडा अभिनीत फिल्म मैरीकॉम को स्वीडन के स्टॉकहोम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जूनियर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है. फिल्म का निर्देशन उमंग कुमार ने किया है. ओलिंपिक पदक विजेता भारतीय महिला मुक्केबाज मैरीकाम के जीवन पर आधारित इस फिल्म को महोत्सव का सर्वोच्च ब्रांज होर्स अवार्ड मिला.

इस फिल्म में प्रियंका की एक्टिंग की खूब तारीफ हुई थी. प्रियंका ने इस फिल्म के लिए काफी मेहनत की थी. उमंग ने कहा, फिल्म मैरीकॉम को इस फिल्म फेस्टीवल के लिए चुना गया और हमने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता तथा हमें इस महोत्सव का सर्वोच्च सम्मान दिया गया. ज्यूरी में नौ से 19 साल तक के बच्चे शामिल थे. इस जीत को बड़ा बताते हुए उमंग ने कहा कि फिल्म अगले महीने स्वीडन में भारतीय फिल्म महोत्सव में भी प्रदर्शित होगी. इस फिल्म के लिए बॉक्सर मैरीकॉम ने खुद प्रियंका की तारीफ करते हुए कहा था कि, प्रियंका ने मेरे किरदार को बखूबी निभाया और मुझे मेरे बचपन की याद दिला दी.■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

रणबीर-कैटरीना की शादी!

रणबीर और कटरीना एक दूसरे को लंबे समय से डेट कर रहे हैं ये खबरें सालों से चल रही हैं. सिर्फ इतना ही नहीं दोनों कुछ महीने पहले से लिव इन रिलेशनशिप में भी रह रहे हैं. हालांकि, कैटरीना और रणबीर दोनों ही इस रिलेशनशिप को स्वीकार करने से हिचकते रहे हैं. बीच में रणबीर और कैटरीना की सगाई की खबरें भी आईं थीं, कि दोनों ने 30 दिसंबर, 2014 को लंदन में सगाई कर ली.

बॉलीवुड के मोस्ट पॉपुलर लव बड्र्स रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ के फैंस के लिए एक अच्छी खबर है. ऐसे तो रणबीर और कटरीना की शादी को लेकर हमेशा से ही तरह–तरह की बातें सामने आती रही हैं लेकिन अब कहा जा रहा है कि दोनों इस साल नवंबर में शादी के बंधन में बंध सकते हैं. गौरतलब है कि रणबीर और कटरीना एक दूसरे को लंबे समय से डेट कर रहे हैं ये खबरें सालों से चल रही हैं. सिर्फ इतना ही नहीं दोनों कुछ महीने पहले से लिव इन रिलेशनशिप में भी रह रहे हैं. हालांकि, कैटरीना और रणबीर दोनों ही इस रिलेशनशिप को स्वीकार करने से हिचकते रहे हैं. बीच में रणबीर और कैटरीना की सगाई की खबरें भी आईं थीं, कि दोनों ने 30 दिसंबर, 2014 को लंदन में सगाई कर ली. अब देखना यह है कि क्या सच में इस साल के नवंबर में रणबीर–कैटरीना एक दूजे के हो जाएंगे. हांलाकि रणबीर अभी भी मीडिया को अपनी शादी को लेकर अनुमान लगाने से बचने को कह रहे हैं. रणबीर ने कहा कि वह अपनी शादी को छिपाकर नहीं रखेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि वह प्यार में हैं और अपनी जिम्मेदारी महसूस कर रहे हैं. जब उनकी शादी की अटकलें लगाई जाती हैं तो यह काफी मजेदार होता है क्योंकि वह खुद इस स्थिति का मजा लेना चाहते हैं. लेकिन फिलहाल उनकी शादी करने की कोई योजना नहीं है.■

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

11 मई–17 मई 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड

भूकंप पीड़ितों की मदद में आगे रही सरकार

वैष्णवी वंदना

भूकंप में राहत पहुंचाने और प्रभावित लोगों की मदद करने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार अव्वल रही. उत्तर प्रदेश से पहले नेपाल के लोगों तक मदद पहुंचाने की अखिलेश सरकार चिंता सराहनीय है. भूकंप की खबर मिलते ही प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नेपाल के भूकंप पीडितों की मदद के लिए तत्काल 10 ट्रक मिनरल वाटर, 10 ट्रक बिस्कुट और एक ट्रक दवाएं भेजीं. बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने राहत सामग्री से भरे 28 और ट्रक रवाना किए. इनमें पेयजल से लदे 16 ट्रक, बिस्किट से भरे आठ ट्रक और मैगी एवं दूध से लदे चार ट्रक शामिल थे. इसके अलावा नेपाल में भूकंप प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को बाहर निकालने एवं बचाव राहत कार्य में मदद पहुंचाने के लिये राज्य से 82 बसें भी नेपाल भेजी गईं. इसके अलावा बाद में 18 और बसें नेपाल भेजी गईं. नेपाल और गोरखपुर के बीच बस सेवा भी शुरू कर दी गई और प्रदेश से 45 चिकित्सकों का दल भी नेपाल के भरतपुर मेडिकल कालेज पहुंचकर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि आपदा और संकट की इस घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार और प्रदेश की जनता नेपाल के साथ है. नेपाल के भूकंप पीड़ितों की सहायता का सिलसिला लगातार जारी है, जबकि भूकंप से प्रदेश में भी जान–माल का काफी नुकसान हुआ.

राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर बताया कि जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश में भूकंप से अब तक 13 लोगों की मौत हुई और 88 लोग जख्मी हुए. खबरे लिखने तक की यह संख्या है, जो बढ़ भी सकती है. प्रदेश में छह भवन पूर्ण रूप से एवं 214 भवन आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं. भूकंप से गोरखपुर में तीन लोगों की मौत हुई और 20 लोग जख्मी हुए, संत कबीर नगर में एक व्यक्ति की मौत हुई और सात लोग जख्मी हुए, बाराबंकी में दो लोगों की मृत्यु हुई तथा नौ लोग घायल हुए, कानुपर देहात में एक आदमी की मृत्यु हुई और एक घायल हुआ, कुशीनगर में एक की मौत हुई और चार लोग घायल हुए, श्रावस्ती में एक की मृत्यु हुई और एक घायल हुआ तथा सिद्धार्थनगर में छह व्यक्ति घायल हुए. इसके अतिरिक्त बलरामपुर में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और चार घायल हुए, बदायूं में एक की मौत हुई तथा देवरिया में एक व्यक्ति की मौत हुई और तीन लोग घायल हुए. प्रतापगढ़, वाराणसी, बहराइच में एक–एक व्यक्ति घायल हुए. बस्ती में छह लोग घायल हुए, फतेहपुर में तीन घायल हुए, मऊ में सात लोग घायल हुए, भदोही में तीन लोग घायल हुए, उन्नाव में एक व्यक्ति घायल हुआ, महराजगंज में चार लोग घायल हुए और अमेठी में एक व्यक्ति जख्मी हुआ. सरकार ने बताया कि संत कबीर नगर में एक घर क्षतिग्रस्त हुआ, बलरामपुर में 38 घर, कुशीनगर में आठ, बाराबंकी में तीन, सिद्धार्थनगर में 24, मऊ में सात, अमरोहा में एक, सीतापुर में एक, कानपुर नगर में 10, आजमगढ़ में सात तथा महराजगंज में 27 मकानों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हुई. नेपाल सीमा पर प्रदेश सरकार की तरफ से सोनौली में राहत कैम्प खोला गया. यह राहत कैंप राज्य प्रशासन और एसएसबी के साझा प्रयास से स्थापित किया गया, जहां खाने और रुकने की व्यवस्था की गई. वहां अपर जिलाधिकारी को समन्वय करने के लिए खास तौर पर नियुक्त किया गया, जो नेपाल भेजी जाने वाली सामग्री और वहां से आने वाले भूकम्प पीड़ितों की सहायता और व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं. इसके अलावा गोरखपुर में भी कंट्रोल रूम स्थापित किया गया. राज्य सरकार द्वारा सीमावर्ती जिलों में स्थित सीमा चौकियों पर राहत शिविर स्थापित किए गए, जिनमें जिला प्रशासन की तरफ से खान–पान की उचित व्यवस्था के साथ–साथ जीवनरक्षक दवाइयों और स्थानीय चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है. राहत शिविरों में पहुंचने वाले भूकम्प पीड़ितों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था भी की गई है.

उत्तर प्रदेश से नेपाल गए राहतकर्मियों की मदद से अबतक 106 बसों से छह हजार लोगों को निकाला जा चुका है. 94 अन्य बसें वहां पर फंसे लोगों को वापस ला रही हैं. काठमांडू समेत नेपाल के विभिन्न इलाकों में फंसे आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात एवं कर्नाटक के लगभग एक हजार से अधिक लोगों को गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्थापित राहत शिविर तक पहुंचाया गया. प्रदेश के विभिन्न जिलों से नेपाल भेजी जाने वाली राहत सामग्रियों में गाजीपुर से 100 कुन्तल चावल, महराजगंज से 100 कुन्तल आटा, 50 कुन्तल चावल और 50 कुन्तल दाल और गोरखपुर से 50 कुन्तल चावल, 50 कुन्तल दाल, 100 कुन्तल आटा, 25 हजार कम्बल, 100 डिब्बे बिस्कुट, 600 पैकेट नमकीन, 25 हजार क्लोरीन टैबलेट, 500 टेन्ट एवं तिरपाल, 65 बोरी ब्लीचिंग पाउडर, 25 हजार सैनेटरी पैड सहित राहत सामग्री नेपाल भेजी जा चुकी है.

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नेपाल में कराए जा रहे राहत व बचाव कार्यों के लिए संसाधन बढ़ाने के निर्देश दिए और कहा है कि प्रदेश सरकार की ओर से नेपाल को ज्यादा से ज्यादा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. नेपाल में फंसे लोगों को निकालने के लिए लगातार बसें भेजी गईं. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की 67 बसें नेपाल भेजी गईं. इसके अतिरिक्त बिहार से लगी हुई नेपाल की सीमा पर पांच एम्बुलेन्स भी भेजे गए. सरकारी मदद के अलावा समाजवादी पार्टी ने कार्यकर्ताओं से एकत्रित डेढ़ लाख रुपये भी राहत कार्य के लिए नेपाल भेजे. मुख्यमंत्री ने संजीदगी का परिचय देते हुए यह भी निर्देश दिया कि राहत सामग्री लेकर नेपाल जाने वाले ट्रक ड्राइवरों सहित नेपाल भूकंप के मद्देनजर राहत कार्यों में लगाए गए एंबुलेंस, बसों सहित अन्य सभी वाहनों के ड्राइवरों को प्रतिदिन 500 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे.

लखनऊ स्थित किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय ने भी 23 डॉक्टरों व 24 पैरा मेडिकल स्टाफ समेत 47 सदस्यीय चिकित्सा दल नेपाल भेजा. केजीएमयू के कुलपति प्रो. रविकांत, सीजीएम प्रशासन सुरेंद्र राम, लखनऊ के क्षेत्रीय प्रबंधक अखिलेश कुमार सिंह, चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विजय कुमार, ट्रॉमा सेंटर के सह प्रभारी डॉ. विनोद जैन की मौजूदगी में बस को रवाना किया गया. विश्वविद्यालय के कुलपति की ओर से चिकित्सा दल को नेपाल रवाना करने पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उन्हें धन्यवाद भी दिया. केजीएमयू के कुलपति ने कहा भी कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से हुई वार्ता के बाद केजीएमयू के जनरल सर्जरी के प्रोफेसर डॉ. संदीप तिवारी के नेतृत्व में 45 सदस्यीय टीम काठमांडू के लिए रवाना कर दी गई.

भूकंप पीड़ितों की मदद में सेना की मध्य कमान भी जुटी हुई है. मध्य वायु कमान मुख्यालय इलाहाबाद ने अपने आठ एमआई–17 हेलीकॉप्टर को बचाव व राहत कायों में लगाया. रक्षा मंत्रालय के ऑपरेशन मैत्री के तहत चार सी–17, तीन सी–130 विमान और तीन आईएल–76 विमानों से राहत सामग्री नेपाल भेजी गई. फील्ड अस्पताल और आधारभूत ढांचे को ठीक करने के लिए इंजीनियरिंग कोर की यूनिट भी काठमांडू गई. उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने भी एक ट्रक दवाएं काठमांडू भेजीं. सीएमओ डॉ. एसएनएस यादव के नेतृत्व में बलरामपुर अस्पताल, सिविल अस्पताल, लोहिया अस्पताल, रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल और लोकबंधु अस्पताल के सीएमएस व प्रभारी फार्मासिस्टों ने आईवी फ्लूयड, एंटीबायोटिक सहित जीवन रक्षक दवाएं स्वास्थ्य महानिदेशालय पर इकट्ठा कीं और उसे एक ट्रक से काठमांडू के लिए रवाना किया गया. ट्रक में लगभग तीन हजार आईवी फ्लूयड की बोतलें और ड्रेसिंग का सामान भी काठमांडू भेजा गया. ट्रक के साथ डॉ. अनिल चौधरी, फार्मासिस्ट एचपी वर्मा और वार्ड ब्वॉय संजय भी काठमांडू गए.

प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने कहा कि अब तक (खबर लिखे जाने तक) उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल के विनाशकारी भूकम्प से प्रभावित लोगों की सहायतार्थ अपने वित्तीय संसाधनों से 50 ट्रकों के जरिए खाद्य सामग्री, दवाइयां एवं अन्य सामग्रियां नेपाल भेजी हैं. प्रदेश सरकार द्वारा 132 बसें भेजी जा चुकी हैं इसके अतिरिक्त और बसें भेजकर 200 तक बसें भेजने के निर्देश दिए गए है. सोनाली में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा कैम्प खोले गए हैं, जहां 25 लाख रुपये की दवाएं पीड़ितों के उपचार के लिए भेजी जा चुकी हैं. मुख्य सचिव ने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने वाले पीड़ितों तक आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी यूपी भवन में ठहरने की व्यवस्था की गई है. आईएएस अफसरों की पत्नियों द्वारा चलाई जाने वाली सहकारी संस्था आकांक्षा समिति की तरफ से भी खाद्य सामग्री एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं से भरे दो ट्रक नेपाल भेजे गए. मुख्य सचिव की पत्नी व आकांक्षा समिति की अध्यक्ष सुरभि रंजन ने ट्रकों को लखनऊ से काठमांडू के लिए रवाना किया. ■

विदेश मंत्री ने की अखिलेश की प्रशंसा

भूकंप में नेपाल के लोगों को आगे बढ़ कर मदद करने के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की प्रशंसा की है. सुषमा स्वराज ने ट्विीट कर अखिलेश यादव को उनकी सदाशयता के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इससे नेपाल को मदद पहुंचाने में लगे भारतवर्ष को काफी मदद मिली है. दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने भी नेपाल में राहत कार्य के लिए अपनी एक माह की तनख्वाह देने की घोषणा की. नेपाल में भूकंप से आई भारी तबाही पर दुखी भारतीय संसद में चर्चा के दौरान सांसद मुलायम सिंह यादव ने अपनी एक माह की तनख्वाहह नेपाल राहत कार्य में देने की घोषणा की और यह अपील भी की कि सभी सांसद अपने एक दिन की तनख्वाकह नेपालियों की मदद में दें. उधर, 30 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगे राहत दल ने नेपाल के भूकंप प्रभावित इलाकों में फंसे सात हजार से अधिक लोगों को निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया. उत्तर प्रदेश सरकार ने आधिकारिक तौर पर बताया कि नेपाल में भेजे गए राहत और बचाव कार्य दल ने सात हजार लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला है. नेपाल में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए 205 बसें भेजी गई थीं. 2,500 भूकंप पीड़ित नेपाल से सोनौली बॉर्डर पहुंचे. इसके अलावा 44 बसों में 3,400 लोग भैरवा बॉर्डर पहुचाए गए. खबर लिखे जाने तक 33 अन्य बसों में काठमांडू से करीब दो हजार और लोगों के चलने की खबर मिली थी.

नेपाल से सटे जिलों पर खास ध्यान दिया जाएगा

उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर बसे इलाकों पर अब खास ध्यान दिया जाएगा और इन जिलों को कई पैकेज दिए जाएंगे. इन जिलों को बिजली, पानी, सड़क व रेलवे लाइन जैसी मूलभूत सुविधाएं भी सुचारु तरीके से उपलब्ध कराई जाएंगी. भूकंप के बाद हुई तबाही को देखते हुए सीमावर्ती इलाकों के आर्थिक विकास के लिए सरकार ने यह फैसला किया है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि सीमा पर बसे इलाकों में जो भी दिक्कतें होंगी प्रदेश सरकार उनका समाधान करेगी. अखिलेश पहले भी कह चुके हैं कि नेपाल सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण किया जाएगा. अखिलेश यादव ने कहा कि नेपाल से भारत के पुराने रिश्ते हैं, इन रिश्तों को हमें और मजबूत करना है, ताकि दोनों तरफ के लोग तरक्की कर सकें. ■

नेपाल को बिजली देगा यूपी

उत्तर प्रदेश प्रदेश सरकार भूकम्प त्रासदी से तबाह नेपाल को जरूरत के मुताबिक बिजली देने की तैयारी कर रही है. उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन के निर्देश पर गोरखपुर पावर कॉरपोरेशन के मुख्य अभियंता डीएके सिंह ने नेपाल के भैरहवां स्थित पावर स्टेशन पहुंच कर उत्तर प्रदेश सरकार की इस मंशा से नेपाली पक्ष को अवगत कराया. फिलहाल भैरहवां स्टेशन पर लगे ट्रांसफार्मर से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति का काम चल रहा है. भैरहवां पावर स्टेशन पर 7.50 व 16.50 एमबीए के दो ट्रांसफार्मर लगे हैं. फिलहाल इन्हीं दोनों ट्रांसफार्मर से क्षेत्र में बिजली आपूत्ति की जा रही है. बीते दिनों नेपाल में भीषण भूकम्प के चलते हुई भारी तबाही से कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई है. ऐसे हालात से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल को पूरा सहयोग देने की तैयारी कर ली है. सरकार की इस मंशा को अमलीजामा पहनाने के मद्देनजर ही उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन के निर्देश पर नेपाल को आधिकारिक तौर पर इस मदद के बारे में अवगत कराया गया. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

किसान हितों की अनदेखी न हो : राजनाथ

डॉ. दिलीप अग्निहोत्री

प्रदेश सरकार ने बैमौसम बारिश और ओला पीड़ित किसानों की ऋृण वूसली को स्थगति कर अच्छा काम किया. यह कार्य बारिश, ओले पड़ने के तत्काल बाद कर दिया जाता तो संभवत: कुछ किसानों को आत्महत्या करने से बचाया जा सकता था. लेकिन यह सरकारी अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है कि यह कार्य तत्काल नहीं हो पाया. सरकार ने करीब दस दिन से अधिक की देरी के बाद कर्ज अदायगी शिड्यूल को नए सिरे से तय करने का काम शुरू किया. इसके अन्तर्गत किसानों को न सिर्फ मूल व ब्याज की अदायगी में तत्काल मोहलत दी जाएगी, बल्कि कर्ज अदायगी का समय भी आगे बढ़ाया जाएगा. भारतीय रिजर्व बैंक के कई नियम ऐसे हैं, जिन्हें किसानों को राहत देने के लिए लागू किया जा सकता है. लेकिन यह कार्य बिना किसी देरी के होना चाहिए. इतना ही नहीं, कई जगहों से राहत के नाम पर सौ, पचास, पछहत्तर रुपये के चेक बांटे गए यह भद्दे मजाक से कम नहीं है. यह समझ से परे है कि राजस्व कर्मी या अधिकारी इस प्रकार के फैसले कैसे कर सकते हैं. फैजाबाद के वाजिदपुर गांव के निवासी मोहम्मद साबित पांच बीघा जमीन के मालिक हैं. इसमें दस हजार खर्च करके गेहूं की फसल लगाई थी. बेमौसम बारिश ने फसल तबाह कर दी और मुआवजा मिला सौ रुपये. एक अन्य किसान को दो बीघा की फसल नष्ट होने पर पछहत्तर रुपये मुआवजा मिला. पचास रुपये तक मिलने के भी कई उदाहरण हैं. कल्पना कीजिए जिन किसानों की फसल बर्बाद हो गई, जो पूरी तरह कृषि पर आधारित थे, उनके सामने जीविका का संकट उत्पन्न हो गया, उनके लिये सौ-पचास रुपये मुआवजे का क्या मतलब हो सकता है. क्या यह रकम उन्हें चिढ़ाने या जले पर नमक छिड़कने के लिए नहीं है. इससे तो अच्छा होता कि इन किसानों को कोई सहायता ही न दी जाती. कम से कम उनकी उम्मीद तो कायम रहती कि चलो देर से ही, लेकिन सही मुआवजा मिलेगा. वह सरकार की बन्द मुट्ठी पर भरोसा कर सकते थे. लेकिन यहां तो जो मुट्ठी खुली उसमें केवल सौ-पचास रुपये थे. यह किसानों के घाव पर नमक छिड़कने के अलावा कुछ नहीं है. केन्द्र सरकार ने तैंतीस फीसदी फसल नष्ट होने पर मुआवजा देने का फैसला किया है, जिसके बाद बर्बादी का आंकड़ा बढ़ गया है. अब इस आधार एक फिर से नुकसान का आंकलन करना होगा. उत्तर प्रदेश में ही फसलों के नुकसान का आंकड़ा ढाई हजार करोड़ रुपये को पार कर सकता है. ऐसे में फसलों के नुकसान की केन्द्र सरकार को नई रिपोर्ट भेजी जाएगी. इतना ही नहीं अब तैंतीस प्रतिशत फसल नष्ट होने पर किसानों को बैंक द्वारा सभी सुविधाएं मिलेंगी. लेकिन इसके लिए प्रशासन को भी सजग होना होगा. जिलाधिकारियों को चाहिए कि वह बैंकों के साथ विशेष बैठकें करें. इन बैठकों में यह सुनिश्चित किया जाए कि पीड़ित किसानों को कर्ज वसूली में परेशान न किया जाए. ब्लॉक स्तर पर भी बैंक तथा स्थानीय स्तर के अधिकारियों की बैठकें करनी होंगी. कई स्थानों पर चेकों का अभाव हो गया है. इससे मुआवजा बांटने में बाधा उत्पन्न हुई. अब अधिकारियों ने बैंकों से कहा है कि वह चेकों की उपलब्धता बनाए रखें. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बीते पच्चीस मार्च को पीड़ित किसानों को राहत देने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे. लेकिन अनेक राज्य सरकारें इन्हें तत्काल लागू नहीं कर सकीं. इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को भी फसल बर्बादी के समय सक्रिय बनाने की आवश्यकता है. पिछली सरकारों ने किसान कृषि बीमा को लेकर खूब वाहवाही बटोरी थी. उत्तर प्रदेश में ही छह लाख किसानों का कृषि बीमा किया गया. इसके लिए बीमा कम्पनियों को एक सौ इकतालीस करोड़ रुपये प्रीमियम के रूप में दिया गया. इस आधार पर किसानों को इस समय दो हजार करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा बांटना चाहिए. यह योजना केन्द्र की है, लेकिन इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है. इस समय यदि बीमा राशि किसानों को मिल जाती, तो उन्हें बड़ी राहत होती. तब छह लाख किसानों में से प्रत्येक को मुआवजा राशि मिलती. राज्य व केन्द्र की सहायता इसके अलावा होती. संकट के समय तत्काल राहत का बहुत अधिक महत्व होता है. उससे सैकड़ों लोगों की जान बचाई जा सकती है. लेकिन बीमा के मामले में स्थिति निराशाजनक है. अभी तक मामूली धनराशि ही किसानों को बांटी जा सकी है. कुल मिलाकर कहा जा सकता है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना उस स्थिति में कारगर साबित नहीं हुई, जब उससे सर्वाधिक उम्मीद थी.

जाहिर है कि मुख्य समस्या किसानों तक तत्काल राहत पहुंचाने की है. यह सहायता मात्र दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए. केन्द्रीय गृहमंत्री ने कहा है कि किसानों की सहायता में बजट कोई समस्या नहीं है. राज्यों को पर्याप्त धनराशि दी जा रही है. उसका उचित वितरण सुनिश्चित करना राज्य सरकारों का काम है. टैक्स के रुपयों से राज्यों को मिलने वाली 32 प्रतिशत राशि को बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया गया है. राजनाथ सिंह का दावा है कि उत्तर प्रदेश को डेढ़ लाख करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं. पिछले दिनों ही 87 करोड़ रुपये दिए गए है. प्रधानमंत्री ने आधी रात में ही किसानों की सहायता राशि बढ़ाने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए थे.

प्रजातंत्र में दलगत मतभेद स्वाभाविक है. लेकिन जिस प्रकार राष्ट्रीय संकट के समय सभी लोग मतभेद भुलाकर एकजुट हो जाते हैं, वैसे ही प्राकृतिक आपदा के समय केन्द्र व राज्य सरकारों को राजनीतिक मतभेदों को अलग रखकर कार्य करना चाहिए. इसके अलावा जिला व तहसील प्रशासन के साथ बैंकों व बीमा कम्पनियों का बेहतर तालमेल होना चाहिए. जिससे न्यूनतम समय में पीड़ितों तक सहायता पहुंचाई जा सके. केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के दौरे पर कहा कि किसानों की आत्महत्या चिंताजनक मामला है और इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए. किसानों को मुसीबत की इस घड़ी में उन्हें मदद पहुंचाने के राज्य सरकार के प्रयास में केंद्र सरकार पूरी तरह उसके साथ है. उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से मुसीबत में किसानों को सहायता पहुंचाने में आपस में हाथ मिलाने को कहा. उन्होंने कहा, मैं किसी पर आरोप लगाने या राज्य सरकार की आलोचना करने नहीं आया हूं. मैं सभी से, राजनीतिक दलों से, जिस तरह से भी संभव हो, किसानों को राहत देने के मामले में एकजुट होने की अपील करता हूं. गृहमंत्री ने कहा कि किसान का बेटा होने के नाते वह किसानों की समस्याओं को भलीभांति समझते हैं. उन्होंने कहा कि देश के संघीय ढांचे की वजह से केंद्र सरकार के लिए किसानों को सीधे धनराशि देना संभव नहीं है. यह राज्य सरकारों के माध्यम से ही किया जाना है. राजनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड यानी एसडीआरएफ में पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक 1351 करोड़ रुपये बचे हुए थे. ताजा वित्तीय वर्ष फंड में भी 581 करोड़ रुपये इस मद में शेष थे. इसके अलावा केंद्र सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में 506 करोड़ रुपये की अतिरिक्त रकम भी राज्य सरकार को दी है. लिहाजा प्रदेश सरकार को इस फंड से तमाम प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को भरपूर मदद और राहत मुहैया कराना चाहिए. राजनाथ ने अन्य राज्यों की तर्ज पर यूपी सरकार से किसानों की कर्ज माफी की घोषणा करने की अपेक्षा की थी. बाद में राज्य सरकार ने कर्ज वसूली की प्रक्रिया स्थगित कर दी. राजनाथ ने भी इस बात की हिमायत की है कि किसान के पूरे खेत और जमीन के साथ उस पर होने वाले फसली उत्पादन का भी बीमा किया जाए. इसमें, न्यूनतम आमदनी को मानक बनाते हुए यह सुनिश्चित होना चाहिए कि किसी नुकसान की सूरत में किसान इसका जिम्मेदार न हो बल्कि, बीमा कंपनियां क्षति की भरपाई करें. इसके लिए जल्द ही कृषि आमदनी बीमा योजना लाने की तैयारी है. राजनाथ ने 60 साल से अधिक उम्र के किसानों को पांच रुपये के मासिक पेंशन देने की योजना के बारे में भी लोगों को बताया. राजनाथ ने यह भी कहा कि यूपी सरकार मुआवजे के नाम पर किसानों के जख्म पर नमक छिड़कने का काम कर रही है. ऐसे किसान जिनके पास एक हेक्टेयर से अधिक जमीन है, उन्हें मुआवजे की परिधि से बाहर कर दिया गया है. वास्तव में मुआवजा क्षति के आधार पर मिलना चाहिए, जिससे किसानों का भला हो.

सियासत के बजाय हल निकाले

उत्तर प्रदेश की सामाजिक संस्था लोक आवाज ने प्रदेश में किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या पर गहरी चिन्ता एवं क्षोभ व्यक्त किया है. किसान की आर्थिक स्थिति के आकलन को लेकर विगत सरकारों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया जिससे किसानों की जमीनी समस्याओं से सरकारें कोसों दूर रहीं. देश में राष्ट्रीय कृषि नीति में बदलाव की सख्त जरूरत है और यह वक्त की मांग है. सभी दलों को दलीय प्रतिबद्धता से ऊपर उठकर किसानों की समस्याओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके समस्या का हल निकालना चाहिए.

प्रो0 केके त्रिपाठी ने सरकार से मांग की है कि देश के हताश व बेदम कृषक समुदाय की आर्थिक सुरक्षा के बुनियादी मुद्दे के लिए आयोग का गठन किया जाए. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के मुताबिक लगभग 3.50 लाख किसानों ने बढ़ते कर्ज के बोझ से खुदकुशी की है. सभी राजनीतिक दल किसानों की खुदकुशी पर अपनी-अपनी राजनीति की रोटियां अलग-अलग ढंग से सेंक रही हैं. देश के अर्थशास्त्री, नौकरशाह व टेक्नोक्रेट किसानों से कहते आ रहे हैं कि जितना अन्न उगाएंगे उतनी ही उनकी आमदनी बढ़ेगी. ऐसा कहकर वह किसानों की मदद नहीं करते बल्कि उनके नाम पर कीटनाशक, उर्वरक, बीज एवं यांत्रिक उपकरण बनाने वाली कम्पनियों का व्यवसायिक हित साधते हैं. प्रो0 त्रिपाठी ने कहा कि नेशनल सर्वे संगठन ने एक कृषक परिवार (05 व्यक्ति) की मासिक आमदनी लगभग 3000 रुपये आंकी थी. जबकि छठे वेतन आयोग के तहत कार्यरत चपरासी का वेतन 15000 रुपये है. यह गम्भीर मुद्दा है कि आजादी के 67 वर्ष बीत जाने के बाद भी हम किसानों को चपरासी के बराबर भी लाभ नही दे पाए. अगर कृषि लाभप्रद थी तो किसान क्यों आत्महत्या करते. देश में लगभग 30-40 प्रतिशत किसान ही समर्थन मूल्य का लाभ उठा पाते हैं. लोक-आवाज का मानना है कि किसानों की आत्महत्या पर न तो सरकार गम्भीर है न ही विपक्षी दल. दोनों इस गम्भीर मुद्दे पर संसद में केवल नूराकुश्ती कर रहे हैं. प्रो0 त्रिपाठी का मानना है कि नव उदारीकरण की नीतियों के कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं. सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण ही किसान हाशिए पर जा चुका है और देश की अर्थ व्यवस्था चरमराती जा रही है. गरीब, गरीब होता जा रहा है तथा देश में नव धनाढ्यों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. देश जीडीपी ग्रोथ से आगे नहीं बढ़ेगा बल्कि किसानों और मजदूरों की खुशहाली से ही भारत की तरक्की होगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

सेवानिवृत नौकरशाहों का पुनर्वास

दीनबंधु कबीर

पहले एक प्रचलित थी, योद्धा कभी रिटायर नहीं होते. अब समय की मांग के मुताबिक कहावत बदली है कि सत्ता के चाटुकार कभी रिटायर नहीं होते. उत्तर प्रदेश में बदले समय की कहावत सटीक लागू हो रही है. चाटुकार बने रहे अफसरों को उनके रिटायर होने के बाद भी उन्हें पूर्व के पदों पर बहाल रखा जा रहा है और उनकी सेवा में विस्तार दिया जा रहा है. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चहेते अफसरों को सरकारी सेवा से रिटायर होने के बाद भी उन्हें पुराने पदों पर बहाल किया जा रहा है. इस सरकारी कदमपर प्रदेश के राज्यपाल राम नाइक ने आपत्ति दर्ज कराई और मुख्य सचिव आलोक रंजन को कड़े निर्देश देते हुए उचित कार्रवाई करने को कहा है. मुख्यमंत्री के सचिव रहे शम्भू सिंह यादव और ओएसडी जगदेव सिंह यादव व आज़म खान के अल्पसंख्यक कल्याण और नगर विकास विभाग के सचिव एसपी सिंह सहित कुछ अन्य चुनिन्दा आईएएस और पीसीएस अफसरों का कार्यकाल बढ़ाए जाने पर राज्यपाल ने अपनी नाराजगी जाहिर की है. राज्यपाल सचिवालय की तरफ से मुख्य सचिव के स्टाफ अफसर को भेजे गए पत्र में निर्देश दिया गया है कि यह प्रकरण औपचारिक रूप से मुख्य सचिव के संज्ञान में लाया जाए और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

समाजसेवी डॉ. नूतन ठाकुर ने राज्यपाल को भेजी अपनी शिकायत में कहा था कि प्रदेश सरकार बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए ऐसे कुछ अफसरों को सेवा विस्तार दे रही है जो सरकार के राजनीतिक नेतृत्व के प्रति वफादार हैं. ये अफसर राजनीतिक नेतृत्व के प्रति ही अपनी वफादारी दिखाते रहे हैं जिससे लोकहित प्रभावित हो रहा है और इससे नौकरशाही में गलत सन्देश जा रहा है. डॉ. ठाकुर ने सतर्कता, वित्त और गोपन विभाग जैसे अत्यंत संवेदनशील पदों पर इस प्रकार सेवा विस्तार वाले अफसरों को तैनात किए जाने को प्रदेश शासन के लिए खतरनाक बताते हुए लोकहित में इन अफसरों का सेवा विस्तार तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग की थी.

राज्यपाल की नाराजगी का उत्तर प्रदेश सरकार पर यह असर हुआ कि सरकार ने डीजीपी के पद से रिटायर हुए एके जैन की सेवा में विस्तार दे दिया और उसे एक और विस्तार देने की भूमिका भी तैयार कर दी. विडंबना यह है कि सरकार को यह नहीं दिखा कि जैन के पीछे यूपी के तमाम वरिष्ठ पुलिस अफसरों की लंबी कतार खड़ी है.

वित्त विभाग में सबसे ज्यादा रिटायर्ड अफसरों को दोबारा तैनाती दी गई है. विशेष सचिव पद पर तैनात लहरी यादव को अभी भी सरकारी सेवा में रखा गया है. इसके अलावा ओएसडी श्याम लाल यादव और वरिष्ठ शोध अधिकारी शाहीना परवीन को भी सेवा विस्तार दिया गया है. सचिव अजय अग्रवाल और मुकेश मित्तल को भी उनके पुराने पदों पर दोबारा तैनाती दी गई है. इसी तरह सरकार कुछ और अफसरों को सेवा विस्तार देने की तैयारी कर रही है. इनमें एलडीए में उपाध्यक्ष पद पर तैनात रहे और कुछ दिनों पहले ही हटाए गए एक विवादास्पद अफसर का नाम सबसे ऊपर है. इसके अलावा कुछ पीसीएस और आईएएस अफसर भी अपने सेवा विस्तार के जुगाड़ में लगे हुए हैं. नौकरशाही का परिदृश्य यह है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर सभी बड़े विभागों से रिटायर हुए अधिकांश अफसर सेवा विस्तार या दोबारा नौकरी पाकर काम कर रहे हैं. सत्ता के गलियारे में यह चर्चा जोरों पर है कि खास रिटायर अफसर मुख्यमंत्री के दुलारे हैं, जिसके कारण मुख्यमंत्री दफ्तर से लेकर ज्यादातर बड़े विभागों में उन अफसरों को ही सेवा विस्तार या दोबारा नियुक्ति देकर काम लिया जा रहा है. सरकार की स्वामिभक्ति का रिकॉर्ड बनाने पर उन्हें इसका पुरस्कार दिया गया है. जिसका पूरे प्रदेश की नौकरशाही में नकारात्मक संदेश जा रहा है.

> **चहेते अफसरों को सुविधाएं और उनके रिटायर होने पर सेवा विस्तार देने और अपने नजदीकी अफसरों को बाकायदा राजकीय सुरक्षा प्रदान करने से उत्तर प्रदेश की नौकरशाही भीषण अराजकता का शिकार हो रही है. प्रदेश सरकार ने बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए ऐसे अफसरों को सेवा विस्तार दे दिया जो सरकार के राजनीतिक नेतृत्व के प्रति वफादार हैं.**

मुख्यमंत्री सचिवालय में दो अफसरों मुख्यमंत्री के सचिव शंभू यादव और ओएसडी जगदेव यादव को रिटायरमेंट के बाद तैनात किया गया है. दोनों अफसर रिटायर हो चुके थे, लेकिन दोबारा नियुक्ति देकर इन दोनों अफसरों के लिए खास जगह बनाई गई. यह दोनों अफसर मुलायम सरकार में भी पंचम तल पर तैनात रह चुके हैं. दोनों सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव और अब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के अत्यंत नजदीकी माने जाते हैं. शिकायत पर राज्यपाल ने मुख्य

सचिव को इन दोनों अफसरों की तैनाती के आदेश की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं. नगर विकास मंत्री आजम खां के विभाग में प्रमुख सचिव के पद पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से आए प्रवीर कुमार, सीबी पालीवाल और देवेश चतुर्वेदी से जब मंत्री से नहीं निभी तो आजम अपना पसंदीदा अफसर ले आए. पीसीएस से आईएएस बने एसपी सिंह को विभाग का सचिव बनाया गया. एसपी सिंह रिटायर हो गए, उसके बाद भी उन्हें दोबारा नियुक्ति देकर विशेष कार्याधिकारी और सचिव बनाए रखा गया. इस विभाग में कोई और अफसर आने को तैयार नहीं था, इसलिए बिना प्रमुख सचिव के सचिव ही यह विभाग चला रहे हैं. पूर्व राज्य सम्पत्ति अधिकारी राज किशोर यादव को सरकार ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बनाकर एडजस्ट कर दिया.

चहेते अफसरों को सुविधाएं और उनके रिटायर होने पर सेवा विस्तार देने और अपने नजदीकी अफसरों को बाकायदा राजकीय सुरक्षा प्रदान करने से उत्तर प्रदेश की नौकरशाही भीषण अराजकता का शिकार हो रही है. प्रदेश सरकार ने बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए ऐसे अफसरों को सेवा विस्तार दे दिया जो सरकार के राजनीतिक नेतृत्व के प्रति वफादार हैं. इससे स्पष्ट तौर पर लोकहित प्रभावित हो रहा है और नौकरशाही में भी गलत संदेश जा रहा है. सतर्कता, वित्त और गोपन विभाग जैसे अत्यंत संवेदनशील पदों पर इस प्रकार सेवा विस्तार वाले अफसरों को तैनात किया जाना प्रदेश के लिए खतरनाक है. लोकहित का मामला होने की वजह से ही राज्यपाल से इन चाटुकार अफसरों के सेवा-विस्तार को स्थगित करने की मांग की गई.

उपरोक्त अफसरों के अलावा मुख्य सचिव के स्टाफ अफसर आरडी पालीवाल, वित्त विभाग के सचिव अजय अग्रवाल, सतर्कता विभाग के सचिव आरके रघुवंशी और गोपन विभाग के विशेष सचिव कृष्ण गोपाल जैसे कुछ चुनिन्दा रिटायर्ड आईएएस/पीसीएस अफसरों का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है या विशेष कार्याधिकारी के पद पर इनकी पुनर्नियुक्ति कर के इन्हें विभिन्न विभागों के विशेष सचिव और सचिव जैसे अत्यंत जिम्मेदार पदों पर बैठाया गया है. उक्त अफसर आम जनता के प्रति दायित्वपूर्ण होने के बजाय राजनीतिक नेतृत्व के प्रति अपनी वफादारी दिखाते रहे हैं. इस प्रकार की नियुक्तियां कानूनी प्रक्रिया के तहत नहीं, बल्कि मनमाने ढंग से हो रही हैं और इसके जरिए संबंधित अफसर अनुचित लाभ उठा रहे हैं. सरकार के इन अराजक निर्णयों से प्रदेश की नौकरशाही में राजनीतिक लाभ लेने के लिए अफसरों और राजनीतिक नेतृत्व के बीच अवांछनीय गठजोड़ बनता जा रहा है, जो अफसर इस गठजोड़ में शामिल हो रहे हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद पद मिल रहे हैं. नियुक्ति के बाद इन अफसरों को विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) बना कर इन्हें जिम्मेदार विभागों का सचिव तक बना दिया जा रहा है. ताजा नियुक्त हुए लोगों में किसी को नगर विकास तो किसी को वित्त विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग का सचिव बनाया गया है. इतना ही नहीं सतर्कता जैसे जिम्मेदार विभाग में भी ऐसे ही जुगाड़ पर लाए गए अफसर सतर्कता सचिव बनाए गए हैं. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के एक सचिव भी ऐसे ही पुनर्नियुक्ति वाले ओएसडी बनाए गए हैं. यहां तक कि गोपन विभाग जैसे गोपनीय विभाग के विशेष सचिव भी नियमित अफसर नहीं, बल्कि ऐसे ही विशेष कार्याधिकारी को बनाया गया है. ऐसे अफसर नियम से बंधे नहीं होते और न ही उन पर पद और गोपनीयता का बंधन होता है. इन पर सेवा नियमावली भी लागू नहीं होती. अखिलेश सरकार का यह रवैया सीधे तौर पर पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के बुनियादी सिद्धांतों के विरुद्ध है और प्रदेश के हितों के खिलाफ है.

चहेते अफसरों के रिटायर होने के बाद उन्हें फिर से नौकरी देने के अलावा चहेते विवादास्पद अफसरों को सरकारी सुरक्षा देने का मसला भी गरमाया हुआ है. गंभीर आर्थिक अपराध के आरोपी आईएएस प्रदीप और संकल्प आनंद (आत्म)हत्या कांड में अभियुक्त कमलेन्द्र प्रसाद सहित 12 ऐसे आईपीएस अफसरों के नाम उजागर हुए हैं जिन्हें राजकीय सुरक्षा मिली हुई है. जिन अधिकारियों को वास्तविक खतरा है, उनके बार-बार आग्रह के बावजूद उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जा रही है. ■

feedback@chauthiduniya.com

व्यवसायियों को ऑनलाइन करने की नायाब पहल

चौथी दुनिया ब्यूरो

उत्तर प्रदेश के छोटे और मध्यम दर्जे के व्यवसायियों को एक साथ जोड़ने के लिए इंडियाऑनलाइनडॉटइन (www.indiaonline.in) ने नायाब पहल की है. अपने गेट-ऑनलाइन के जरिए देशभर के व्यवसायियों को एक साथ जोड़ने में अभूतपूर्व कामयाबी के बाद इस संस्था ने खास तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए यूपीऑनलाइनडॉटइन (www.UpOnline.in) पेश किया है. सम्पूर्ण भारतवर्ष के कारोबार को एक मंच या एक नेटवर्क के नीचे लाने की इस पहल की व्यवसायिक जगत में जोरदार सराहना हो रही है.

देशभर के छोटे एवं मध्यम व्यवसायियों को एक मंच पर लाने और अपने व्यापार को साझा करने के लिए गेट-ऑनलाइन को नए फीचर और आकर्षक सुविधाओं के साथ उत्तर प्रदेश में प्रस्तुत किया गया है. कंपनी की प्रवक्ता पूजा कुमारी ने बताया कि छोटे एवं मध्यम व्यापारीhttp://local.up-online.in/index पर आकर अपने ऑनलाइन कारोबार को बढ़ावा देने के लिए अपनी मुफ्त व्यापारिक वेबसाइट भी बना सकते हैं. यह लघु उद्योगों को उन लोगों की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक राजस्व के लिए सहायता करती है जिनके पास खुद की वेबसाइट नहीं है. कंपनी ने इसे नए और आकर्षक फीचर को अपनी स्थायी सेवाओं के साथ लॉन्च किया है ताकि व्यापारियों को एक नए रूप के अलावा ग्राहकों के साथ आसानी से जुड़ने और आकर्षक लाभ कमाने का अवसर मिल सके. यूपीऑनलाइनडॉटइन, इंडियाऑनलाइनडॉटइन का ही हिस्सा है. कंपनी के हाल के एक अध्ययन से पता चला है कि उत्तर प्रदेश में स्थानीय व्यापारियों में अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने का रुझान तेजी से बढ़ा है और यह वृद्धि 80 प्रतिशत तक पहुंची है. यह स्थानीय व्यवसायियों को भारत के हर राज्य में विकास के साथ-साथ उनकी ऑनलाइन मौजूदगी और उनके व्यवसायों को एक ब्रान्डिंग और लोकप्रियता प्रदान करती है, जिससे छोटे व्यापारियों के कारोबार को एक नयी दिशा मिलने के साथ ही लाभ की संभावना बढ़ाती जाती है. इसलिए लघु बाजार में व्यापारियों को उनकी दृश्यता में सुधार के क्रम में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने की आवश्यकता है. इंडियाऑनलाइनडॉटइन के निदेशक राहुल जालान कहते हैं, हम गेट-ऑनलाइन के जरिए देशभर के व्यापारियों को अपनी ऑनलाइन उपस्थिति बनाने के साथ-साथ उनके विकास और व्यापार के अवसर को व्यापक करने का बेजोड़ अवसर दे रहे हैं. जालान कहते हैं कि भारत के आर्थिक विकास में छोटे व्यवसायों की महत्वपूर्ण भूमिका है और उसे बढ़ावा देने और उसे सहायता देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है. दूसरे शब्दों में कहें तो हम एक व्यापक मंच बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिसके माध्यम से कम से कम व्यय द्वारा भी अधिक और बड़े पैमाने पर लाभ कमाया जा सके. इंडियाऑनलाइनडॉटइन ने गेट-ऑनलाइ की पहल करके सभी छोटे और लघु उद्योगों का राष्ट्र के विकास के सन्दर्भ में जो योगदान है, उसे समझने और उसे सार्थक दिशा प्रदान करने की कोशिश की है. देश की लगभग 30 लाख यूनिट का विशाल नेटवर्क, जहां लगभग 70 लाख लोगों की आजीविका चलती है, जहां 6000 से अधिक उत्पादों का निर्माण होता है, जो विनिर्माण उत्पादन में 45 प्रतिशत और निर्यात में 40 प्रतिशत भागीदारी निभाते हैं और भारतीय लघु उद्योग समूह के रूप में राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन्हें एक साथ एक मंच पर ला खड़ा करना एक यज्ञ की तरह है. देश में तेज और समावेशी विकास के एजेंडे की ओर कदम के रूप में लघु और छोटे व्यापार खास महत्व रखते हैं, इंडियाऑनलाइनडॉटइन इसे स्थायी तौर पर रेखांकित करने का काम कर रहा है.

इंडियाऑनलाइनडॉटइन की प्रवक्ता पूजा कुमारी कहती हैं कि इंडिया ऑनलाइन नेटवर्क, पैन इंडिया इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड की एक पहल है जो 350 से अधिक भारत केंद्रित पोर्टल के साथ जुड़ता है और यह अपनी तरह का सबसे बड़ा और अद्वितीय नेटवर्क है. यहां उपभोक्ताओं के लिए सभी संभव संसाधनों और सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है. भारत को उसके राज्यों, संघ शासित प्रदेशों, महानगरों और लगभग 300 प्रमुख शहरों में प्रत्येक के लिए एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से कवर किया गया है और देश के लगभग 4000 अन्य कस्बों और उनके संबंधित राज्य पोर्टलों को उप-साइटों के रूप में शामिल किया गया है. ■

feedback@chauthiduniya.com

आईएएस-आईपीएस यूपी से मुक्ति चाह रहे हैं

प्रांजल अंशुमान

एक समय था जब मायावती के शासनकाल में तबादलों और प्रताड़नाओं से तंग आकर प्रदेश के आईएएस और आईपीएस अधिकारी डेपुटेशन पर या शैक्षणिक अवकाश लेकर राज्य से भागने लगे थे. वह समय अब फिर से दोहरा रहा है. समाजवादी शासनकाल के कुछ अंतराल बीत जाने के बाद आईएएस और आईपीएस अधिकारियों में फिर से बाहर भागने की होड़ लग गई है. कई आईएएस अफसर दिल्ली डेपुटेशन पर जाना चाहते हैं तो कई अफसर दूसरे राज्यों में जाने की अर्जी लगा रहे हैं. कार्मिक मंत्रालय के पास कैडर चेंज करने तक के लिए आवेदन दिए जा रहे हैं. केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, देशभर में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को बेखौफ होकर काम करने की मंचीय सलाह दी जाती है, लेकिन बेखौफ काम करने पर अधिकारियों को प्रताड़ित भी किया जाता है. उत्तर प्रदेश में उस समय अखिलेश यादव सरकार के सत्ता में आए ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे, जब युवा आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल का मामला सामने आया था. नागपाल की सत्ता-शीर्ष द्वारा की गई प्रताड़ना के बाद वही पुराना सवाल फिर सामने आया कि ऐसी राजनीति में नौकरशाही कमजोर होती जाएगी, क्योंकि नेता चाहता ही है कि नौकरशाह कमजोर रहें. दुर्गा शक्ति नागपाल का मामला तो एक टेस्ट केस है, जो आईएएस बनने की चाहत रखने वाले युवकों के मनोबल को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है. यह बात एक अध्ययन में भी सामने आई है. नागपाल से लेकर अशोक खेमका तक के प्रकरणों की एक लंबी फेहरिस्त है. कई आईएएस अफसर तो कहते भी हैं कि समाज में जिस बदलाव का सपना लेकर वे सिविल सर्विस में आए थे, उसे कार्यरूप में उतार पाना बेहद कठिन है. उनके सामने सबकुछ गलत होता रहता है, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते. उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव व राज्यसभा के सचिव रहे योगेंद्र नारायण का आधिकारिक वक्तव्य है कि इस तरह की घटनाओं से योग्य युवक आईएएस की नौकरी से मुंह मोड़ने लगे हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है.

एक सर्वेक्षण में भी यह बात सामने आई कि 73 फीसदी से अधिक आईएएस समाज के लिए सकारात्मक करने के लिए आईएएस बनना चाहते थे, लेकिन भीषण राजनीतिक दखलंदाजी के कारण उनमें से आधे लोग अब नौकरी छोड़ना चाहते हैं. 33 प्रतिशत आईएएस ने माना है कि काम में बाहरी दबाव झेलना रुटीन की तरह है. 60 फीसदी अफसर कहते हैं कि उनका तबादला जरूरत के मुताबिक नहीं बल्कि अन्य वजहों से होता है. इस अन्य का मतलब समझा जा सकता है. 43 फीसदी अधिकारी यह स्वीकार करते हैं कि गलत तरीके से काम करने के लिए उन पर दबाव डाला जाता है. आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि बीते 10-12 साल में दो सौ से अधिक आईएएस अधिकारी नौकरी छोड़कर जा चुके हैं. इनमें यूपी कैडर के करीब दो दर्जन अधिकारी शामिल हैं.

यूपी कैडर के आईएएस अधिकारियों को तो खास तौर पर प्रदेश में नौकरी रास नहीं आ रही है. यह विचारणीय मामला है. कई अधिकारी अपना कैडर बदलवा कर दूसरे राज्यों में जाने की तैयारी कर रहे हैं. केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय के पास एक दर्जन से ज्यादा आईएएस अधिकारियों ने प्रतिनियुक्ति के लिए या अपना कैडर बदलने के लिए प्रस्ताव भेजा है. इनमें से ज्यादातर अधिकारियों के प्रस्तावों में कमी होने की वजह से उसे लंबित रखा गया है. 1999 बैच के आईएएस अधिकारी पी गुरुप्रसाद ने आंध्र प्रदेश कैडर में जाने की अनुमति मांगी है. केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय (डीओपीटी) ने उत्तर प्रदेश सरकार के नियुक्ति विभाग से यह स्पष्टीकरण मांगा है कि गुरुप्रसाद सुपर टाइम स्केल पर आ गए हैं कि नहीं. मंत्रालय का कहना है कि अगर वे सुपर टाइम स्केल में आ गए होंगे तो उनका कैडर नहीं बदला जा सकता. अगर वे सुपर टाइम स्केल में नहीं आते हैं तो कैडर में बदलाव हो सकता है. 2003 बैच की आईएएस मिनिस्ती एस. यूपी कैडर छोड़ कर मध्य प्रदेश कैडर में जाना चाहती हैं. लेकिन कार्मिक मंत्रालय का कहना है कि उन्होंने अभी 16 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है. उन्होंने खुद ही सुपर टाइम स्केल में होने का जिक्र किया है और कैडर बदलवाने की वजह भी नहीं बताई है. लेकिन कार्मिक मंत्रालय में उनका प्रस्ताव लंबित है.

विचित्र बात यह है कि अभी-अभी सिविल सेवा में आए 2014 बैच के युवा आईएएस अफसर हिमांशु अग्रवाल ने पंजाब कैडर और वरुण राजन ने झारखंड कैडर जाने की अनुमति मांगी है. इनके कैडर परिवर्तन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार या पंजाब और झारखंड सरकार से अभी कोई एनओसी नहीं मिली है. 2001 बैच की आईएएस अपर्णा भी आंध्र प्रदेश कैडर जाना चाहती हैं, उन्हें यूपी सरकार से एनओसी मिली तो इनका कैडर बदल जाएगा. 2007 बैच की आईएएस चैत्रा वी. भी आंध्र जाना चाहती हैं. उन्होंने नौ साल की सेवा पूरी नहीं की है, यूपी सरकार से अनुमति मिलने के बाद ही इस बारे केंद्र कोई फैसला करेगा. 2001 बैच के आईएएस विनोद शर्मा उत्तराखंड कैडर जाना चाहते हैं. कार्मिक मंत्रालय के पास उनका आवेदन तो पहुंच चुका है लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार से सहमति नहीं मिली है. 2003 बैच के आईएएस मयूर माहेश्वरी और उनकी पत्नी आईएएस रितू माहेश-वरी हरियाणा कैडर में जाना चाहती हैं. लेकिन इनका प्रस्ताव भी लंबित है. इसके अलावा दर्जनों ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने डेपुटेशन पर जाने या अपना कैडर बदल-वाने या शैक्षणिक अवकाश पर जाने का आवेदन कार्मिक मंत्रालय में दे रखा है. लिहाजा, सवाल यह नहीं है कि कौन आईएएस अधिकारी कैडर बदलवा कर कहां जाना चाहता है, या डेपुटेशन पर कहां पोस्टिंग चाहता है. सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश कैडर में आने के बाद वे कौन सी स्थितियां सामने हैं, जिसके कारण

अधिकारी अपना कैडर बदलवा कर यहां से भाग जाने पर आमादा है. इन स्थितियों या विवशताओं की गहराई से समीक्षा होनी चाहिए. 2014 बैच के नवयुवा अधिकारी भी अगर यूपी कैडर छोड़ना चाहते हैं, तो यह प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण ही है.

नौकरशाही के गलियारे में कभी यह बात कही जाती थी कि उत्तर प्रदेश कैडर मिलना सौभाग्य होता है. लेकिन आज स्थिति इसके ठीक विपरीत है. आज यूपी का नौकरशाह यूपी छोड़कर दिल्ली या अन्य राज्यों में भागने की होड़ में लगा हुआ है. तकरीबन एक वर्ष पहले का सरकारी तथ्य है कि यूपी में तैनात 592 आईएएस अधिकारियों में से 76 अधिकारी प्रतिनियुक्ति लेकर दिल्ली चले गए और दर्जनों कतार में थे. ऐसे में सरकार पर यह आरोप लगना स्वाभाविक है कि राजनीतिक दबाव के कारण अफसर यूपी में काम नहीं करना चाहते. गाजियाबाद में खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के बाद अखिलेश सरकार का प्रकोप झेल चुकीं दुर्गा शक्ति नागपाल ने तो उत्तर प्रदेश छोड़ ही दिया. दुर्गा शक्ति और उनके पति आईएएस अभिषेक सिंह भारत सरकार में अपनी सेवा दे रहे हैं. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के प्रमुख सचिव रहे राकेश गर्ग भी केंद्र चले गए. नीतीश्वर कुमार, समीर वर्मा, एनजी रवि, राकेश गर्ग, प्रवीर कुमार अर्सा पहले यूपी छोड़ दिया. बीएल मीणा, अनामिका सिंह, राजेश कुमार सिंह, रवींद्र कुमार, संयुक्ता समाद्दार भी केंद्र की सेवा में हैं. वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी डॉ. जीके गोस्वामी, बीके सिंह, आल-ोक सिंह, दलजीत चौधरी मायावती के कार्यकाल से ही भारत सरकार में हैं और यूपी वापस लौटने को तैयार नहीं हैं. इनके अलावा करीब एक दर्जन आईएएस और आईपीएस यूपी छोड़ने की कतार में हैं.

यूपी में लंबे वक्त तक काम कर चुके नौकरशाहों का मानना है कि अधिकारियों के यूपी छोड़ने के पीछे राजनीतिक दबाव मुख्य वजह है. नेताओं का जातिवाद और गुटवाद नौकरशाही पर हावी है और उसी आधार पर अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग हो रही है. इससे आजिज लोग प्रदेश छोड़ कर बाहर जाना चाह रहे हैं. अधिकारियों के अनाप-शनाप अतार्किक तबादले हो रहे हैं. यही वजह है कि अधिकांश नौकरशाह यूपी से मुक्ति चाह रहे हैं. अफसरों पर सियासी दबाव का आरोप अकेले अखिलेश सरकार पर नहीं हैं. मायावती सरकार में भी नौकरशाही भीषण दबाव और जातिवादी अराजकतावाद का शिकार थी. जाहिर है, उत्तर प्रदेश में नौकरशाही का मनोबल टूट चुका है, इसे उठाने की जरूरत है. ■

सरकारी दावों की खुली पोल

चौथी दुनिया ब्यूरो

चारधाम यात्रा के कुशल होने की बद्रीनाथ धाम मार्ग पर ही हवा निकल गई. बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हाथी पर्वत में भारी चट्टान खिसक जाने के कारण यात्रा पूरी तरह से बाधित हो गई है. यात्रा ठप होने के कारण तीर्थयात्री बिना दर्शन के ही वापस लौटने को विवश हैं. हिमालय में किए गए प्राकृतिक छेड़छाड़ का नतीजा है कि पहाड़ों का खिसकना जारी है हिमालय के वयोबृद्ध लोग इसे मानवीय गलतियों का नतीजा बता रहे हैं. बद्रीनाथ मार्ग की चौड़ाई बढ़ाने के लिए बीआरओं द्वारा अन्धाधुन्ध की गयी ब्लास्टिंग को जिम्मेदार मान रहे हैं.

दो दिनों से बद्रीनाथ गोविंदघाट में फंसे 156 से अधिक तीर्थयात्रियों को हेलीकॉप्टर से और 600 से अधिक यात्रियों को पैदल जोशीमठ पहुंचाया गया है. बद्रीनाथ हाईवे पर करीब 150 मीटर सड़क नदी में समा गई है. यह एक सच है कि पूरी यात्रा मार्ग खतरनाक एवं भगवान भरोसे ही है, जहां कही भी कुछ हो सकता है. उल्लेखनीय है कि विशालकाय हिमखंडों को काटकर बद्रीनाथ यात्रा को किसी तरह बहाल किया गया ही था कि जोशीमठ के सामने हाथी पर्वत ने तांडव दिखाना शुरू कर दिया. पहले 23 व 24 अप्रैल को चट्टान खिसकी थी और दो दिनों तक मार्ग अवरुद्ध रहा. पूरी चट्टान सड़क व अलकनंदा में आ गिरी. चट्टान के टूटने से उस समय इतनी भयानक आवाज हुई कि जोशीमठ के लोग भी घरों से निकल कर बाहर आ गए. बीते रोज इसी स्थान पर दो स्लाइड के बीच फंसी इनकी पोकलैड मशीनें मलबे में दब चुकी थीं. हाथी पर्वत के खिसकने से बद्रीनाथ हाईवे करीब डेढ़ सौ मीटर पूरी तरह जमींदोज हो गया. इस बीच चट्टानें टूटने और मार्ग के अगले एक सप्ताह तक खुलने की संभावनाएं क्षीण होने के बाद प्रशासन ने भी पिछले दो दिनों से जोशीमठ व बद्रीनाथ में फंसे यात्रियों को बैरंग वापस उनके गंतब्यों को पहुंचाने का कार्य शुरू करते हुए बद्रीनाथ व गोविंदघाट से करीब 156 से अधिक से यात्रियों को हेलीकॉप्टर से और करीब साढ़े 600 से अधिक यात्रियों को पैदल जोशीमठ पहुंचाया.

केन्द्र सरकार के हेलीकॉप्टर सेवा की अनुमति न देने पर लोगों में नाराजगी

मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अवरुद्ध बद्रीनाथ हाईवे का हवाई सर्वेक्षण किया. इसके बाद उन्होंने अधिकारियों से कहा कि तीर्थयात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने हाथी पर्वत का हवाई सर्वेक्षण कर पूरे हालात का जायजा लिया. जोशीमठ के समीप हाथी पर्वत पर पहाड़ के खिसकने और हजारों श्रद्धालुओं के जोशीमठ व बद्रीनाथ में तरफ फंसे होने की सूचना पर हरीश रावत हल्द्वानी से यहां पहुंचे थे. उन्होंने सेना हेलीपैड पर अधिकारियों के साथ ताजा संकट पर विचार-विमर्श किया. यहां बैठक कर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यात्रा बाधित न होने देने के लिए पूरी तरह मुस्तैद रहने को कहा. उन्होंने बीआरओ के अधिकारियों को जल्द से जल्द मार्ग खोलने के निर्देश देते हुए कहा कि जल्द-जल्द इस हाईवे को खोला जाए. इस दौरान मुख्यमंत्री ने जोशीमठ व बद्रीनाथ से हवाई मार्ग से आवागमन के लिए अगले तीन दिनों के लिए हवाई टिकट में रियायत देने की घोषणा करते हुए कहा कि महिलाओं व बच्चों के लिए 500 रुपये प्रति यात्री व पुरुषों से 750 प्रति यात्री हवाई सफर के वसूले जाएंगे. लेकिन केन्द्र सरकार ने केदारनाथ धाम के लिये हेलीकाप्टर सेवा की अनुमति नही दी है. इसको लेकर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष

> **जोशीमठ के समीप हाथी पर्वत पर पहाड़ के खिसकने और हजारों श्रद्धालुओं के जोशीमठ व बद्रीनाथ में तरफ फंसे होने की सूचना पर हरीश रावत हल्द्वानी से यहां पहुंचे थे. उन्होंने सेना हेलीपैड पर अधिकारियों के साथ ताजा संकट पर विचार-विमर्श किया. यहां बैठक कर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यात्रा बाधित न होने देने के लिए पूरी तरह मुस्तैद रहने को कहा. उन्होंने बीआरओ के अधिकारियों को जल्द से जल्द मार्ग खोलने के निर्देश देते हुए कहा कि जल्द-जल्द इस हाईवे को खोला जाए.**

किशोर उपाध्याय ने आज कहा कि राजग सरकार के इस रवैये से श्रद्धालुओं को असुविधा होने और स्थानीय व्यापारियों के रोजगार पर हथौड़ा पड़ने के साथ ही राज्य सरकार की छवि पर भी प्रतिकूल असर पड रहा है. उपाध्याय ने कहा कि 21 अप्रैल से प्रदेश में चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है और राज्य सरकार द्वारा बार-बार अनुरोध किये जाने के बावजूद अब तक केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय द्वारा केदारनाथ के लिये हेलीकॉप्टर सेवा की अनुमति नहीं दी गयी है. उपाध्याय ने कहा कि केन्द्र द्वारा हेलीकॉप्टर उड़ान की अनुमति न मिलने के कारण केदारनाथ दर्शन के लिये जाने वाले श्रद्धालुओं को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है. राज्य सरकार के अनुरोध के बाद केन्द्र ने एक नहीं सुनी.

खंडूड़ी ने व्यक्त की चिंता

प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद भुवन चंद्र खंडूड़ी ने बद्रीनाथ एवं जोशीमठ के मध्य भूस्खलन के कारण विभिन्न प्रदेशों के तीर्थयात्रियों के फंसने पर गहरी चिंता व्यक्त की है. उन्होंने बीआरओ के अधिकारियों व मुख्य अभियंता से फोन पर बात कर जल्द से जल्द मार्ग खोलने को कहा. खंडूड़ी ने जिलाधिकारी चमोली से फोन पर बातचीत कर फंसे यात्रियों को हेलीकॉप्टर से निकालने को कहा. जिलाधिकारी ने श्री खंडूड़ी को जानकारी दी कि कुछ तीर्थयात्रियों को पैदल मार्ग व कुछ को हेलीकॉप्टर द्वारा लाया जा रहा है. खंडूड़ी ने राज्य सरकार से भी अनुरोध किया कि चारधाम यात्रियों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए जाएं. जिस दिन यह घटना घटी खण्डूड़ी अपने चुनाव क्षेत्र में ही थे और वह यात्रियों की सुरक्षा को लेकर व्यथित दिखे. ■

feedback@chauthiduniya.com

> सारी पार्टियां महापुरुषों का सम्मान नहीं करतीं बल्कि उन्हें वोट बैंक की चाभी समझ कर इस्तेमाल करती हैं. अखिलेश सरकार ने भी ऐसा ही किया, तो सबको बुरा लगने लगा. अब अखिलेश यादव ने महाराणा प्रताप की जयंती पर भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का मन बनाया तो फिर से निंदा प्रस्ताव जारी होने शुरू हो गए. अब इन सारे सार्वजनिक अवकाशों को विधानसभा चुनावों से पहले की राजनीति से जोड़ कर देखा जाने लगा है.

महापुरुषों के नाम पर अवकाश की सियासत

छुट्टियों को लेकर सियासत हमेशा से होती रही है. जाति, धर्म और संप्रदाय के आधार पर छुट्टी न घोषित किए जाने की मांग लगातार होती रही है. पिछले कुछ वर्षों में छुट्टियों में 50 फीसदी का इजाफा हुआ है. अब सरकारी छुट्टियां 37 हो गई हैं, जो दूसरे राज्यों से ज्यादा हैं. अवकाश की राजनीति का मसला हाईकोर्ट तब पहुंचा जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 6 दिसंबर को अम्बेडकर परिनिर्वाण दिवस पर अवकाश करने की घोषणा की. खास बात यह है कि यह अवकाश समाजवादी पार्टी की सरकार में ही रद्द किया गया था. किसी राजनीतिक दल के सत्ता में आने के बाद अपनी विचारधारा से जुड़े लोकप्रिय नेताओं के नाम पर सड़कों, भवनों, योजनाओं और कार्यक्रमों की शुरुआत एक परम्परा की तरह बन चुकी है.

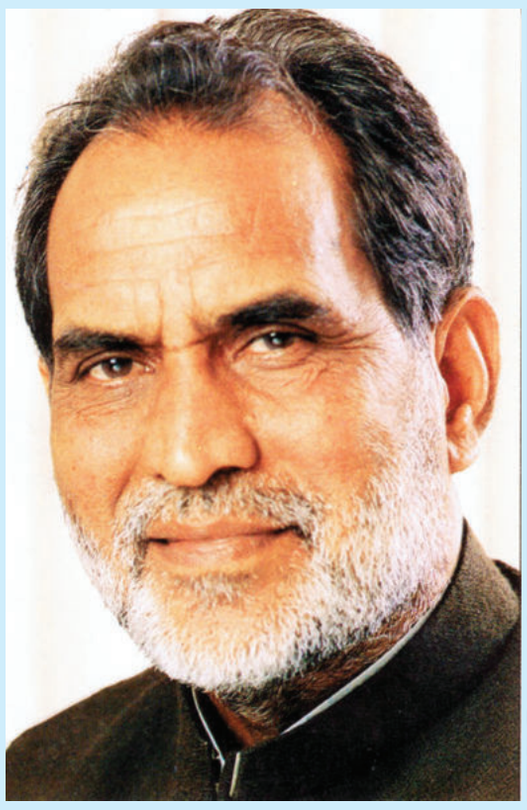

सूफी यायावर

आपदा पर राजनीति, राहत पर राजनीति, दंगा पर राजनीति, यह उत्तर प्रदेश की फितरत हो गई है. अब एक नई राजनीति शुरू हुई है, सार्वजनिक अवकाश की राजनीति. अंबेडकर और कांशीराम के नाम पर पहले घोषित अवकाश को रद्द किया और फिर अम्बेडकर के नाम पर अवकाश दोबारा शुरू कर दिया तो अखिलेश सरकार की हर तरफ निंदा शुरू हो गई. सारी पार्टियां महापुरुषों का सम्मान नहीं करतीं बल्कि उन्हें वोट बैंक की चाभी समझ कर इस्तेमाल करती हैं. अखिलेश सरकार ने भी ऐसा ही किया, तो सबको बुरा लगने लगा. अब अखिलेश यादव ने महाराणा प्रताप की जयंती पर भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का मन बनाया तो फिर से निंदा प्रस्ताव जारी होने शुरू हो गए. अब इन सारे सार्वजनिक अवकाशों को विधानसभा चुनावों से पहले की राजनीति से जोड़ कर देखा जाने लगा है. बाबसाहेब भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर छह दिसंबर को अवकाश घोषित किए जाने के सरकारी फैसले को राजनीतिक नजरिये से देखते हुए इसे 20 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों, उनके परिवार वालों और दलित समुदाय को लुभाने की कोशिश के रूप में फिट किया जा रहा है. हालांकि यह तो है ही कि तरक्की में आरक्षण के मसले पर सपा सरकार के विरोधी स्टैंड से बिदके दलित समुदाय को मुलायम करने की कोशिश में अम्बेडकर पुण्यतिथि के अवकाश को दोबारा शुरू किया गया. छुट्टियों के गुणा-गणित में उत्तर प्रदेश में एक साल के दौरान सरकारी अवकाशों की संख्या बढ़कर अब 37 हो गई है. महाराणा प्रताप की जयंती पर छुट्टी हो गई तो यह संख्या 38 हो जाएगी. उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की तो बल्ले-बल्ले है. एक अधिकारी ने कहा कि इस साल अवकाशों की संख्या 37 पहुंचने के साथ ही पिछले 10 साल में सरकारी छुट्टियों की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

इससे पहले अखिलेश यादव सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जन्मतिथि 17 अप्रैल को अवकाश घोषित किया. महर्षि कश्यप और महर्षि निषादराज जयंती के मौके पर पांच अप्रैल को अवकाश रखा गया. हजरत अजमेरी गरीब नवाज उर्स के मौके पर 26 अप्रैल को भी अवकाश घोषित किया गया है. समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर की जन्मतिथि 24 जून को भी सपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. सार्वजनिक अवकाश का मसला इस कदर उठा कि इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जनहित याचिका तक दाखिल हो गई. न्यायमूर्ति श्रीनारायण शुक्ल और रितुराज अवस्थी की पीठ ने सरकार से जवाब मांग लिया. याचिका में अधिवक्ता अशोक पांडेय ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में सरकारें पिछले कई साल से अवकाश की राजनीति कर रही हैं. इस तरह अवकाश घोषित करने से शासन व्यवस्था पर बुरा असर पडा है. लिहाजा, तयशुदा अवकाश नीति बनाकर इसका तत्काल नियमन किया जाना चाहिए. याचिका में यह आरोप भी लगाया गया है कि कुछ अवकाश तो केवल राजनीतिक वजहों से घोषित किए जाते हैं, जबकि सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का अधिकार केन्द्र सरकार का है. लेकिन राज्य सरकार इसका बेजा इस्तेमाल कर रही है. राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि केन्द्र के 1957 के सर्कुलर के मुताबिक राज्य सरकारें सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का अधिकार रखती हैं. अदालत ने राज्य सरकार को इस मसले पर विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है. उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को पहले से ही किसी भी दूसरे प्रदेश की तुलना में ज्यादा छुट्टिां मिलती हैं. क्षत्रिय समाज के लोगों की ओर से मंत्री अरविंद सिंह गोप ने मुख्यमंत्री के समक्ष यह मांग रखी है. अखिलेश यादव ने इस पर विचार करने का भरोसा दिया है. समाजवादी पार्टी के क्षत्रिय विधायक और मंत्री भी महाराणा प्रताप की जयंती पर छुट्टी चाहते हैं. महाराणा प्रताप जयंती 9 मई को पड़ती है, सरकार इस बार जयंती पर छुट्टी देने की घोषणा कर सकती है. चंद्रशेखर जयंती पर भी समाजवादी पार्टी के क्षत्रिय नेताओं ने 17 अप्रैल को अपनी एकजुटता दिखाई थी. चंद्रशेखर के बहाने पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव के सामने मंत्री अरविंद सिंह गोप, रघुराज प्रताप सिंह (राजा भैया) राजा महेंद्र अरिदमन सिंह, राज किशोर सिंह, सांसद नीरज शेखर, पूर्व सांसद भगवती सिंह और एमएलसी यशवंत सिंह समेत पार्टी के एक दर्जन से ज्यादा विधायक जुटे थे. अब 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती पड़ रही है. सभी की इस मांग को पार्टी महासचिव और ग्राम्य विकास राज्य मंत्री अरविंद सिंह गोप ने मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का जिम्मा लिया था.

छुट्टियों को लेकर सियासत हमेशा से होती रही है. जाति, धर्म और संप्रदाय के आधार पर छुट्टी न घोषित किए जाने की मांग लगातार होती रही है. पिछले कुछ वर्षों में छुट्टियों में 50 फीसदी का इजाफा हुआ है. अब सरकारी छुट्टियां 37 हो गई हैं, जो दूसरे राज्यों से ज्यादा हैं. अवकाश की राजनीति का मसला हाईकोर्ट तब पहुंचा जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 6 दिसंबर को अम्बेडकर परिनिर्वाण दिवस पर अवकाश करने की घोषणा की. खास बात यह है कि यह अवकाश समाजवादी पार्टी की सरकार में ही रद्द किया गया था. किसी राजनीतिक दल के सत्ता में आने के बाद अपनी विचारधारा से जुड़े लोकप्रिय नेताओं के नाम पर सड़कों, भवनों, योजनाओं या कार्यक्रमों की शुरुआत एक परम्परा की तरह बन चुकी है. कुछ जानी-मानी शख्सियतों के जन्मदिन या पुण्यतिथि के दिन राजकीय अवकाश घोषित करना भी इसी की कड़ी है. यह प्रवृत्ति किसी एक राजनीतिक दल या एक राज्य तक सीमित नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश इस मामले में सबसे आगे है. साल भर में 37 छुट्टियां, साप्ताहिक अवकाशों के अतिरिक्त हैं.

दरअसल, इसके पीछे मकसद जितना संबंधित शख्सियतों के प्रति सम्मान प्रकट करना होता है, उससे ज्यादा मंशा यह होती है कि उनके नाम पर सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के साथ-साथ कुछ खास सामाजिक वर्गों के बीच अपनी पैठ बढ़ाई जाए और चुनावों में इसका फायदा उठाया जाए. पिछले कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश में दिवंगत महत्त्वपूर्ण शख्सियतों को एक तरह से राजनीति का मोहरा बनाया जा रहा है. आमतौर पर अम्बेडकर जयंती पर छुट्टी घोषित होती रही है. कुछ समय पहले राज्य की समाजवादी पार्टी की सरकार ने छह दिसंबर को अम्बेडकर की पुण्यतिथि के दिन अवकाश की घोषणा की. इससे पहले सपा सरकार ने ही मायावती सरकार की ओर से अम्बेडकर निर्वाण दिवस और कांशीराम के जन्मदिन पर घोषित छुट्टियां रद्द कर दी थीं. जाहिर है, समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर बाबासाहेब के निर्वाण दिवस के दिन छुट्टी की घोषणा इसलिए की कि दलित समुदाय को अपनी ओर आकर्षित किया जा सके. कुछ समुदायों को खुश करने के इरादे से अवकाश का सहारा लेने के सिलसिले में अखिलेश यादव की सरकार ने परशुराम जयंती, महर्षि कश्यप और महर्षि निषादराज जयंती, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के जन्मदिन भी अवकाश की सूची में जोड़ दिए हैं. एक छुट्टी हजरत अजमेरी गरीब नवाज के उर्स के मौके पर भी घोषित की गई है. देश की संस्कृति इतनी विस्तृत है कि सभी समुदायों का कोई न कोई प्रतीक-व्यक्तित्व बताया जा सकता है. एक से अधिक नाम भी लिए जा सकते हैं. लेकिन सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित करना संभव नहीं है.

राज्य सरकार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा-25 के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित करती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश में पूरी तरह राजनीतिक कारणों से मनमाने तरीके से छुट्टियां घोषित की जा रही हैं. पिछली मायावती सरकार ने कांशीराम के जन्म और पुण्यतिथि पर अवकाश घोषित किया तो मौजूदा अखिलेश सरकार ने चंद्रशेखर, कर्पूरी ठाकुर और चरण सिंह के जन्मदिवस पर छुट्टी घोषित कर दी. इस प्रकार मनमाने तरीके से छुट्टियों की घोषणा से सरकारी काम बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं और उन पर तत्काल नियंत्रण की जरूरत है. ■

feedback@chauthiduniya.com

छह महीने काम, छह महीने मौज

छुट्टियों को लेकर क़ानून है जिसके तहत केंद्र और राज्य सरकार के पास अलग-अलग छुट्टियां घोषित करने का अधिकार है. केंद्र में 14 छुट्टियां हैं, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने क़रीब 37 छुट्टियां घोषित कर रखी हैं. अधिकतर छुट्टियां महापुरुषों के नाम पर घोषित की गई हैं. महापुरुषों के नाम पर घोषित छुट्टियां सरकारों के बदलने से बदलती रहती हैं. यानी, पार्टी बदली तो महापुरुष बदले और छुट्टियां बदलीं. इतनी बड़ी संख्या में होने वाली छुट्टियों और छुट्टियों को लेकर होने-वाले फेरबदल से सरकारी काम-काज पर बेहद बुरा असर पड़ता है. अचानक छुट्टी घोषित होने के कारण भी मुश्किलें बढ़ जाती हैं. उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार ने कांशीराम के जन्म दिवस और परिनिर्वाण दिवस की छुट्टियों को सत्ता पर आते ही ख़त्म कर दिया था. लेकिन कई अन्य महापुरुषों के नाम पर नई छुट्टियां शुरू भी कर दीं. इसी तरह उत्तर प्रदेश की बसपाई सरकार ने भी किया था. भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिवस पर भी छुट्टी शुरू की गई और परिनिर्वाण दिवस पर भी दोबारा अवकाश घोषित किया गया. राज्य सरकार के मुख्यालय की सेवाओं में काम करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को हफ़्ते में दो दिन छुट्टी मिलती है. ऐसे में साल में 104 दिन के साप्ताहिक अवकाश मिल जाते हैं. सालाना छुट्टियां और बीमारी के कारण मिलने वाली छुट्टियां इससे अलग हैं. वहीं जनपदीय सेवाओं में काम करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन की छुट्टी मिलती है. स्थिति यह है कि मुख्यालयों में काम करने वाले अधिकारी-कर्मचारी साल में लगभग आधे समय छुट्टियों पर ही रहते हैं. छुट्टियों पर राजनीति करने में सारी पार्टियां एक-दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ में लगी रहती हैं. लेकिन अखिलेश ने उनकी छुट्टी रद्द की तो मायावती बिफर पड़ीं और कह दिया कि उत्तर प्रदेश में तो अराजकता है और वहां राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए. बसपा ने इसे राजनीति में गिरावट की पराकाष्ठा बता दिया. मायावती को रंज था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि नौ अक्टूबर पर होने वाले सार्वजनिक अवकाश को रद्द क्यों कर दिया. मायावती ने कांशीराम की पुण्यतिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था. अब कांशीराम की पुण्यतिथि के दिन नौ अक्टूबर को स्कूल, कॉलेज और दफ्तर सामान्य रूप से खुलते हैं. बसपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्या ने तो घोषणा ही कर रखी है कि उनकी सरकार आने पर रद्द की गई छुट्टियां फिर बहाल की जाएंगी, यानी समाजवादी सरकार की ओर से घोषित कुछ छुट्टियां खारिज भी की जाएंगी. सपा सरकार ने शुरुआत में ही अम्बेडकर पुण्यतिथि पर घोषित छुट्टी भी रद्द कर दी थी. लेकिन तरक्की में आरक्षण मसले पर सपा सरकार के विरोधी स्टैंड से नाराज दलितों की सहानुभूति लेने के लिए सपा सरकार ने फिर से बाबा साहब की पुण्यतिथि 6 दिसंबर पर अवकाश घोषित कर दिया. इस तरह अवकाश को लेकर सियासी खींचतान और तिकड़म जारी है. महापुरुषों के नाम पर अवकाश घोषित करने से पार्टियों को लगता है कि उस समुदाय का वोट उसे ही मिल जाएगा. देश में महापुरुषों को भी जातियों और वोट-खेमों में बांट कर रख दिया गया है. कांशीराम की पुण्यतिथि पर घोषित अवकाश रद्द किए जाने पर तो मायावती सपा सरकार पर इस कदर बौखला गई थी कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर कांशीराम न होते तो मुलायम का पूरा परिवार भैंस चरा रहा होता. ■

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

बिहार झारखंड

11 मई–17 मई 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

झटकों से ज्यादा अफ़वाहों ने मारा

13.1 तीव्रता वाले भूंकप की अफवाह ने तो लोगों की बैचेनी इतनी बढ़ा दी कि लोग बदहवास होकर जहां–तहां जाने लगे. लोगों को यह समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर जब इस तरह का भूकंप आ ही जाएगा तो फिर बचेगा क्या? मंदिरों में पूजा–पाठ शुरू हो गया और घरों का माहौल बहुत ही गमगीन हो गया. स्थिति की भयावहता को भांपते हुए पटना प्रशासन ने माइक से प्रचार कराकर इस तरह की सूचनाओं को अफवाह बताया और लोगों को आशवस्त किया कि आप लोग निश्चिंत रहे. कुछ शरारती तत्व इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं जिन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है.

सरोज सिंह

पिछला पखवाड़ा बिहार और नेपाल के लिए बेहद ही पीड़ादायक रहा. कुदरत के कहर ने दो मिनट के भीतर ही हजारों जानें लील लीं और लाखों को बेघर कर दिया. राहत और बचाव कार्यों की व्यापकता से अब इन इलाकों में जिंदगी धीर–धीरे पटरी पर आ रही है. जो चले गए, उन्हें तो वापस लाना संभव नहीं है लेकिन बेघरों को बसाने और घायलों के जख्मों पर मरहम लगाने का जो अद्भुत प्रयास सरकार से लेकर हरेक इंसान ने किया वह वाकई काबिलेतारीफ है. लेकिन इस संकट भरे दौर का एक काला पन्ना भी है जिसका पोस्टमार्टम करना बेहद जरूरी है. सेना, सरकार, स्वयंसेवी संगठन और व्यक्तिगत हैसियत से जब सारे लोग पीड़ितों की सेवा में लगे थे तब कुछ ऐसे भी गैरजिम्मेदार लोग थे जिन्होंने तरह–तरह की अफवाहों से इस दौर में संकट को काफी बढ़ा दिया. खासकर सोशल मीडिया में ऐसी ऐसी बिना सिर–पैर की सूचनाएं आने लगीं जिससे नागरिकों के बीच दहशत फैली और इसी दहशत में कोई पार्कों में रात गुजारने को मजबूर हो गया तो किसी ने सड़कों पर अपने बाल बच्चों के साथ रतजगा किया. अस्पतालों में सीने में दर्द की शिकायत लेकर मरीज काफी संख्या में पहुंचने लगे. भूकंप के पहले झटके के बाद से ही यह सिलसिला शुरू हो गया. अफवाहों के बाजार में बात आई कि बिहार में ही हजारों लोग भूकंप में मर गए. ठीक इसके तुरंत बाद सोशल मीडिया पर बार–बार संदेश आने लगा कि फलां समय में जोरदार भूकंप आने वाला है. इतने बजे से इतने बजे तक आप लोग सतर्क रहें.

व्हाट्स–एप के माध्यम से अफवाह उड़ी कि 13.1 तीव्रता वाला भूकंप आने की आशंका है, अफवाहों से पता चला कि सुबह 11:10 से 12, शाम 5:40 से 6:07, रात 10:36 से 11:50 और अर्धरात्रि 1:42 से 2:20 के बीच भूकंप आएगा, जिसके कारण लोग दहशत में रहे और अपने घर से बाहर निकल कर कोई पटना के एतिहासिक गांधी मैदान में तो किसी ने अपने घर के पास वाले पार्क में रात बितायी.

13.1 तीव्रता वाले भूंकप की अफवाह ने तो लोगों की बैचेनी इतनी बढ़ा दी कि लोग बदहवास होकर जहां–तहां जाने लगे. लोगों को यह समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर जब इस तरह का भूकंप आ ही जाएगा तो फिर बचेगा क्या? मंदिरों में पूजा–पाठ शुरू हो गया और घरों का माहौल बहुत ही गमगीन हो गया. स्थिति की भयावहता को भांपते हुए पटना प्रशासन ने माइक से प्रचार कराकर इस तरह की सूचनाओं को अफवाह बताया और लोगों को आशवस्त किया कि आप लोग निश्चिंत रहे. कुछ शरारती तत्व इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं जिन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है. व्हाट्स–एप के जरिए अफवाह फैलाने के आरोप में पूर्व विधायक के खिलाफ पुलिस से शिकायत की गई. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सचिवालय थाने में मामला दर्ज किया है. पुलिस को शिकायत मिली की आरोपी पूर्व विधायक व्हाट्स–एप के एक ग्रुप पर भूकंप आने की गलत सुचना दे रहे थे. जब आपदा प्रबंधन विभाग से पूछताछ की गई तो खबर अफवाह थी. इसके बाद सचिवालय थाने में शिकायत की गई. आरोपी पूर्व विधायक नरपतगंज का निवासी है.

आपदा प्रबंधन विभाग ने भी लोगों से अपील की कि आप लोग अफवाहों पर ध्यान न दें. भूकंप आने की सूचना देना किसी के लिए भी संभव नहीं है. दुनिया में केवल जापान ही ऐसा देश है जो केवल छह सेकंड पहले लोगों को भूकंप की चेतावनी देने में सफल रहा है. पटना में लोगों के दिलों से भय दूर करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद पटना के पार्कों में गए और वहां मौजूद लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की. नीतीश कुमार ने लोगों से कहा कि आप डरें नहीं बल्कि सर्तक रहें. उन्होंने प्रशासन को पार्कों में जनता के लिए सभी आवश्यक सुविधा मुहैया कराने का निर्देश भी दिया. अगले दिन शाम को एक बार फिर एक अफवाह जोरदार ढंग से उड़ी की चांद उल्टा हो गया है. चांद का उल्टा होना भारी अपशकुन बताया गया और इसे महाप्रलय का संकेत कहा गया. देखते ही देखते टीवी चैनलों में भी इसकी चर्चा होने लगी. टीवी पर उल्टा चांद की खबर आते ही दहशत चरम पर पहुंच गया. लोगों ने अपने आप को अहसाय महसूस किया और यह मान लिया कि जीवन का अंत अब तय है. जब तक इस अफवाह का खंडन आता तब तक काफी देर हो चुकी थी. इस अफवाह को जितना नुकसान पहुंचाना था, वह पहुंचा चुकी थी. बाद में बताया गया कि शुक्ल पक्ष में चांद ऐसा ही दिखता है इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है. इन अफवाहों और नागरिकों की बैचेनी को देखते हुए सरकार ने स्कूलों को भी दो दिनों तक बंद रखने का फैसला किया.

आपदा प्रबंधन विभाग पर अफवाह का असर कुछ ऐसा है कि विभाग के इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (इओसी) के टेलीफोन लगातार घनाघना रहे थे. एक शख्स ने फोन पर सूचना दी कि उनके मोहल्ले में एक साथ कई लोगों को चक्कर आ रहा है. सूचना देने वाले ने यह भी पूछा कि कहीं यह भूकंप के बाद भूमिगत जल में जहर फैलने का असर तो नहीं है? क्योंकि हमारे मोहल्ले में ये सभी लोग चापाकल का पानी पी रहे हैं. तभी एक अन्य टेलीफोन पर सहरसा से एक शख्स ने पूछा कि 13.1 तीव्रता वाला भूकंप कितने बजे आएगा? दरअसल उल्टा चांद के बाद तालाब और चापाकल के पानी का जहरीला हो जाने की अफवाह भी जोर से फैली. मुजफ्फरपुर शहर का हाल तो यह हो गया कि शाम होते–होते सारे बोतलबंद पानी का स्टॉक बाजार से खत्म हो गया. लोगों को लगा कि सप्लाई का पानी जहरीला हो गया है इसलिए अगर जान बचानी है तो फिर बोतलबंद पानी ही पिया जाए. हद तो यह हो गई कि जो लोग बोतलबंद पानी नहीं खरीद पाए वह कई घंटों तक प्यासे ही बैठे रहे. बाद में प्रशासन के लोगों ने खुद चापाकल का पानी पी पीकर लोगों को भरोसा दिलाया कि कहीं पानी में जहर नहीं है यह सब अफवाह है और आपलोग अफवाहों पर ध्यान नहीं दें. इसके बाद ही शहर में जनजीवन सामान्य हो पाया. सोशल मीडिया का तो इस संकट में कुछ लोगों ने गलत इस्तेमाल किया ही पर टीवी चैनलों ने भी इसमें कुछ चूक कर दी. बेशक चैनलों ने लोगों को जागरूक किया उन्हें सर्तक किया पर अफवाहों के खिलाफ जो लड़ाई उन्हें लड़नी चाहिए थी, उसमें वह कुछ कमजोर दिखे. दरअसल होना यह चाहिए था कि चैनलों को अफवाहों का खंडन पूरे तथ्य के साथ तुरंत जनता के बीच परोसना चाहिए था लेकिन हुआ यह कि पहले अफवाहों पर चर्चा हुई और बाद में इसे गलत बताया गया. इस छोटी सी चूक ने अफवाहों को अपने मकसद में कामयाब कर दिया और जनता बेवजह परेशान हो गई. बड़े भूंकप के बाद कम तीव्रता के छोटे छोटे झटके आने की आशंका जैसी खबरों को पूरी प्रमुखता से नहीं दिखाया गया. खैर चैनलों ने तो कमोवेश अच्छा ही काम किया पर सोशल मीडिया का कुछ लोगों ने गलत इस्तेमाल कर कई जानों को संकट में डाल दिया. पर इस दौर में सोशल मीडिया ने अपनी उपयोगिता भी साबित की. नेपाल के भूकंप पीड़ितों को राहत पहुंचाने के मामले में इंटरनेट और सोशल मीडिया पर फेसबुक का सेफ्टी चेक और गूगल की पर्सन फाइंडर जैसी सेवाओं का नाम सबसे पहले आता है. इन सेवाओं ने लोगों को अपनों की स्थिति और खुद के सुरक्षित होने संबंधी सूचनाओं की जानकारी देने में मदद की.2011 में जापान में आई सुनामी के बाद लांच की गई फेसबुक की यह सेवा आपदा प्रभावित इलाकों में फंसे हुए लोगों के लिए अलर्ट जारी करती है जिससे लोग अपने फेसबुक मित्रों को अपने सुरक्षित होने की सूचना को साझा करते हैं. इस बार के आपदा में लोगों ने इस सेवा का जमकर उपयोग किया और अपने मित्रों और परिजनों को राहत पहुंचाई. कहा जाए तो माध्यम कोई बुरा नहीं है बस कुछ लोग इसे बदनाम कर देते हैं. इसलिए बेहतर होगा कि एक जिम्मेदार नागरिक की तरह संकट की घड़ी में हम अपना व्यवहार रखें और मानवता की सेवा करें न कि अफवाहें फैलाकर लोगों की जिंदगी को और संकट में डाल दें. ■

feedback@chauthiduniya.com

अफवाहों की सूचना के बाद लोग अपने कार्यालयों से बाहर निकल आए. सभी तरफ अफरा–तफरी मची रही.

एक नज़र

प्राकृतिक विपदा में पार्टी से ऊपर उठकर काम करें

नेपाल के साथ साथ उत्तर बिहार व अन्य राज्यों में आये इस भयंकर तुफान एवं भूकंप ने कई लोगों को ईहलीला समाप्त हो गयी है इस प्राकृतिक प्रकोप में आमजन मानस से अनुरोध करते हुए रालोसपा के युवा नेता अमरेन्द्र सिंह कहा कि केन्द्र सरकार ने सराहनीय कदम उठाया है और साथ ही बिहार सरकार तथा बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के कार्यों की सराहना की और कहा कि इस विपदा में पार्टी से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है. सिंह ने मृतात्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना जताई. श्री सिंह ने लोगों से इस विकट परिस्थिति में धैर्य धारण एवं सूझ–बूझ से काम करने की अपील की.

वैश्य स्वाभिमान चेतना रथ घूमेगा

सूबे की 23 प्रतिशत आबादी वोले वैश्य समाज संगठित कर राजनैतिक ताकत बनाने के उद्देश्य से पूरे बिहार में वैश्य स्वाभिमान चेतना रथ घूमेगा. अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के राष्ट्रीय महासचिव गोपाल मोर एवं प्रवक्ता संजय वर्मा ने बताया कि बिहार में वैश्य समाज की आबादी सर्वाधिक है, जो 56 उपजातियों का विशाल समूह है. मगर विडंबना की बात है कि सभी राजनीतिक दल इस समाज की उपेक्षा बड़ी चतुराई से करते रहे हैं. वोट और नोट का रिश्ता कायम रख समाज को सत्ता से महरूम रखते आए हैं. नेताद्वय ने कहा कि प्रस्तावित रथयात्रा सूबे के 38 जिलों में घूमेगी. आगामी चुनाव में अपना हित सुरक्षित देखकर ही किसी राजनीतिक दल को अपना बहुमूल्य वोट देगी.

आनंदमय बनाती है इस्सयोग

परमात्मा प्रत्येक मानव के भीतर अपनी संपूर्ण दिव्यता के साथ प्रतिष्ठित रहते हैं. मनुष्य की अपनी ही लौकिक दुर्वलताएं, उसका स्वार्थ और कुत्सित कामनाएं, इसे इसके स्वयं के भीतर स्थित परमात्मा से जीवन–पर्यन्त दूर रखती है. 'इस्सयोग' की सूक्ष्म और सहज साधना–पद्धति अपना कर मनुष्य अपने और अपने परमात्मा के बीच के इस दीवार को हटा कर, अपने ब्रह्म–स्वरूप को पा सकता है. यह विचार अंतर्राष्ट्रीय इस्सयोग समाज के तत्त्वावधान मे, पटना के गोला रोड स्थित संस्था के नवनिर्मित एमएसएम बी उत्सव भवन में आयोजित 'शक्तिपात–दीक्षा' कार्यक्रम में, संस्था की अध्यक्ष और तत्त्वज्ञानी सदगुरुमाता मां विजया जी ने व्यक्त किया. भीषण गर्मी के साथ भूकंप के झटकों के बावजूद विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या मे आये नव–जिज्ञासु स्त्री–पुरुषों को, माताजी तथा संस्था के उपाध्यक्ष(मुख्यालय) बड़े भैया श्रीश्री संजय कुमार ने संयुक्त रूप से इस्सयोग की सूक्ष्म और आंतरिक साधना आरंभ करने के लिये आवश्यक 'शक्ति–पात–दीक्षा' प्रदान की. इस कार्यकम में संस्था के संयुक्त सचिव अभियंता उमेश कुमार, सरोज गुटगुटिया, लक्ष्मी प्रसाद साहु, संदीप गुप्ता, संगीता झा, अनंत कुमार साहू, नीना दूबे, श्रीप्रकाश सिंह, शिवम झा, प्रणव, प्रभात चन्द्र झा, मनोज राज, अवध किशोर शर्मा, मोहन राय, समेत बड़ी संख्या में संस्था के अधिकारी एवं स्वयंसेवक उपस्थित थे. ■

शिवहर

स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीति गर्म

इंतेजारुल हक

स्थानीय निकाय चुनाव की आहट से पूर्वी चम्पारण का राजनीतिक तापमान गरमाने लगा है. एक ओर जहां संभावित प्रत्याशी अपने आकाओं को खुश करने में जुटे हैं तो दूसरी ओर मौजूदा विधान पार्षद द्वारा मतदाताओं व कार्यकर्ताओं के बीच हाजिरी लगानी शुरू कर दी गयी है. मौजूदा विधान पार्षद के छह वर्षो के कार्य कलाप का लेखा–जोखा भी होने लगा है. चौक–चौराहों पर इनके कार्यो की समीक्षा तेज होती जा रही है और बहुत से मुद्दों पर चर्चा के दौरान इन्हें कठघरे में खड़ा किया जा रहा है.वर्तमान में रेणु सिंह यहां की विधान पार्षद हैं जो साहेबगंज के विधायक राजु सिंह की पत्नी और जदयू नेता ई. शशि सिंह की बहन हैं.हालांकि मौजूदा कार्यकाल में इनके क्षेत्र को कोई खास उपलब्धि इनके प्रभाव से नहीं हासिल हो सकी है जिसे क्षेत्र की विकास धारा में उल्लेखनीय माना जा सके. त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिनिधियों की समस्याओं के साथ–साथ क्षेत्र में समय नहीं देना एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है. जानकार बताते हैं कि रेणु सिंह द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान एक बार भी त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को सदन के पटल पर नहीं रखा गया और न ही क्षेत्र में समय दिया गया है.इस कारण यह मुद्दा वर्तमान विधान पार्षद की राह का एक बड़ा रोड़ा साबित तो होगा ही इस के साथ ही कई अन्य मुद्दे उनकी राह की बाधा बनकर खड़ी होंगी. राजद–जदयू के विलय होने को लेकर दोनों दलों के संभावित दावेदारों की कश्मकश चेहरे पर नंगी दिखने लगी है.संभावित दावेदारों के बड़े–बड़े बैनर व होर्डिंग इनकी बेचैनियों और आशंकाओं की चुगली खाते जान पड़ते हैं. अभी तक संभावित प्रत्याशियों के जो नाम सामने आये हैं उनमें एक उर्दू दैनिक अखबार के संपादक डॉ. खालिद अनवर की दावेदारी सब से प्रबल है. डॉ. अनवर को लालू यादव का आर्शीवाद प्राप्त होने की जहां पूरे क्षेत्र में चर्चा बना हुआ है तो दूसरी तरफ पूर्वी चम्पारण जिला मुखिया संघ का भरपूर समर्थन भी इन्हें प्राप्त है.वे स्थानीय होने का भी लाभ लेने की कोशिश में हैं और क्षेत्रों का भ्रमण कर जनप्रतिनिधियों को अपने ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं. सभावितों की सूची में दूसरा महत्वपूर्ण नाम कलावती देवी का है और श्रीमति देवी एक बार यहां से प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और राजद में इनकी पकड़ काफी मजबूत रही है.इन्हें भी लालू यादव का समर्थन प्राप्त है और काफी मजबूती के साथ–चुनावी मैदान में उतरी हैं.वे अपने कार्यकाल में हुए विकासात्मक कार्यो व त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों के अधिकार के लिए सदन के पटल पर रखे गये मुद्दों को लेकर मैदान उतरी हैं.वे खैरवा के कब्रिस्तान की चहारदीवारी कराने,गोला पकड़िया में पुल बनवाने,पैनी नदी में सुलिस गेट लगवाने तथा क्षेत्र में शौचालय व चापाकल लगवाने समेत इनके द्वारा कराये गये कई विकासात्मक कार्यो का हवाला देते हुए कहती हैं कि वे हमेशा से लालू यादव के साथ थीं और आज भी हैं.

अब राजद–जदयू का विलय हो गया और दोनों पार्टियों की ओर से कोई एक ही प्रत्याशी मैदान में दिखेगा. दूसरी तरफ राजद के ही राजेश गुप्ता उर्फ बब्लू गुप्ता के चुनावी मैदान में उतरने की संभावना से भी इंकार नही किया जा सकता. राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं चल रही हैं उनके मुताबिक भाजपा उन्हें अपना प्रत्याशी बनाने जा रही है. इसके अलावा श्री गुप्ता को जिला परिषद अध्यक्ष मंजू देवी का भी सहयोग प्राप्त होने की चर्चाएं जोर–शोर से चल रही है.श्री गुप्ता पूर्व में कई चुनाव लड़ चुके हैं और हार के बावजूद राजद की राजनीत में काफी सक्रिय रहे हैं.वहीं निर्दलीय से समाज सेवी परवेज अहमद खां व भाकपा से अतीक अहमद खां चुनावी मैदान में उतरेंगे.परवेज अहमद खां युवा लोजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं और अभी विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत कर अपनी उम्मीदवारी को मजबूत करने की दिशा में काफी सक्रिय हैं.वहीं अतीक अहमद खां को भाकपा ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है.

अन्य और भी नाम हैं जो महत्वकांक्षाओं के कंधे पर सवार होकर खामोशी से जुगाड़ की प्रतिक्रिया मे लगे हैं. कुल मिलाकर निकाय चुनाव को ले राजनीति गरमा गयी है और त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधियों को अपने–अपने पक्ष में करने की भरपूर कोशिश की जाने लगी है. ■

feedback@chauthiduniya.com

> अभी तक संभावित प्रत्याशियों के जो नाम सामने आये हैं उनमें एक उर्दू दैनिक अखबार के संपादक डॉ. खालिद अनवर की दावेदारी सब से प्रबल है. डॉ. अनवर को लालू यादव का आर्शीवाद प्राप्त होने की जहां पूरे क्षेत्र में चर्चा बना हुआ है तो दूसरी तरफ पूर्वी चम्पारण जिला मुखिया संघ का भरपूर समर्थन भी इन्हें प्राप्त है.

कलावती देवी

डॉ. खालिद

बब्लू गुप्ता

परवेज़ ख़ान

अतीक़ अहमद ख़ान

निजी विद्यालय संचालकों पर मेहरबान क्यों है प्रशासन?

इंतेज़ारुल हक़

आखिर कब तक चलेगी निजी विद्यालयों के संचालकों की मनमानी? कबतक रिएडमिशन व अन्य कार्यक्रमों के नाम पर अभिभावकों का होता रहेगा शोषण? आखिर शिक्षा विभाग व जिला प्रशासन के अधिकारी इस बावत खामोश क्यों है और इसके पीछे इनकी मंशा क्या है?बार–बार छात्रों व विभिन्न संगठनों द्वारा आंदोलन किये जाने व विरोध मार्च निकाले जाने के बावजूद जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किये जाने पर एक लम्बी गरम बहस छिड़ी हुई है और जानकार अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध बताने लगे हैं. जिले में संचालित गैर सरकारी विद्यालयों में जिस तरह री–एडमिशन के नाम पर लूट मची हुई है और अभिभावकों का दोहन किया जा रहा है इससे एक बात तो साफ हो गयी है कि इन निजी विद्यालयों के संचालकों पर विभागीय अधिकारी इन दिनों खास मेहरबान हैं.यहां न तो अभी तक राइट टू एजुकेशन का पालन होता है और न ही आर्थिक दृष्टीकोण से कमजोर मेधावी छात्रों का नामांकन लिया जाता है.शहर के एक–दो विद्यालय को छोड़ अधिकांश विद्यालयों की स्थिति एक जैसी है आधुनिक शिक्षा के नाम पर खुलेआम अभिभावकों का दोहन किया जाता है.प्रति दिन विद्यालयों के संचालकों द्वारा मनमानी करने व कमीशन आधारित पुस्तक छात्रों को उपलब्ध कराने के साथ–साथ मोटी रकम लेने की शिकायतें मिलती रहती हैं किन्तु कोई कार्रवाई नहीं होती. जानकार बताते हैं कि पूर्वी व पश्चिमी चम्पारण जिले में शिक्षा पूर्ण रूप से व्यवसाय का रूप ले चुका है और आधुनिक शिक्षा के नाम पर जो विद्यालय संचालकों द्वारा किया जा रहा है वह अपने आप में काफी गंभीर है. मोतिहारी शहर में संचालित जीवन पब्लिक स्कूल, देलही पब्लिक स्कूल, मॉडर्न पब्लिक स्कूल, संतजेवियर्स, राजीव गांधी सेकेण्ड्री स्कूल,ज्ञान निकेतन समेत प्राय: सभी निजी विद्यालयों की स्थिति एक जैसी है और आधुनिक शिक्षा व रीएडमिशन के नाम पर अभिभावकों को शोषण करने का काम बदस्तूर जारी है. इसके अलावा नामांकन के बाद पुस्तक व ड्रेस वहीं से खरीदनी है जहां विद्यालयों के संचालक चाहेंगे.अगर गलती से किसी छात्र ने दूसरी जगह से किताबें खरीद भी लेता है तो इसे हर हाल में वापस करना ही पड़ेगा.दूसरी तरफ विद्यालय में कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसका भी खर्च अभिभावकों को ही उठाना पड़ता है.चाहे शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है या फिर कोई अन्य कार्यक्रम,सभी केवल दोहन का ही काम होता है. चम्पारण छात्र संघ व बिहार नव युवक सेना द्वारा जिले भर में विरोध प्रदर्शन किया गया और जिलाधिकारी तक इसकी शिकायतें भी की गयीं किन्तु कोई कार्रवाई नहीं हुई. विरोध प्रदर्शन का अभिभावकों का समर्थन भी प्राप्त था और बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लेकर यह साबित किया था कि विद्यालय संचालकों की मनमानी व शोषण से काफी परेशान है. प्राइवेट स्कूलों में अवैध तरीके से हो रहे री–एडमिशन के खिलाफ आज चम्पारण छात्र संघ व बिहार नवयुवक सेना ने विरोध मार्च निकाला था.आंदोलन में शामिल विकास राज, अनिकेत पाण्डेय, संतोष सिंह, आशुतोष सिंह, योगेश गुप्ता, राधेराज, शिवम साह आदि ने बताया कि प्रभारी जिलाधिकारी को ज्ञापन भी इस बाबत सौंपा गया और रि–एडमीशन के नाम पर की जा रही मनमानी पर रोक लगाने की मांग की गयी.इधर जिला शिक्षा पदाधिकारी से इस बाबत विस्तार से जानकारी लेने की कोशिश की गयी किन्तु इनसे बात नही हो सकी जिसकारण इनका पक्ष नही लिया जा सका.यही स्थिति पश्चिम चम्पारण जिले की है जहां नीजी विद्यालयों के संचालकों की मनमानी चरम पर है और अभिभावकों का खुले–आम शोषण हो रहा है.कई बार यहां भी शोषण के खिलाफ आवाज इठायी गयी किन्तु इसे दबा दिया गया.अगर इस मामले की गहनता से जांच होतो अनेक चौंकाने वाले मामले सामने तो आयेंगे ही साथ ही गरीब व मेधावी छात्रों का कल्याण भी हो सकेगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

देवघर

देवघर नगर निगम चुनाव 2015

मेयर पद पर बहुकोणीय मुक़ाबले के आसार

रणजीत झा

देवघर नगर निगम चुनाव 2015 के लिए 26 मई को मतदान होना है. जैसे–जैसे देवघर नगर निगम के मतदान की तिथि निकट आ रही है, मेयर पद के लिए महिला उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर होती दिख रही है. मेयर पद महिला के लिए आरक्षित होने पर मुख्य चार महिलाएं चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं. मेयर पद के लिए उम्मीदवारों में धन, बल, राजनीति का अनुभव एवं दबंग परिजनों के समर्थन से मुकाबला कड़ा होने की प्रबल संभावना है. सुबह से शाम तक कोई उम्मीदवार महंगी लग्जरी गाड़ियों में कैंपेन कर रही है तो कोई पैदल घर–घर जाकर संपर्क अभियान में है. मेयर पद की उम्मीदवारों के परिजन भी जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं. सारी चुनावी तिकड़म का उपयोग निगम चुनाव में देखने को मिल रहा है. रीता चौरसिया, रीता नरौने, सावित्री देवी एवं ममता गुप्ता मुख्य रूप से मेयर पद की रेस में हैं.

रीता चौरसिया अपने पति व शहर के प्रख्यात चिकित्सक डॉ. आरके चौरसिया की छवि के साथ–साथ भाजपा महिला जिलाध्यक्ष पद के अनुभव को लेकर मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रही है. वर्तमान जिला भाजपा की गतिविधियों में रीता चौरसिया की अहम भूमिका रही है जिसका लाभ उन्हें मिलने की संभावना है. वैसे स्वभाव से सरल एवं मृदुभाषी महिला के रूप में रीता चौरसिया शहर में जानी जाती है जिनसे आम शहरवासी आसानी से मिल पाते हैं. पिछले नगर निगम सत्र में वार्ड पार्षद के रूप में भी दमदार उपस्थिति दर्ज कर चुकी है.

राज पलिवार की बहन एवं उपमहापौर संजयानंद झा की पत्नी सावित्री देवी पिछले विधानसभा चुनाव से ही कई सार्वजनिक मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर चुकी हैं. समाजसेवी एवं संघ के सक्रिय कार्यकर्ता की पुत्री होने के नाते सामाजिक गतिविधियों पर बचपन से नजर रही है. स्थानीय पंडा समाज से आनेवाली सावित्री देवी का निगम क्षेत्र के हर वर्ग में पहचान है.

प्रख्यात समाजसेवी स्वर्गीय कमलकांत नरौने की पत्नी रीता नरौने मेयर पद के उम्मीदवारों में अहम मानी जा रही है. वार्ड पार्षद एवं नगर निगम, जोन सात के अध्यक्ष राकेश नरौने की माताजी होने का जबरदस्त लाभ उन्हें मिलेगा. राकेश नरौने का शहर के हर वर्ग के युवाओं में खासा प्रभाव है, जिनमें नगर निगम चुनाव के परिणाम प्रभावित करने की क्षमता है. राकेश नरौने अपने माताजी को जिताने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे. रीता नरौने नगर निगम चुनाव में कड़ी टक्कर देने वाली उम्मीदवार साबित होंगी. रीता नरौने का कहना है कि लंबे समय से नगरपालिका एवं नगर निगम के क्रियाकलापों एवं गतिविधियों की जानकारी से शहरवासियों को अच्छी सेवा देने का भरपूर प्रयास करुंगी.

सन 1991 से भाजपा में सक्रिय राजनीति करने वाली ममता गुप्ता भी मैदान में उतर चुकी हैं. भाजपा के महिला मोर्चा के कई पदों पर रह चुकी ममता गुप्ता भी अपने अनुभवों एवं संपर्कों का लाभ उठाने में सक्षम हैं. ममता गुप्ता वर्तमान में प्रदेश भाजपा कार्यसमिति सदस्य भी हैं. वैश्य समाज से आने वाली ममता गुप्ता का निगम क्षेत्र में अच्छी पकड़ मानी जा रही है. ममता गुप्ता का मानना है कि विपरीत परिस्थितियों में काम करने का अनुभव रहा है. कई चुनावों में मतदाताओं के बीच जाकर समझा पाने का अनुभव भी उनके साथ है. ममता गुप्ता कहती है कि शहर की ज्वलंत समस्याओं में पेयजल, सड़क, नाली एवं सफाई के साथ श्रद्धालुओं की सुविधा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. कहा जा रहा है कि इन दिग्गजों के समर्थन से महिला उम्मीदवारों के बीच बहुकोणीय मुकाबले में कांटे की टक्कर होने की संभावना है. अब देखना है कि कौन उम्मीदवार कितने मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान कराने में सफल हो पाती है और चुनाव जीतकर देवघर नगर निगम के दूसरे महापौर का ताज पहनेगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

ममता गुप्ता

रीता चौरसिया

रीता नरौने

सावित्री देवी

अन्य ख़बरें

शिक्षकों ने निकाला आक्रोश मार्च

मोतिहारी में नियोजित शिक्षक महासंघ के बैनर तले नव नियुक्त माध्यमिक शिक्षक संघ, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ एवं टीईटी–एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ के संयुक्त तत्वावधान में आक्रोश मार्च निकाला गया. यह मार्च विधान सभा सत्र समाप्त होने के उपरान्त भी अबतक सरकार द्वारा वेतनमान की घोषणा नहीं करने के विरुद्ध निकाला गया. इस मार्च का नेतृत्व नव नियुक्त माध्यमिक शिक्षक संघ के डॉ. राधामोहन यादव, टीईटी–एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष प्रियरंजन सिंह एवं बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला उपाध्यक्ष रीता गुप्ता ने संयुक्त रूप से किया. यह मार्च बंगला मध्य विद्यालय से निकलकर डीईओ कार्यालय तक गया जहां मार्च सभा में तब्दील हो गया. सभा को संबोधित करते हुए डॉ. राधामोहन यादव ने कहा कि वेतनमान नहीं मिलने तक मैट्रिक का मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार जारी रहेगा. वहीं प्रियरंजन सिंह ने कहा कि जिले के सभी टीईटी–एसटीईटी उत्तीर्ण शिक्षक सरकार की धमकियों को नजरअंदाज करते हुए आंदोलन को निर्णायक मोड़ तक पहुंचायेंगे. इस मार्च में जिला प्रवक्ता राजेश रजक, ओम प्रकाश सिंह, महफुजुल रहमान, सुधाकर पाण्डेय, सुधीर यादव, सर्वेश कुमार शर्मा, कुन्दन ठाकुर, रणजीत कुमार, चेतन आनन्द, तारीक अनवर, कामेश्वर, विवेक कुमार, इमेश चन्द्र शर्मा, संजय कुमार सहित सैकड़ों शिक्षक उपस्थित थे. *–इंतेज़ारुल हक़*

दूसरी पारी खेलने को बेताब शैलजा

वार्ड पार्षद शैलजा देवी नगर निगम चुनाव में फिर इस बार चुनाव में जीत दर्ज कर दूसरी पारी खेलने को बेताब है. वार्ड के मतदाताओं के अनुसार वार्ड में अपनी दमदार उपस्थिति एवं किए गए विकास कार्यो के आधार पर खासी लोकप्रियता हासिल की है जिसके आधार पर ही फिर चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं. वार्ड में मतदाताओं से मिल रहे भरपूर समर्थन से उत्साहित शैलजा देवी का कहना है कि पिछले कार्यकाल में वार्ड के लोगों के हर सुख–दुख में साथ रहा एवं विकास के लिए निगम की बैठकों में जमकर आवाज उठाती रहीं तथा विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए जीतोड़ कोशिश करती रही है. नगर निगम के सूत्रों की मानें तो शैलजा देवी अपने वार्ड की ही नहीं बल्कि पूरे नगर निगम के क्रियाकलापों पर कड़ी नजर रखती रही है और समय–समय पर गड़बड़ी के खिलाफ जमकर आवाज उठाकर विरोध दर्ज भी कराई है. देवघर नगर निगम के नगर आयुक्त हो या कोई पदाधिकारी या कर्मचारी किसी के भी विरुद्ध शिकायत मिलने पर शैलजा देवी ने जमकर आवाज बुलंद की तथा सही दिशा निर्देश देने के साथ साथ नगर निगमवासियों के हित में निर्णय लेने पर मजबूर करती रही है. साथ ही, बीच–बीच में आवश्यक सुझाव देकर निगम के कार्यकलापों को सही दिशा दी है. शैलजा देवी अपने वार्ड के बाकी बचे विकास कार्य को पूरा करने का संकल्प लेकर ही फिर इस बार चुनावी मैदान उतर चुकी है. *–रणजीत झा*

गरीबों के लिए वरदान विद्यालय

आधुनिक युग में प्राइवेट स्कूलों की चकाचौंध से ओत प्रोत अभिभावकगण इन दिनों स्कूल प्रबंधन की ओर से री एडमिशन फीस एवं भारी भरकम विकास शुल्क से त्रस्त होकर आंदोलनरत हैं. स्कूल प्रबंधन के विरोध में रोज धरना प्रदर्शन हो रहे हैं. इस बीच देवघर में निदेशक दिनेश कुमार के नेतृत्व में अपना विद्यालय का शुभारंभ

सांसद निशिकांत दुबे एवं समाजसेवी रीता चौरसिया ने किया. यहां अल्प आयवाले अभिभावकों के दर्द को समझते हुए काफी कम स्कूल फीस रखी गई है. किसी भी प्रकार के री एडमिशन एवं विकास शुल्क नहीं लिया जा रहा है. खास कर गरीब व मध्यम आयवाले अभिभावकों का विशेष ध्यान रखा गया है ताकि इनके बच्चे भी प्राइवेट स्कूल की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाकर राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे. देवघर शिक्षा जगत के वरिष्ठ शिक्षकगणों की गरीमामयी इपस्थिति से अपना विद्यालय शुभारंभ समारोह एक महत्व रखता है. *–रणजीत झा*

कटाव का कहर जारी

गोगरी प्रखंड के सर्किल नंबर–1 के सुरक्षा घेरा बदला नगरपारा बांध पर एक बार फिर कोसी के कटाव का खतरा मंडराने लगा हैं.यही नहीं बाढ़ प्रमंडल 2 के बाढ़ निरोधी कार्य दल के द्वारा पूर्व के कटाव स्थल पर सेंड बैग के द्वारा कटाव निरोधक कार्य पूरा कर लिया गया है. पर विरबास अनशन स्थल से आगे 30वें और 31 वें किलोमीटर के पास भीषण कटाव शुरू हो गया हैं.कोशी खेतों को काटती बांध के पास पहुंच गई है.स्थानीय लोगों को आशंका है कि कभी भी कोसी का कटाव बीरवास का भुगोल बदल सकता हैं. मालूम हो कि पिछले दस वर्षो में कोसी ने कमरी,बसुआ,और बिरवास को पूरी तरह लील कर बांध के किनारे और बांध के पास धकेल दिया हैं.इन वर्षो मे बीरवास कई बार करोड़ों खर्च कर बांध बनाया गया.जिसमें न केवल सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ. बल्कि किसानों का लहलहाता खेत खत्म हो गया,पर आजतक किसी भी किसानों को मुआवजा नहीं मिला.भीषण कटाव देखते हुए स्थानीय सिकन्दर षर्मा,दिनेश शर्मा,चन्देवशी यादव,अंजनी यादव ने बाढ़ प्रमंडल के अधिकारीयों से मांग की है कि एक बार जिलाधिकारी कटाव स्थल का मुआयना कर कटाव निरोधक कार्य मे गति प्रदान करने की कृपा करें.

उधर बाढ़ प्रमंडल के सहायक कार्यपालक अभियंता ने कहा की नए जगह के लिये आवेदन नहीं आया है,इसलिए कार्य आगे नहीं किया जा रहा हैं. *–गीता कुमार*

जहरीला पानी पीने को लोग विवश

गोगरी अनुमंडल क्षेत्र के पसराहा थाना क्षेत्र के दर्जनों गावों में जल संकट गहराने लगा है.यहां के लोग आयरन, फ्लोराइड, एवं आर्सेनिक जैसे जहरीले रासायनिक पदार्थो से युक्त जहरीले जल को पीने को मजबूर हैं. इस विषैले पानी पीने वाले को खुद पता नहीं कि कैसे वे धीरे –धीरे साइलेंट मौत के करीब पहुंच रहा है. सरकार द्वारा ग्रामीणों को अशुद्ध पेय जल उपलब्ध कराने के लिए हजारों रुपये खर्च कर गांव में जगह–जगह आयरन रिमूवल प्लान्ट लगाया गया है.घटिया निर्माण और स्थान चयन में बरती गयी अनियमितता के कारण ऐसे चापाकल या तो खराब है या आम आदमी के पहुंच से काफी दूर हैं. गंगा के मैदानी इलाके के पानी में आर्सेनिक कि बड़ी मात्रा घुली हुई मिल रही हैं.यह तत्व इतना जहरीला है कि इससे कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी इस क्षेत्र में अपना पांव पसार रही है.खास कर लीवर कैंसर आंत का कैंसर मुंह के कैंसर कि शिकायत बढ़ी है.वहीं डॉक्टर परबत्ता के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. रणधीर कुमार ने बताया कि गंगा में प्रदुषण के वजह से पानी में जहरीले तत्वो की मात्रा बढ़ी हैं. *–गीता कुमार*

प्राकृतिक असंतुलन का कारण भूकंप

गोगरी अनुमंडल क्षेत्र के पसराहा थाना चौक के बजरंगबली मंदिर में श्री श्री 108 हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा स्थापित किया गया. इस अवसर पर हिन्दू देवी देवताओं के दर्जनों मूर्ति का निर्माण किया गया. साथ ही रामध्वनि का आयोजन किया गया. रामध्वनि का उद्घाटन जिप अध्यक्षा श्री मति कृष्णा यादव ने किया. इस अवसर पर जिप अध्यक्षा ने लोगों को

संबोधित करते हुए कहा कि रामध्वनि से लोगों के मन कि शुद्धि होती है. वहीं पसराहा थाना के चकहर गांव में रामध्वनि यज्ञ का उद्घाटन करने आई जिप अध्यक्षा कृष्णा कुमारी यादव अपने संबोधन में यज्ञ के बहाने केन्द्र सरकार पर निशाना साधते हुए लोगों को लोक सभा चुनाव में किये वादे को याद दिलाई. उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान बीजेपी ने जो वादे किये इनमें से एक भी वादे पर खरी नहीं उतरी. उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में जितने किसानों ने आत्म हत्या की है उतनी तो पिछले 10 वर्षो में भी नहीं हुई. उन्होंने कहा कि आपने जिसे अपना सांसद चुना जो अच्छे दिन लाने का सपना दिखाकर आपको ठगने का काम किया. आज आपके सामने दुख सुख बांटने नहीं आ रहा है. मैं खगड़िया कि बेटी हूं और हमेशा आपके सेवा के लिए तत्पर रहूंगी. वैसे चकहर में बिजली कि समस्या पर ध्यान आकृष्ट कराने पर घर पर आकर मिल बैठ कर समस्या का निदान करने कि बात कही. *–गीता कुमार*

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र

विकल्प देगा जनाधिकार मोर्चा

आज बिहार राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रहा है. आम जनता एक ओर जहां सरकार की भ्रष्ट राजनीति से पूरी तरह निराश एवं हताश है, वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा भी भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जातिवाद, अवसरवाद के विरुद्ध गंभीर नजर नहीं आ रही है. यदि इस विषय पर भाजपा सचमुच गंभीर होती तो सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए परिवारवाद के सुप्रीम प्रतीक रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) तथा जॉर्ज फर्नान्डिस के कट्टर विरोधी, अवसरवादी, जातिवादी एवं सिर्फ जाति के नाम पर मुख्यमंत्री पद का दावा करने वाले नेता उपेन्द्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रालोसपा) के साथ न तो समझौता करती, न सहयोगी बनाती और न केंद्र सरकार में कोई जगह देती.इसी संदर्भ में बिहार में स्वच्छ राजनिति एवं ईमानदार सरकार के गठन के लिए एक मजबूत विकल्प उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पिछले दिनों राज्य के बेदाग छवि के लगभग 50 प्रमुख एवं जागरुक नागरिकों ने पटना में एक बैठक की थी. जिसकी अध्यक्षता बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य एवं जदयू के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ शंभूकांत शरण श्रीवास्तव ने की थी. बैठक में सर्व–सम्मति से लिए गए निर्णय के आलोक में उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जनाधिकार मोर्चा नाम से एक मजबूत संगठन की स्थापना की गई है. इस संगठन की कोर कमेटी में कुल 11 सदस्य हैं. इस कमेटी के संयोजक के रूप में पटना एवं झारखंड उच्च न्यायालय के प्रख्यात वरीय अधिवक्ता विभूति प्रसाद पांडे को नियुक्त किया गया है. सह–संयोजक के रूप में पी.के. सिन्हा को नियुक्त किया गया है. इसके अवाला बाकी के सदस्यों के नाम डॉ शंभूशरण श्रीवास्तव, मिथिलेश कुमार सिंह, बाबूलाल मधुकर, नीलिमा सिन्हा, अब्दुल मन्नान खान, जुल्फीकार अली, नरेंद्र कुशवाहा, मृत्युंजय पटेल और संजय कुशवाहा है. आगामी मई महीना से सभी जिला मुख्यालय में जनाधिकार सम्मेलन होगा, जिसकी शुरुआत 10 मई 2015 को भागलपुर से होगी. जनाधिकार मोर्चा का प्राथमिक उद्देश्य होगा स्वच्छ एवं लोकतांत्रिक प्रणाली पर आधारित राजनीति की वापसी तथा ईमानदार सरकार का गठन. इसके अलावा इसी परिपेक्ष्य में राजनीति में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने, अपराधियों एवं बाहुबलियों के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने दिनोदिन बढ़ती हुई आपराधिक विषमता पर रोक लगाने आदि हैं. जनाधिकार मोर्चा लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं लोकतांत्रिक परम्पराओं का पालन करने हेतु एक ऐसे समता मूलक समाज की स्थापना के लिए निरंतर प्रयास करेगी, साम्प्रदायिकता का कोई स्थान नहीं होगा.

कारगिल चौक पर धरना

जनता दल राष्ट्रवादी ने मुसलमानों को 16 प्रतिशत आरक्षण देने के सवाल पर, कारगिल चौक पर एक दिवसीय धरना दिया. उप–स्थित समूह को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अशफाक रहमान ने कहा कि तथा कथित सेकुलर पार्टियां तथा केन्द्र सरकार मुस्लिम वोट बैंक को लेकर दोहरी नीति अपनाती रही है. तभी तो मुसलमानों के सवाल पर जनता दल राष्ट्रवादी ने चरणबध्य तरीके से लड़ाई शुरू कर दी है. मुलसमानों को बारगेन करने एवं डराने के नये–नये तरीकों पर राजनीतिक दलों की विश्वसनीयता पर भी श्री अशफाक रहमान ने सवाल दागा है. उन्होंने आगे कहा कि मुलसमानों के वोट से सत्ता की मलाई खाने वाले तथाकथित मुलसमानों के हमदर्द नेता तथा पार्टियों ने उनकी बुनियादी मुद्दों पर क्या किया है? वो इस पर जवाब देंगे? इस पर भी राष्ट्रव्यापी बहस चलनी चाहिए. तभी तथाकथित इन 'नेताओं' के असली चेहरे उजागर होंगे. उन्होंने आगे कहा कि सच्चर कमेटी की बातों को लेकर सरकार कभी भी गंभीर बैठक क्यों नहीं कर रही है? धरना में प्रदेश महासचिव मेराज खान के अलावे शमीम आलम, डॉ. शफीकुल रहमान, अर्चना सिंह, गुलाम साबिर, भूषण प्रसाद चन्द्रवंशी, मृदुला कुमारी, मो. एकबाल अहमद, मुन्नी कुमारी, डॉ. माशूक अली, संजय यादव, जमिल हुसैन, मुन्ना मुखिया, खालिक अंसारी, विनय घोष, कालेश्वरी देवी, मो. दानिश आदि शमिल थे.

आध्यात्मिक प्रदर्शनी का उद्घाटन

मोतिहारी के शंकर सरैया के कलवारी टोला में आयोजित नव कुण्डीय शिव भक्ति महायज्ञ परिसर में सौ फीट के व्यास वाले पण्डाल में ब्रह्माकुमारी बालगंगा द्वारा लगाए गए बारह ज्योति लिंगम एवं आध्यात्मिक प्रदर्शनी का उद्घाटन काशी पीठ के शंकराचार्य श्री नारायण तीर्थ एवं उतर बिहार ब्रह्माकुमारी प्रभारी बीके रानी दीदी ने दीप प्रज्जवलित कर किया. शंकराचार्य ने बारी–बारी से बारह वों शिवलिंग कक्ष का अवलोकन नारियल फोड़कर एवं दीप जलाने के साथ किया. अलग–अलग खण्डों में सुसज्जित शिव लिंग नीले एवं लाल रोशनी में दिव्यता लिए हुए अपना प्रतिकंपन छोड़ रहे थे. वैज्ञानिक ढंग से घुमावदार खंडों में सजाये शिव लिंग को देख शंकराचार्य काफी प्रसन्न हुए. बारह वें शिवलिंग कक्ष समापन पर लगे आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी को शंकराचार्य ने देखा. चित्रों के रहस्य पर बीके रानी दीनी ने विस्तार से उन्हें समझाया. चित्रों में परमात्मा शिव के 32 गुण, शिव शंकर में अंतर सीढ़ी, गोला, मानव जीवन का लक्ष्य, आत्मा का परिचय आदि था. चित्रों एवं पंडाल को नया आध्यात्मिक आकार देने में भाई, हिमांशू एवं रंजन भाई थे. उक्त मौके पर बाल गंगा केन्द्र प्रभारी बीके निशा, बीके मीना, बीके सीता, बीके अशोक, हरिशंकर भाई, शम्भू भाई, धनन्जय भाई, डॉ. अंजु वर्मा, रेखा सिन्हा, वीणा त्रिपाठी एवं अन्य थे. *–इंतेज़ारुल हक़*

बाबा साहेब की जयंती मनी

पूर्वी चम्पारण जिले के केसरिया प्रखंड परिसर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 125 वीं जयन्ती समारोह पूर्वक मनायी गयी. कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत शिक्षक सूर्य पासवान ने की जबकि संचालन चतुर्भुज बैठा ने किया. जयंती समारोह को संबोधित करते हुए अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष सुरेन्द्र सुमन कनौजिया ने बाबा साहेब के आदर्शों पर विस्तार से चर्चा की और इसपर अमल करने की अपील की. उन्होंने दलित समाज के लोगों से नशा को छोड़ शिक्षा हासिल करने की अपील की. मौके पर संरक्षक रामसेवक राम, मुखिया हरिशंकर पासवान, विक्रमा बैठा, शिवनाथ राम, सुशील कुमार, राम पुकार पासवान, प्रमोद पासवान, मनोज कुमार राम, जय प्रकाश बैठा, लालबाबू राम, चौरसिया ध्रुव प्रसाद, चंदन राम, ज्ञान प्रकाश, सुनिता कुमारी, रूपन पासवान, बंगाली पासवान, राजनारायण बैठा, केके जायसवाल, श्री नारायण राम समेत कई लोगों ने संबोधित करते हुए बाबा साहेब के जीवनी पर प्रकाश डाला. इस कार्यक्रम में जिला से आए अतिथियों को फूलमाला व शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया. प्रखंड परिसर के समीप प्रतिमा लगाने के लिए विधिवत भूमि पूजन किया गया. इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी थी. *–इंतेज़ारुल हक़*